बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 286

एआई के दम पर वृद्धि

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के जनवरी 2026 के विश्व आर्थिक पूर्वानुमान इस सप्ताह जारी किए गए जो बताते हैं कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वैश्विक वृद्धि के एक अहम इंजन के रूप में उभरा है। 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 3.3 फीसदी कर दिया गया है और यह मोटे तौर पर तकनीकी विकास और एआई से जुड़े निवेश की वजह से है। ऐसे निवेश प्रमुख रूप से अमेरिका में हो रहे हैं। आईएमएफ का अनुमान है कि 2025 की पहली तीन तिमाहियों में अमेरिका में तकनीकी क्षेत्र में निवेश ने औसत वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में करीब 30 आधार अंकों का योगदान किया। इससे वहां के लिए 2026 का वृद्धि अनुमान बढ़कर 2.4 फीसदी हो गया। 2026 की शुरुआत में कॉरपोरेट आय और निवेश घोषणाएं यह संकेत देती हैं कि एआई अधोसंरचना पर होने वाला व्यय जिसमें उन्नत सेमीकंडक्टर से लेकर डेटा सेंटर और क्लाउड क्षमता आदि शामिल हैं, व्यापक पूंजीगत व्यय से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह आईएमएफ के इस आकलन को मजबूत करता है कि प्रौद्योगिकी वैश्विक व्यापार की नाजुक स्थिति के बावजूद वृद्धि को सहारा दे रही है। एआई को व्यापक रूप से अपनाने से उत्पादकता और मध्यम अवधि की वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि व्यापारिक तनावों में लगातार कमी नीति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता को बढ़ा सकती है और निवेश की गति को पुनर्जीवित कर सकती है।

आईएमएफ ने यह चेतावनी भी दी है कि एआई आधारित वृद्धि का आधार बहुत संकीर्ण है। एआई में निवेश की तेजी एक ऐसा बुलबुला साबित हो सकती है जो 2000 के दशक के आरंभ के डॉट कॉम बुलबुले की तरह ही फट सकता है। यदि अपेक्षाएं वास्तविक उत्पादकता लाभ से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती हैं, तो अत्यधिक निवेश अचानक रुक सकता है। शेयर बाजार मूल्यांकन में तीव्र गिरावट पूंजीगत व्यय को कम करके और भरोसे को कमजोर करके वृद्धि को जल्दी धीमा कर सकता है, भले ही यह पूर्ण वित्तीय संकट को जन्म न दे। कुछ बड़ी अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों का छोटा समूह इक्विटी बाजार को चला रहा है, जिससे एआई-संबंधित मूल्यांकन व्यापक बाजार से कहीं अधिक ऊपर पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट भी यह बताती है कि एआई निवेश अत्यधिक केंद्रित बना हुआ है। 2024 में वैश्विक कॉरपोरेट एआई खर्च का 72.5 फीसदी हिस्सा अमेरिका के हिस्से में आया, जो यह रेखांकित करता है कि अधिकांश देश अभी कितने पीछे हैं।

बहरहाल, विश्व आर्थिक मंच के शोध बताते हैं कि एआई व्यवस्थाएं अकेले अमेरिका में 4.5 लाख करोड़ डॉलर मूल्य के काम कर रही हैं। ऐसे में जहां अलग-अलग कामों के लिए एआई को व्यापक तौर पर अपनाने से उत्पादकता में सुधार हुआ होगा, वहीं निवेश का स्तर और उसका केंद्रीकरण चिंता का विषय है। ऊर्जा की तीव्रता, डेटा के केंद्रीकरण और श्रम विस्थापन को लेकर भी चिंताएं हैं। कई उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजी, कौशल और डेटा तक सीमित पहुंच मौजूदा आय और उत्पादकता की खाई को और चौड़ा करने का खतरा पैदा करती है।

भारत की विकास गाथा वैश्विक चुनौतियों और घरेलू संभावनाओं के मेल पर आधारित है। आईएमएफ ने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पुष्टि की है और 2025-26 के लिए इसका वृद्धि पूर्वानुमान संशोधित कर 7.3 फीसदी तक कर दिया है। 2026-27 में वृद्धि के 6.4 फीसदी तक रहने की उम्मीद है। वर्तमान वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि अपेक्षा से अधिक रही, और नीति-निर्माताओं के लिए चुनौती यह होगी कि अगले वित्त वर्ष में इस गति को कैसे बनाए रखें। एआई निवेशों के संदर्भ में, भारत को बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा डेटा केंद्रों में निवेश आकर्षित करने से भी लाभ हुआ है। हालांकि, उसे एआई निवेश में संभावित मंदी या उलटफेर के प्रभाव के लिए तैयार रहना पड़ सकता है, जिससे अमेरिका और अन्य शेयर बाजारों में तीव्र गिरावट आ सकती है। किसी भी स्थिति में, विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से पूंजी निकाल रहे हैं, और यदि वैश्विक बाजार धारणा में उल्लेखनीय कमजोरी आती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इस प्रकार, वैश्विक व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के अलावा, एआई संबंधित लेनदेन के समाप्त होने की आशंका से भी वृद्धि के लिए जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

अजय मोहंती

भारत-मॉरीशस कर संधि और विधि का शासन

सीमा-पार कराधान के बुनियादी सिद्धांत एक बार फिर चर्चा में हैं। निजी निवेश बढ़ाने के लिए एक मजबूत कर नीति और विधि के शासन की आवश्यकता है। बता रहे हैं अजय शाह और रेणुका साने

भारत-मॉरीशस कर संधि को लेकर हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर सीमा पार कराधान के बुनियादी सिद्धांतों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। हाल ही के एक निर्णय में यह जोर दिया गया है कि कर प्राधिकरण संधि लाभों को अस्वीकार करने के लिए कर-निवास प्रमाणपत्र (टीआरसी) से आगे भी देख सकते हैं, जिससे वैश्विक निवेशकों में नई चिंता पैदा हुई है। गहरी समस्या भारत के पूंजी कराधान पर बदलते रुख और कानून के शासन को बनाए रखने में निहित है। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें रोजाना की खबरों से परे बुनियादी बातों पर ध्यान देना होगा यानी इस पर कि कर नीति कैसे आर्थिक वृद्धि को आकार देती है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमने मूल्यवर्धित कर (वैट) के माध्यम से बौद्धिक स्पष्टता हासिल की है। वैट गंतव्य सिद्धांत पर काम करता है। निर्यात शून्य-कर वाले होते हैं, जिससे भारतीय इस्पात हमारी सीमाओं से घरेलू करों से मुक्त होकर, केवल बाजार मूल्य के साथ और सभी अप्रत्यक्ष करों से रहित होकर बाहर जाता है। आयात पर घरेलू वस्तुओं के समान दर से कर लगाया जाता है। यह तटस्थता सुनिश्चित करता है। यह कर प्रणाली भारतीय उत्पाद और विदेशी उत्पाद के बीच चयन को प्रभावित नहीं करती। इसी तरह का दर्शन कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) में देखा जाता है। प्रत्येक देश अपनी कार्बन कर दर चुनता है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकृत नहीं होता। ऐसी तटस्थता वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। जब इस तर्क को वित्त पर लागू किया जाता है, तो ऐसी तटस्थता के लिए निवास आधारित कराधान आवश्यक होता है। पूंजी से होने वाली आय पर कर प्राप्तकर्ता पर, उसके निवास देश में लगाया जाता है, न कि उस स्रोत पर जहां निवेश किया गया है। यदि अमेरिका का कोई पेंशन फंड भारत में निवेश करता है, तो उसके रिटर्न पर कर अमेरिका में लगाया जाना चाहिए, भारत में नहीं।

यह केवल एक सैद्धांतिक प्राथमिकता नहीं है। यह पूंजी की कमी वाली अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। भारत को आर्थिक विकास को वित्तपोषित करने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता है, जिसके लिए विदेशी पूंजी जरूरी है। वैश्विक पूंजी सबसे अधिक कर-पश्चात जोखिम-समायोजित रिटर्न चाहती है। यदि भारत स्रोत-आधारित कराधान लागू करता है। यानी विदेशी निवेशकों पर हमारी सीमाओं पर कर लगाता है तो हम उनके कर-पश्चात रिटर्न को कम कर देते हैं। इस कर लागत की भरपाई के लिए, वैश्विक निवेशक भारतीय परिसंपत्तियों से अधिक कर-पूर्व रिटर्न की मांग करते हैं।

इस तरह, निवेश परियोजनाएं जो 10 फीसदी पूंजी लागत पर व्यवहार्य होतीं, वे 14 फीसदी पर भी अव्यवहार्य हो जाती हैं। स्रोत-आधारित कराधान पूंजी पर एक शुल्क की तरह कार्य करता है, जो सीमा पर ही अवरोध पैदा करता है, निवेश को धीमा करता है, भारतीय कंपनियों के लिए लागत बढ़ाता है और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि को धीमा करता है। आदर्श रूप से, भारत को घरेलू स्तर पर पूंजी पर कम या शून्य कर दर रखनी चाहिए ताकि पूंजी आवक में गहराई आए। लेकिन इसके बिना भी, विदेशी निवेशकों के लिए निवास-आधारित कराधान का पालन करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। कई वर्षों तक हमने इस परिणाम को एक बेहतरीन संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से हासिल किया। हमने कर संधियों का उपयोग करके वास्तविक रूप से निवास-आधारित कराधान प्राप्त किया।

सार्वजनिक मामलों में पाखंड की एक स्वस्थ भूमिका होती है। चुनावी लोकतंत्रों में लोकलुभावन बयानबाजी अक्सर यह मांग करती है कि राज्य 'अमीरों पर कर लगाए' या 'विदेशियों पर कर लगाए।' हालांकि समझदार लोग यह जानते हैं कि हमें आर्थिक दक्षता के लिए परिस्थितियां निर्मित करनी होती हैं। यही वजह है कि वैश्विक पूंजीवाद की इमारत अक्सर कर निरपेक्ष माध्यमों के जरिए प्राप्त कुशल कराधान पर आधारित होती है। सफल देशों ने आम तौर पर एक अच्छी चालाकी अपनाई है, जिसमें वे सार्वजनिक तौर पर लोकप्रिय बातें कहते हैं, जबकि यह भी पक्का करते हैं कि ऐसे तरीकों से दुनिया की अर्थव्यवस्था ठीक से व्यवस्थित हो। इसी तरह से देखें तो, मॉरीशस मार्ग ने भारत को निवास-आधारित कराधान अपनाने की अनुमति दी, जिससे घरेलू कर नीति की अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में पूंजी की लागत कम बनी रही।

इस संतुलन के लिए कानूनी निश्चितता आवश्यक थी। इस निश्चितता की नींव आजादी बचाओ आंदोलन मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण द्वारा व्यक्त सिद्धांत थे। मानक एकदम स्पष्ट था। मॉरीशस सरकार द्वारा जारी एक वैध टीआरसी अपने आप में संपूर्ण था। भारतीय कर अधिकारी इस दस्तावेज से आगे जाकर निवेशक की स्थिति पर प्रश्न नहीं उठा सकते थे। लेकिन यह ढांचा 2016 में टूटने लगा। कर संधि में लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट्स (एलओबी) प्रावधान शामिल करने के लिए संशोधन किया गया। वैसे तो इसका घोषित उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना था, लेकिन इस संशोधन ने काम करने के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया। इसने टीआरसी के वस्तुनिष्ठ मानक की जगह संस्था के वाणिज्यिक सार से संबंधित व्यक्तिपरक परीक्षणों को रख दिया।

इस बदलाव ने कर विभाग को निवास प्रमाणपत्र देखने की शक्ति प्रदान की। हालिया निर्णय इसी बदलाव का परिणाम है, जहां टीआरसी अब कर अधिकारियों की जांच शक्तियों के विरुद्ध ढाल नहीं रहा। वर्ष2016 की गलतियां 2026 में हमें फिर से परेशान कर रही हैं। 2016 के बदलाव के साथ ही निजी निवेश में व्यापक कठिनाइयां भी आई हैं। सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में विदेशी स्वामित्व की संरचना का आंकड़ा उल्लेखनीय है। विदेशी स्वामित्व 2000-01 के 8.38 फीसदी से बढ़कर 2015-16 में 19.19 फीसदी के शिखर तक पहुंचा। लेकिन तबसे यह आंकड़ा ठहर गया और उलट गया। 2024-25 तक विदेशी स्वामित्व घटकर 16.04 फीसदी रह गया। एक सफल उभरते बाजार में हम उम्मीद करते हैं कि समय के साथ घरेलू आग्रह कम होगा। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व होती है और दुनिया से जुड़ती है, इक्विटी परिसंपत्तियों में विदेशी स्वामित्व का हिस्सा लगातार बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

न्यायपालिका को कार्यपालिका के अतिक्रमण पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जब अदालतें पहले से तय प्रश्नों को दोबारा उठाती हैं या नए मानकों के पुरानी तारीख से लागू करने की अनुमति देती हैं, तो वे भारत में निवेश के पूर्व जोखिम को बढ़ा देती हैं। आज एक विदेशी निवेशक को केवल व्यापारिक जोखिम ही नहीं बल्कि इस जोखिम को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आज हस्ताक्षरित कर संधि की कल दोबारा व्याख्या की जा सकती है। हम अब ऐसे कर अधिकारियों की व्यवस्था में हैं जिनका आर्थिक वृद्धि का ज्ञान कमजोर है, और एक न्यायिक प्रणाली की भी, जो अनुबंधों की पवित्रता और टीआरसी की प्रधानता को बनाए रखने में विफल रही है। कोई देश अपने विचारकों से बेहतर नहीं हो सकता। भारतीय आर्थिक विकास की परवाह करने वाले लोगों के एजेंडा में चार नीति परियोजनाएं शीर्ष पर होनी चाहिए। वे हैं: सीमा शुल्क हटाना, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में इनपुट क्रेडिट की रुकावटें हटाना, कार्बन कर लागू करना, और निवास-आधारित कराधान अपनाना। यह समझ अफसरशाही, राजस्व विभाग और न्यायपालिका तक फैलनी चाहिए।

(लेखक क्रमशः एक्सकेडीआर फोरम के शोधकर्ता और ट्रस्टब्रिज रूल ऑफ लॉ फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

नई वैश्विक व्यवस्था की चाहत बन न जाए आफत

नीति नियम

मिहिर शर्मा

दुनिया में आर्थिक रूप से कमजोर एवं विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई तथाकथित नियम-आधारित व्यवस्था से कई शिकायतें रही हैं। उन्हें इस बात का दुख सताता रहा है कि इस व्यवस्था ने औपनिवेशिक काल से बाहर निकले राष्ट्रों के पदानुक्रम को संस्थागत रूप दे दिया और लगभग स्थायी बना दिया। चीन सहित ग्लोबल साउथ में शामिल इन देशों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आई इस व्यवस्था को लेकर कई दूसरी चिंताएं भी थीं जो अक्सर सामने आती रही हैं। उदाहरण के लिए ग्लोबल साउथ की नजर में यह व्यवस्था पश्चिमी देशों के पाखंड पर पर्दा डालती रही और इसने आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने के बजाय गरीब देशों की जरूरतों को मुखर होने नहीं दिया।

हालांकि, ग्लोबल साउथ के कुछ देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इरादों और उनकी सोच पर थोड़ा छुपाते हुए खुशी जाहिर की जो बाद में जगजाहिर हो गई। कम से कम ट्रंप ने उस दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया जिन्हें पहले जाहिर होने नहीं दिया जाता था। उनकी नजर में अधिक से अधिक नुकसान यह होगा कि ट्रंप की सोच एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था का खात्मा कर सकती है जो विकासशील दुनिया के खिलाफ भेदभाव करती रही है। मगर वास्तव में कुछ लोगों के अनुसार वह उन अमेरिकी नेताओं से शायद ही अलग रहे हैं जो उनसे पहले सत्ता की बागडोर संभाल चुके हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति बुश (सीनियर) ने पनामा के मैनुअल नोरिएगा को पकड़ लिया था और उनके पुत्र यानी जूनियर बुश जब राष्ट्रपति बने तो इराक पर धावा बोला गया। बुश के बाद आए डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों राष्ट्रपतियों ने नियमित रूप से उन देशों पर बमबारी की जो उनकी नजरों में भरोसे के काबिल नहीं थे। इन देशों में सूडान से लेकर पाकिस्तान तक शामिल थे।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन सभी विचारों में कुछ न कुछ सच्चाई है मगर ज्यादा कुछ नहीं। अगर कुछ है तो वह दुनिया को लेकर एक ऐसी सोच है जो ग्लोबल साउथ को मिलने वाले लाभों पर एक गहरी समझ के बजाय पश्चिम के प्रति सहज विरोध से परिभाषित होती है।

यह तो साफ है कि राष्ट्रपति ट्रंप वे सभी कारमाने कर सकते हैं जो अन्य राष्ट्रपतियों ने किए। मगर एक काम ऐसा था जिसे ट्रंप ने बिना किसी खेद या औचित्य के और अमेरिका या उसकी जनता के प्रति जवाबदेही के एहसास के बिना किया। इसकी योजना भी कुछ इस तरह तैयार की गई कि उसमें क्रूरता थी मगर ठोस नतीजे नदारद थे। कुछ दिनों पहले ट्रंप प्रशासन ने एक लैटिन अमेरिकी नेता को उसके राष्ट्रपति भवन से घसीट कर एक ऐसी घरेलू अमेरिकी न्यायालय में पेश कर दिया जिसकी तटस्थता संदिग्ध है। ट्रंप ने लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी लोकतांत्रिक देश डेनमार्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ग्रीनलैंड हड़पने की जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात की भी तनिक परवाह नहीं कि डेनमार्क ने हाल के अमेरिकी युद्धों में कितना अहम योगदान दिया है। ट्रंप ने जलवायु से लेकर महिलाओं के स्वास्थ्य तक ग्लोबल साउथ की चिंताओं के लिए केंद्रीय मुद्दों पर बहुपक्षीय सहयोग को रेखांकित करने वाले दर्जनों संगठनों से अमेरिका के निकलने का ऐलान कर दिया। इनमें कुछ संगठन तो काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

जिन लोगों ने ट्रंप को तवज्जो नहीं दी या उन्हें कम आंका या फिर जिन्होंने ट्रंप का स्वागत किया है, उन्हें अपनी गलतियां अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। पारंपरिक बहुपक्षवाद का अंत संप्रभुता के युग को बहाल नहीं करेगा। यह विकासशील देशों के पास मौजूद कूटनीतिक विकल्पों के लिए गुंजाइश का विस्तार नहीं करेगा। लोकतांत्रिक शक्ति के युग के बजाय ट्रंप संघर्ष, देशों के बीच ऊंच-नीच और आक्रामकता के युग की शुरुआत करेंगे। अमेरिका ने निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है और वह ग्रीनलैंड को केवल इसलिए हथिया सकता है क्योंकि वह ऐसा करना चाहता है और वह यह कर भी सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई भी पहले यह जान ले कि ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका आगे और क्या-क्या हथियाएगा।

जो राष्ट्र स्वयं को विकासशील दुनिया के मुखिया, उल्लेखनीय क्षेत्रीय शक्ति या अमेरिका के भविष्य के अहम भागीदारों के रूप में समझते रहे हैं (भारत उन देशों में से एक है और इनमें से प्रत्येक श्रेणी में फिट बैठता है) उन्हें इस नए युग में विशेष सच्चाई से सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका उनके क्षेत्रों की दीर्घकालिक स्थिरता में कम दिलचस्पी रखता है और वह एक ऐसा देश है जो उनका पक्ष लेकर कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिका वह देश भी है जो अपने कथित हितों की रक्षा के लिए अचानक और अप्रत्याशित कदम उठा सकता है। ये कदम इन देशों एवं उनके पास-पड़ोस के माहौल को प्रभावित और अस्थिर करते हैं। हां, अमेरिका हम पर अपने आक्रामक मूल्यों जैसे लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों और ऐसी चीजों को थोपना कम कर सकता है मगर इससे हमारे हितों को नुकसान पहुंचने की आशंका कम नहीं होती। अमेरिका इस तरह के मूल्यों से बेपरवाह होकर अपना हित साधने के लिए सदैव कदम उठा सकता है। यह एक ऐसा सौदा नहीं है जिससे हम फायदे की स्थिति में हैं भले ही हमारी उम्मीदें जो भी रही हों। युद्ध के बाद की व्यवस्था का अंत कुछ ऐसा ही दिखेगा जिसके लिए लंबे समय से कई लोग आवाज उठा रहे हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें ताकत बेरोक-टोक होगी और भारत से लेकर ब्राजील तक सभी विकासशील देशों को यह एहसास कराया जाएगा कि वैश्विक मामलों में उनका वास्तविक प्रभाव और वजूद क्या है। वास्तव में उनका प्रभाव बहुत कम है और उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए नाकाफी है।

आपका पक्ष

अनाज पैदावार और भंडारण क्षमता बढ़ाने पर हो जोर

'अनाज से अधिक फल व सब्जी पैदावार का क्षेत्र बढ़ा' शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में पढ़ा। यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहां फल और सब्जियों की पैदावार बढ़ रही है। अगर सरकार इसे विदेश में बेचने के उचित प्रबंध करे, तो इससे सरकार और किसान, दोनों को भरपूर कमाई हो सकती है। लेकिन फल-सब्जियों के साथ अनाज की उपज बढ़ाने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कृषि प्रधान देश में अनाज की पैदावार कम हो जाए और स्थानीय स्तर पर जरूरत पूरी करने के लिए इसका आयात करना पड़े।
जिन फल, सब्जियों या अन्य खाद्य वस्तुओं की अपने देश में भरपूर फसलें होती हैं, उनकी कीमतें भी कभी-कभी बेतहाशा बढ़ जाती हैं, ऐसा क्यों? इससे भंडार गृहों की कमी दिखती है। सरकार को पर्याप्त भंडारण क्षमता विकसित करनी होगी। साथ ही वर्षा, आंधी, ओला आदि प्राकृतिक आपदाओं से भी फसलों को बर्बाद होने से बचाने के इंतजाम करने होंगे।

भंडारण क्षमता मजबूत होगी तो फसलों को खराब होने से बचाया जा सकेगा और जरूरत के समय पर मंडियों में आपूर्ति बढ़ाई जा सकेगी। कृषि विशेषज्ञों को चाहिए कि वे ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे हर राज्य में मौसम की मार से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को बचाया जा सके। जिस तरह मौसम का चक्र परिवर्तन हुआ है, उसी हिसाब से फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मौसम चक्र के हिसाब से उगाई जानी चाहिए फसलें

स्थिर और मजबूत नहीं चीन का व्यापार मॉडल

साल 2025 में चीन की आर्थिक वृद्धि दर 5% के स्तर पर बताई गई जो वास्तव में हकीकत नहीं है। इस प्रकार के बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए जाने वाले आंकड़ों से उसकी अर्थव्यवस्था में तेजी आने का सही संकेत नहीं मिलता। यह सरकार की उस चालाकी को दर्शाती है, जिसके जरिए वह आंकड़ों को मन मुताबिक पेश करती है, व्यापार के रास्तों को बदल देती है और सरकार की ताकत के दम पर स्थिरता बनाए रखने के दावे पेश करती है। चीनी अर्थव्यवस्था की यह तस्वीर भले ठीक-ठाक लगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर इसकी कमियां इसे कमजोर ही कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का व्यापार अधिशेष अब 1.20 लाख करोड़ डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। यह दिखाता है कि चीन अपनी घरेलू खपत की कमी को पूरा करने के लिए दुनिया भर के बाजारों में अपना सामान भर रहा है। ट्रंप टैरिफ से चीन के आंकड़ों पर भले कम असर पड़ा हो, लेकिन इसने दुनिया से चीन के जुड़ाव को काफी कम कर दिया है। इसी वजह से पेइचिंग अब अपनी सप्लाई चेन को विकासशील देशों (ग्लोबल साउथ) की ओर ले जा रहा है और अपनी करेंसी 'युआन' में व्यापार बढ़ा रहा है। लेकिन इसमें भी कम चुनौतियां नहीं हैं। चीन की अर्थव्यवस्था आज भी दूसरे देशों की मांग पर टिकी है, जबकि पूरी दुनिया अब चीन के भारी व्यापार असंतुलन और उसकी व्यापार नीतियों का कड़ा विरोध कर रही है। नतीजा यह है कि चीन का यह मॉडल दिखने में तो स्थिर लगता है, पर वास्तविकता में यह एक भंवर में फंसा लगता है।

अमरजीत कुमार, हजारीबाग

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

नई दिल्ली में बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस ने भारत-ईयू व्यापार वार्ता को जल्द अंतिम रूप दिए जाने का समर्थन किया और भारत-स्पेन संबंधों को सामरिक जुड़ाव तक बढ़ाने की इच्छा जताई। दोनों पक्षों ने गतिशीलता, शैक्षणिक आदान-प्रदान और संस्थागत भागीदारी को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की।

आर्थिक इंजन को ताकत दे रहे युवा

एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया यू40 लिस्ट, 2025 के अनुसार देश में 201 उद्यमी 31 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 40 कंपनियों की संभाल रहे हैं कमान

प्राची पिसाल

अजय मोहंती

भारत में 40 वर्ष से कम उम्र के 201 उद्यमी संयुक्त रूप से 31 लाख करोड़ रुपये (357 अरब डॉलर) के उद्यमों की कमान संभाले हुए हैं। यह जानकारी मंगलवार को जारी एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया यू40 लिस्ट 2025 रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा (31 लाख करोड़ रुपये) भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 11वां हिस्सा है।

दिलचस्प है कि 83 प्रतिशत उद्यमी पहली पीढ़ी के संस्थापक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह फेहरिस्त भारत में बढ़ती उद्यमिता एवं नेतृत्व की भावना को दर्शाती है। शेष 17 प्रतिशत उद्यमी व्यावसायिक परिवारों की विभिन्न पीढ़ियों से ताल्लुक रखते हैं जबकि 8 प्रतिशत दूसरी पीढ़ी के, 5 प्रतिशत तीसरी पीढ़ी के, 3 प्रतिशत चौथी पीढ़ी के और 1 प्रतिशत पांचवीं पीढ़ी के उद्यमी हैं। अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन के करण अदाणी, जिंदल स्टेनलेस के अभ्युदय जिंदल, ग्रो के ईशान बंसल और स्विगी के नंदन रेड्डी और श्रीहर्ष मजेटी इस सूची में शामिल कुछ प्रमुख नाम हैं। लिंक्डइन पर 13.9 लाख फॉलोअर्स के साथ जीरोधा के निखिल कामत डिजिटल पहुंच रखने वाले उद्यमियों की सूची में सबसे ऊपर हैं। हुरुन इंडिया के संस्थापक एवं मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा, 'भारत के नए आर्थिक इंजन को युवा उद्यमियों से ताकत मिल रही है। यह नई पीढ़ी भारत में करियर की ऊंचाइयों को फिर से परिभाषित कर रही है। इनमें कई उद्यमियों की उम्र लगभग 35 साल है जो एसएएएस, वित्त-तकनीक (फिनटेक), स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ ऊर्जा, लॉजिस्टिक और कंज्यूमर ब्रांड में कारोबार तैयार कर रहे हैं। भारत में नवाचार पूर्व की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो रहा है और उद्यमिता पारंपरिक सीमाओं से बहुत आगे बढ़ गई है।'

विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष पायदानों पर विराजमान उद्यमियों में बेंगलूरु स्थित एक्सपोनेंट एनर्जी के सह-संस्थापक संजय जगन्नाथ (36) शामिल हैं जो सूची में सबसे कम उम्र के हैं जबकि सोलर स्क्वैर की सह-संस्थापक श्रेया मिश्रा (36) सूची में सबसे कम उम्र की महिला हैं। सूची में केवल 15 महिलाएं हैं। ट्रैवल फूड सर्विसेस के वरुण कपूर और गोल्डमेडल इलेक्ट्रिकल्स के कपिल जैन 18-18 वर्षों के व्यावसायिक अनुभव के साथ सूची में सबसे ऊपर हैं। शहरों में बेंगलूरु 48 उद्यमियों के साथ अग्रणी है जो भारत की यू40 राजधानी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है जबकि यू40 समूह की औसत आयु 38 वर्ष है। ये उद्यमी सामूहिक रूप से 4,43,000 से अधिक पेशेवरों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। सॉफ्टवेयर उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र में इन उद्यमियों की उपस्थिति सबसे ज्यादा है जिसमें 40 उद्यमी हैं। इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल में 18, परिवहन एवं माल ढुलाई में 16 और वित्तीय सेवा क्षेत्र में15 उद्यमी हैं। सामूहिक रूप से इन उद्यमियों ने बाहर से 22 अरब डॉलर से अधिक रकम जुटाई है। एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया के बयान में कहा गया है कि यू40 के नेतृत्व वाली कंपनियां रकम का इस्तेमाल सोच-समझकर कर रही हैं जिसमें उत्पाद विकास और विस्तार के लिए 29 प्रतिशत आवंटित किया गया है।

सूची में सभी यू40 के नेतृत्व वाले उद्यमों में 53 कंपनियों का मूल्यांकन 1 अरब डॉलर से अधिक है, 48 का मूल्यांकन 20.1 से 50.0 करोड़ डॉलर के बीच, 23 का मूल्यांकन 50-100 करोड़ डॉलर के बीच और 17 का मूल्यांकन 10-20 करोड़ डॉलर के बीच है। स्नातक संस्थानों में आईआईटी खड़गपुर 15 पूर्व छात्रों के साथ अग्रणी है जिसके बाद आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मद्रास प्रत्येक के 10-10 पूर्व छात्र हैं। एवेंडस वेल्थ-हुरुन इंडिया यू40 लिस्ट 2025 में नाम दर्ज कराने के लिए आयु 36 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए न्यूनतम कारोबार मूल्यांकन 10 करोड़ डॉलर होना चाहिए। दूसरी पीढ़ी और उससे आगे के उद्यमियों के लिए यह रकम 20 करोड़ डॉलर होनी चाहिए।

विश्वसनीय देश के साथ हो सामरिक साझेदारी : सिंह

भास्वर कुमार

वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह

भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि भारत के लिए अगली पीढ़ी की हवाई ताकत प्रणालियों एवं हथियारों के विकास के लिए एक विश्वसनीय देश के साथ रणनीतिक साझेदारी करने का यह माकूल समय है। सिंह ने बुधवार को कहा कि भविष्य में सहयोग के लिए उन्नत सैन्य विमान इंजन को लेकर फ्रांस के साथ साझेदारी का निर्णय इस दिशा में एक बुनियाद के रूप में काम कर सकता है।

उन्होंने कहा कि दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच एक मजबूत सैन्य शक्ति, विशेष रूप से वायु की ताकत को बढ़ाना जरूरी हो गया है। सिंह ने कहा कि भारत के पास जरूरी इच्छाशक्ति और मानव पूंजी है मगर लेकिन इसे कुछ हद तक तकनीक से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएएफ प्रमुख राष्ट्रीय ने राजधानी में सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर ऐंड स्ट्रैटजिक स्टडीज द्वारा 'नैशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स' विषय पर आयोजित 22वें सुब्रत मुखर्जी सेमिनार में ये बातें कहीं।

उन्होंने यह आश्वासन जरूर दिया कि तकनीकी कमी समय के साथ दूर की जा सकती है। मगर सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आईएएफ की जरूरतों एवं इन्हें पूरा करने में लगने वाले समय भारत के पड़ोस में हो रही गतिविधियों से भी निर्धारित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और देश को विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मौजूदा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का समर्थन जारी रहना चाहिए और हमें अन्य 'मेक इन इंडिया कार्यक्रमों' में निवेश करने के लिए त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है ताकि हमें प्रौद्योगिकी मिले और निकट भविष्य में आवश्यक उत्पाद, हथियार और प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो पाएं। हमें तकनीक के साथ तालमेल बैठाने की जरूरत है।'

मौजूदा अनुसंधान एवं विकास प्रयासों का समर्थन जारी रहना चाहिए और हमें अन्य 'मेक इन इंडिया कार्यक्रमों' में निवेश करने के लिए त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता है

आईएएफ प्रमुख ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस तरह के कार्यक्रम भारत को अगली पीढ़ी की हवाई शक्ति प्रौद्योगिकियों में अंतर पाटने में किस तरह मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि, देश अपने दम पर सफल हो सकता है मगर इसमें समय अधिक लग जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक रुझानों के अनुरूप भारत को इसलिए प्रक्रिया तेज करने के लिए किसी अन्य देश के साथ साझेदारी करने की जरूरत है। सिंह ने कहा, 'हम सभी रणनीतिक साझेदारियों में हैं। अगली पीढ़ी के प्लेटफार्म एवं हथियारों के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करने का यह समय बिल्कुल सही है। यह उसी तर्ज पर किया जा सकता है जैसे हमने भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन के लिए किया है।'

सितंबर 2025 में अंतिम दो मिग-21 बाइसन स्क्वाड्रनों की सेवाएं समाप्त होने के बाद आईएएफ की युद्धक क्षमता घट कर 29 सक्रिय लड़ाकू स्क्वाड्रनों तक रह गई है जो पिछले 60 वर्षों में सबसे कम है। भारत के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होना अनिवार्य बताया गया है। इससे वायु सेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए विकल्पों की तलाश करने के लिए विवश होना पड़ा है। यह जरूरत इसलिए भी आन पड़ी है क्योंकि वायु सेना को अब तक एक भी तेजस मार्क-1ए विमान नहीं मिला है। ऐसे 180 विमान तैयार करने का ठेका सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है।

हालांकि, रक्षा खरीद बोर्ड ने पिछले सप्ताह फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन से 114 राफेल लड़ाकू विमानों के खरीद प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। इससे वायु सेना पर दबाव कुछ कम हो सकता है। प्रस्ताव पर अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद द्वारा विचार किया जाएगा जिसके बाद इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अंतिम मंजूरी मिल जाएगी। रक्षा सूत्रों के अनुसार जेट विमान 'मेक इन इंडिया' ढांचे के तहत खरीदा जाएगा जिसमें दसॉ एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करेगी।

भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सेवानिवृत्त

भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सेवानिवृत्त हो गईं। नौसेना की पूर्व कप्तान विलियम्स (60) ने नासा में 27 वर्षों से अधिक समय तक सेवाएं दीं और अंतरिक्ष स्टेशन के तीन मिशन में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में गुजारे। उन्होंने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी (स्पेसवॉक) समेत कई ऐतिहासिक उपलब्धियां अपने नाम की हैं। विलियम्स के पिता दीपक पांड्या जाने माने तंत्रिका विज्ञानी थे और वह मूल रूप से भारत के गुजरात के रहने वाले थे तथा उनकी मां उर्सुलीन बोनी पांड्या स्लोवेनियाई-अमेरिकी मूल की हैं।

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगलवार को बताया कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सेवानिवृत्ति का आदेश पिछले साल दिसंबर के अंत से प्रभावी हो गया। बोइंग की कैप्सूल परीक्षण उड़ान के दौरान विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में फंसे रहे बुच विलमोर ने पिछले साल गर्मियों में नासा छोड़ दिया था। नौसेना की पूर्व कप्तान विलियम्स (60) ने नासा में 27 वर्षों से अधिक समय तक सेवाएं दी हैं। उन्होंने 62 घंटे अंतरिक्ष में चहलकदमी का रिकॉर्ड भी बनाया।

अरावली पर जांच के लिए बने समिति

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि अवैध खनन से अपूरणीय क्षति हो सकती है, इसलिए वह अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की व्यापक एवं समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली के पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और न्यायमित्र के. परमेश्वर को चार सप्ताह के भीतर खनन क्षेत्र के विशेषज्ञ पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया, ताकि विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सके। पीठ ने कहा कि समिति इस न्यायालय के निर्देशन और निगरानी में कार्य करेगी। उच्चतम न्यायालय ने अपने उस आदेश को भी विस्तारित किया, जिसमें अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार करने वाले 20 नवंबर के निर्देशों को स्थगित रखा गया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय को सूचित किया गया कि छिटपुट स्थानों पर अवैध खनन हो रहा है, और पीठ ने राजस्थान सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया कि इस तरह का कोई भी अनधिकृत खनन नहीं होगा। अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर उठे विवाद के बीच उच्चतम न्यायालय ने 'अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा तथा उससे जुड़े मुद्दे' शीर्षक से इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था।

वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहन

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए वाहनों से होने वाला प्रदूषण सबसे अधिक जिम्मेदार है। इसके साथ ही, आयोग ने बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के लिए 15 दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की। आयोग की ओर से न्यायालय में पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली के पीठ को बताया कि 2015 से 2025 तक के अध्ययनों के विश्लेषण से पता चलता है कि दिल्ली में पीएम 2.5 (हवा में 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास के कण) की मौजूदगी का कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के भीतर प्राथमिक उत्सर्जन (धूल, कार्बन मोनोऑक्साइड) और द्वितीयक कण का मिश्रण है। द्वितीयक कण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की सूर्य के प्रकाश, पानी या अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनते हैं। सीएक्यूएम ने चरणबद्ध तरीके से कई उपायों को लागू करने की सिफारिश की। इनमें उत्सर्जन क्षमता के आधार पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर से समयबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से हटाना। दूसरे, पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण के तहत) 2.0 को सुदृढ़ बनाना और सुदूर संवेदन उपकरणों के माध्यम से सड़क पर चलने वाले वाहनों की निगरानी करना। इसके अलावा दिल्ली और एनसीआर में अधिक मार्गों और स्टेशनों के साथ क्षेत्रीय रेल परिवहन और मेट्रो रेल नेटवर्क को विस्तारित करना और मेट्रो और क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली को जोड़ने वाले मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट केंद्रों का विकास करना। इसके अलावा, गंतव्य-आधारित सार्वजनिक परिवहन ट्रैकिंग के साथ रियल टाइम यात्री सूचना प्रणाली के माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। * दिल्ली-एनसीआर में सभी वाहनों को शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए संबंधित इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों की समीक्षा और संशोधन करना। पुराने वाहनों को कबाड़ में भेजने के लिए उसके मालिकों को अधिक प्रोत्साहन राशि देना। **भाषा**

ओरिएण्टल इंश्योरेंस Oriental Insurance

(भारत सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लेट-ए, ब्लॉक 4, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली
फोन : 011–2434 8503, 8506

निविदा सूचना

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निवेश बाजार टर्मिनल एवं संबंधित विश्लेषणात्मक समाधान प्रदान करने के लिए योग्य और अनुभवी वेंडरों से सीलबंद भौतिक बोलियां आमंत्रित करती है।

विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए हमारी वेबसाइट **https://orientalinsurance.org.in/tenders** पर **Tenders** अनुभाग देखें।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 13.02.2026 को सायं 5:00 बजे तक

उप महाप्रबंधक (निवेश)

IRDAI Regn. No. 556
CIN: U66010DL1947GOI007158

PROFITMART

ISSUED IN PUBLIC INTEREST
PROFITMART SECURITIES PVT LTD (PSPL)

- पीएसपीएल अपने ग्राहकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन उत्पाद या कोई गारंटीकृत, आश्वस्त या डब्बा ट्रेडिंग प्रदान नहीं करता है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।
- पीएसपीएल ट्रेडिंग खातों के लिए नकद स्वीकार नहीं करता है, सभी लेनदेन केवल www.profitmart.in पर दिए गए बैंक खाते के विवरण के माध्यम से किए जाते हैं, किसी अन्य वेबसाइट के झांसे में न आएं।
- अपना ट्रेडिंग आईडी और पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें, पीएसपीएल और इसके कर्मचारी/अधिकृत व्यक्ति (एपी) कभी भी इनकी मांग नहीं करते है।
- हम अवैध गतिविधियों का समर्थन या अनुमति नहीं देते हैं, अपनी सुरक्षा और जानकारी की पुष्टि के लिए हमेशा हमारी आधिकारिक ग्राहक सेवा से संपर्क करें।
- कृपया ध्यान दें कि लेन-देन विवरण केवल हमारे पंजीकृत डोमेन **profitmart.in** / **profitmart.co.in** से ईमेल किए जाते हैं। अन्य आईडी से आने वाले ईमेल से सावधान रहें।

M/s. PROFITMART SECURITIES PVT. LTD.,
यूनिट संख्या 213, ओपल स्क्वायर, प्लॉट संख्या सी-1, ठाणे, मुंबई - 400604
ईमेल: support@PROFITMART.IN फोन: 020 49119119
◆ **NSE** सदस्यता सं. 14556 ◆ **BSE** सदस्यता सं. 6676 ◆ **MCX** सदस्यता सं. 40885
◆ **SEBI** पंजीकरण नं. INZ000093633 ◆ **CDSL SEBI** पंजीकरण नं. IN-DP-295-2016

जी आर एस ई GRSE

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited
(भारत सरकार का उपक्रम / A Govt. of India Undertaking), रक्षा मंत्रालय / Ministry of Defence
Regd and Corp Office: GRSE BHAVAN, 61, Garden Reach Road, Kolkata - 700 024
Web: www.grse.in, (CIN: L35111WB1934GOI007891)

ऑनलाइन बोली के लिए ई-निविदा सूचना
एनआईटी सं.: SCC/NK/NIC/OT(P)/RENO-RNC/214/RA-3364
दिनांक: 19.01.2026
विषय: विभाग-राँची यूनिट में नवीनीकरण कार्य
निविदा जमा देने की नियत तिथि: 12.02.2026 (12.30 बजे)
बोली-पूर्व बैठक की तिथि: 29.01.2026 (10.00 बजे)

1. विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https://eprocuregrse.co.in;** सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https://eprocure.gov.in/cppp/** और जीआरएसई वेबसाइट **https://grse.in/tender-published/** पर उपलब्ध होगा।
2. भौतिक रूप से बोली-पूर्व बैठक में उपस्थिति और साइट का दौरा एसओटीआर के अनुसार अनिवार्य है।
3. इस निविदा सूचना के विषय में तिथियों में कोई परिवर्तन सहित कोई परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

"In Pursuit of Excellence and Quality in Shipbuilding"

https://bankofbaroda.bank.in

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

निविदा सूचना

बैंक ऑफ़ बड़ौदा निम्नलिखित के लिए ऑनलाइन निविदा आमंत्रित करता है

क्र.सं.	निविदा का नाम	बोली जमा करने की अंतिम तिथि
1	सबस्क्रिप्शन-आधारित मॉडल में अतिरिक्त PIM उपयोगकर्ता लाइसेंसों की खरीद	12-फरवरी-2026
2	सीएसएमसी मॉडल में मल्टीफंक्शन प्रिंट/कॉपी/स्कैन मशीन की खरीद के लिए निविदा	12-फरवरी-2026

विवरण बैंक की वेबसाइट https://bankofbaroda.bank.in पर निविदा खंड के अंतर्गत तथा गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पर उपलब्ध है।

अन्य सूचना, यदि कोई हो, को बैंक की वेबसाइट https://bankofbaroda.bank.in पर निविदा खंड में और गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल पर जारी किया जाएगा। बोलीकर्ता कृपया आवेदन को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले इसे अवश्य देख लें।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 22.01.2026
मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी

150/25-26

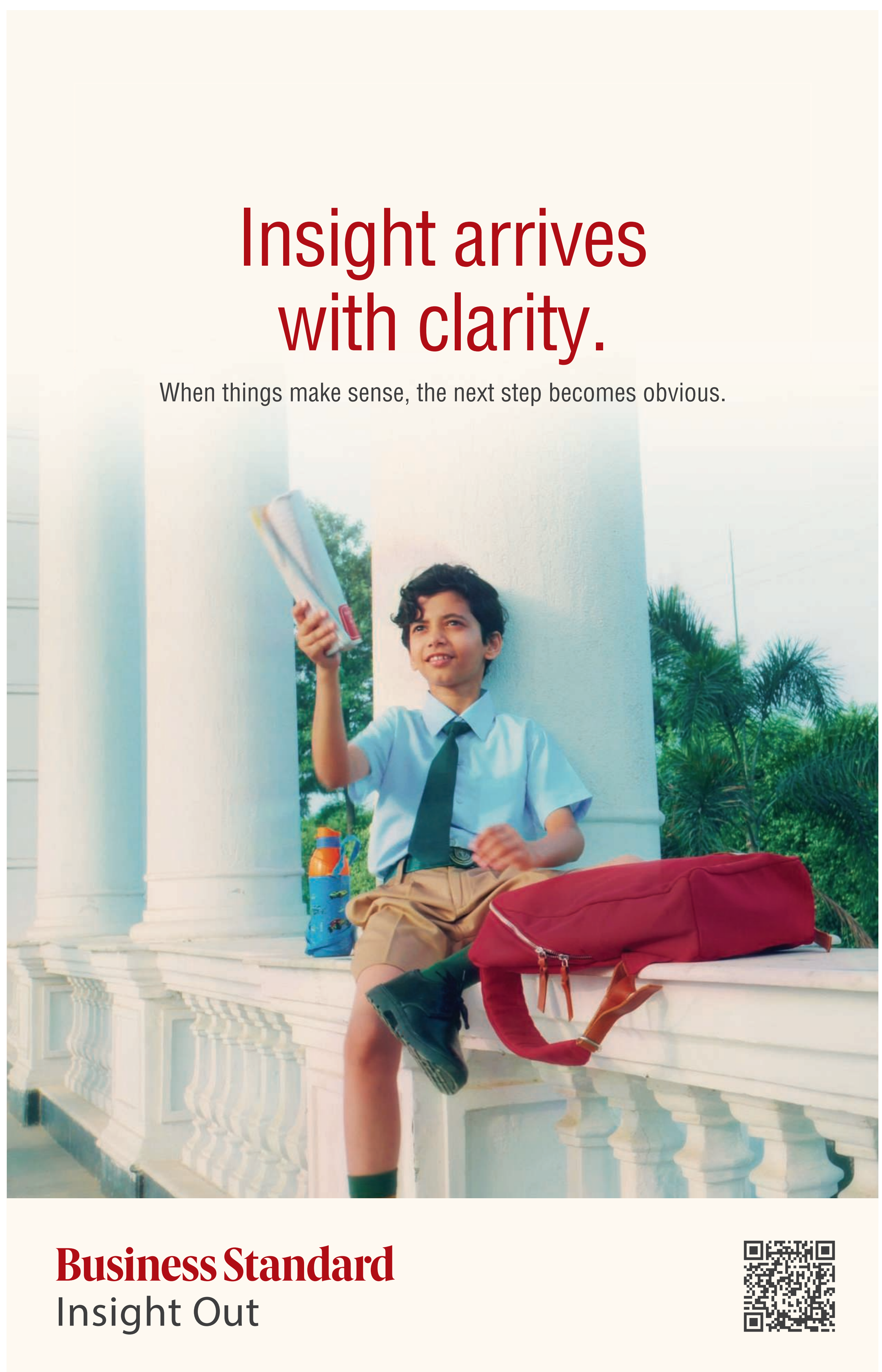

अमर उजाला

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 22 जनवरी 2026

प्रवाह

77 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 ● आगरा

दिखावा करना किसी मूर्ख इन्सान का बड़प्पन दिखाने का तरीका है। -ब्रूस ली

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक जानलेवा गड्ढे में गिरकर हुई युवक की मौत को महज सड़क दुर्घटना कहकर खारिज नहीं कर सकते। यह एक त्रासदी है, जो व्यवस्था की घनघोर विफलता को ही इंगित करती है।

एनसीआर में गड्ढा

एक युवा की मौत हमेशा ही दुखद होती है, लेकिन 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता ने नोएडा के सेक्टर-150 के जानलेवा गड्ढे में गिरकर जिस तरह से जान गंवाई, वह सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि समाज और राज्य की सामूहिक विफलता को भी इंगित करती है। इसे सड़क दुर्घटना कहकर खारिज करना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि घने कोहरे में कार पर नियंत्रण खोना एक बात है, और नियंत्रण खोने के बाद करीब दो घंटे तक जीवित रहते हुए मौत का इंतजार करने पर मजबूर होना पूरी तरह दूसरी। उल्लेखनीय है कि युवराज मेहता रात के समय कार से अपने घर लौट रहे थे। घने कोहरे की वजह से रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। उनकी कार सड़क के किनारे पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, जो एक निर्माणाधीन साइट का हिस्सा था। उन्होंने अपने पिता को फोन कर जान बचा लेने की गुहार भी लगाई। क्षोभ का विषय है कि वहां कोई रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं था, सिर्फ एक कम ऊंचाई की दीवार थी, जो ऐसी दुर्घटनाओं को आमंत्रण देने वाली ही थी। पिता मौके पर पहुंचे, आपदाओं से निपटने वाले बल भी पहुंचे, पर अपर्याप्त संसाधनों के चलते होने वाली देरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुर्घनाग्रस्त कार को ढूंढने में तीन दिन लग गए। कुछ ही दिन पहले इसी जगह पर एक ट्रक भी पानी में चला गया था, तब बड़ी मुश्किल से ड्राइवर को बचाया जा सका था। स्थानीय निवासी भी समय-समय पर चेतावनी संकेतों और सुरक्षा के पर्याप्त उपाय न होने की शिकायत करते रहे हैं। इसके बावजूद अगर यह हादसा हुआ है, तो यह महज दुर्घटना नहीं है, बल्कि राज्य की उदासीनता, प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही की कमी का सीधा नतीजा है। हादसे के बाद, जैसा कि अमूमन ऐसे मामलों में होता है, बिल्डर, अधिकारियों इत्यादि पर कार्रवाइयों और विशेष जांच दल के गठन की औपचारिकता हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि शिकायतों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारी व्यवस्थाएं क्या इतनी कमजोर हैं कि एक युवक की पुकार सुनकर भी उसे नहीं बचा सकतीं? यह हालत एक्सप्रेसवे व आईटी पार्कों से घिरे नोएडा की है, जो वर्षों से देश के शहरी भविष्य का प्रतीक माना जाता रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक के बजट के बावजूद अगर हमारी व्यवस्थाएं ऐसी चौपट हैं, जैसी इस मामले में दिखी हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। पिछले साल वडोदरा में गंभीरा नदी पर पुल का ध्वस्त होना हो या फिर इसी महीने इंदौर में दूषित जल का प्रकोप और अब एनसीआर का जानलेवा गड्ढा, ये सभी दरअसल शहरी भारत की उन विडंबनाओं की ओर इशारा करते हैं, जिन पर गौर किए बगैर आखिर हम विकसित भारत के स्वप्न को कैसे पूरा करेंगे?

शेखी बघारना और बात है

आर्थिक विकास में अमेरिका निस्संदेह दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन तमाम शोध बताते हैं कि अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के मामले में वह लिथुआनिया जैसे देशों से भी पीछे है। मजे की बात है कि चाहे ट्रंप हों, बाइडन हों या ओबामा, इस गिरावट को रोकने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया।

निकोलस क्रिस्टोफ
द न्यूयॉर्क टाइम्स

अमेरिकी शेखी बघारना पसंद करते हैं कि हम दुनिया में सबसे अव्वल हैं। निश्चित रूप से वे दूसरे देशों पर हमला करने और विदेशी नेताओं को अगवा करने की अपनी सैन्य क्षमता में अव्वल हैं। लेकिन आम नागरिकों की भलाई के मामले में? हाल ही में जारी *सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स* नामक अध्ययन बताता है कि जीवन की गुणवत्ता के मामले में, अमेरिका 171 देशों में 32वें स्थान पर है और पोलैंड, लिथुआनिया और साइप्रस जैसे देशों से पीछे है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, दोनों राष्ट्रपतियों के समय में रैंकिंग में अमेरिका लगातार नीचे गिरता गया और अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा स्वास्थ्य देखभाल और दूसरी सेवाओं में कटौती के कारण यह और नीचे गिरेगा। *सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स* 2010 में विद्वानों और विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय टीम ने पेश किया था। 2011 में अमेरिका 18वें नंबर पर था।

चिंताजनक होने के बावजूद तब भी फ्रांस, इटली और स्पेन से अमेरिका आगे था। लेकिन अब वे देश अमेरिका से आगे निकल गए हैं। इस सूचकांक को प्रकाशित करने वाले समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल ग्रीन ने कहा कि *सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स* में 12 घटक हैं, और 2011 से अमेरिका इन सभी की रैंकिंग में नीचे गिरा है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि अमेरिका में जीवन की गुणवत्ता सिर्फ कुछ छोटे स्कैंडिनेवियाई देशों से ही नहीं, बल्कि अमेरिका के सभी जी-7 प्रतिस्पर्धियों से भी खराब है। अमेरिका स्लोवेनिया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जैसे पुराने कम्युनिस्ट देशों और दक्षिण कोरिया जैसे दूसरे नए लोकतंत्रों से भी पीछे रह गया है।

वह कहते हैं कि अमेरिका ने एक आर्थिक महाशक्ति और सामाजिक प्रगति की महाशक्ति बनकर शीतयुद्ध जीता था। लेकिन पिछले 30 वर्षों में, अमेरिका ने सामाजिक प्रगति के मामले में सब यों ही चलने दिया है। *सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स* बेशक सिर्फ एक पैमाना है, और कोई इस या उस स्कोर पर बहस कर सकता है। लेकिन विभिन्न देशों में जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए यह वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के इस्तेमाल करने का एक उपयोगी तरीका है। इस सूचकांक के अनुसार, सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका 99वें स्थान पर है, यानी वह पाकिस्तान और निकारागुआ से भी पीछे है। स्कूली शिक्षा (बारहवीं तक) के मामले में अमेरिका 47वें स्थान पर आता है, जहां वह वियतनाम और कजाकिस्तान से नीचे है। वहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमेरिका 45वें स्थान पर है और इस मामले में भी वह अर्जेंटीना और पनामा से पीछे ही है। खुशहाली के आधार पर देशों का आकलन करने की ज्यादातर दूसरी कोशिशें भी दिखाती हैं कि हाल के वर्षों में अमेरिका संघर्ष कर रहा है।

हालिया *वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट*, जो खुशी और लोग अपनी जिंदगी का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इस बारे में मतदान के आधार पर देशों की रैंकिंग तय करती है, उसमें अमेरिका 24वें स्थान पर है, जो एक दशक पहले के 15वें स्थान से नीचे है। अटलांटिक काउंसिल के *फ्रीडम इंडेक्स* में अमेरिका 22वें नंबर पर गिरावट की तरफ है, और इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के *डेमोक्रेसी इंडेक्स* में अमेरिका 28वें नंबर पर है। इस साल अमेरिकी आजादी के घोषणापत्र की 250वीं सालगिरह है, जिसमें 'जीवन, आजादी और खुशी की तलाश' का जश्न मनाया जाता है। एक तरह से, *सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स* और ये दूसरे आकलन उपकरण मूल्यांकन करते हैं कि अमेरिका अपने ही पैमानों के हिसाब से दुनिया में किस स्थान पर है। निश्चित रूप से आर्थिक विकास के मामले में अमेरिका ने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वह उस जीडीपी विकास को उन चीजों में बदलने में पीछे रह जाता है, जिनकी आम लोगों को सबसे अधिक परवाह है। इसके उलट, लातविया को लें। इसकी प्रति व्यक्ति जीडीपी अमेरिका की आधी से भी कम है, लेकिन *सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स* में इसके अंक अमेरिका जैसे ही हैं। लगता है कि आंकड़े इकट्ठा करने के मामले में (जैसे नवजात बच्चों की मृत्यु दर) अमेरिका कुछ दूसरे देशों से ज्यादा ईमानदार है, और चिंता की बात है कि पश्चिमी यूरोप, अपनी सामाजिक तरक्की के बावजूद, एक ऐसा आर्थिक मॉडल अपना रहा है, जो नवाचार और दीर्घकालीन विकास को दबाता है। फिर भी, यह सूचकांक कुछ हकीकत भी दर्शाता है। यह उस निराशा और असंतोष को समझाता है, जिसने दक्षिणपंथी डोनाल्ड ट्रंप और वामपंथी जोहरान ममदानी की चुनाव जीतने में मदद की। जब अमेरिकी कहते हैं कि व्यवस्था उनके लिए काम नहीं कर रही है, तो ये रैंकिंग ही बताती हैं कि उन्हें ऐसी निराशा क्यों महसूस होती है। जैसा कि मैंने कहा था, हालात और खराब हो सकते हैं। ट्रंप के स्वास्थ्य देखभाल में कटौती के फैसले से सालाना 51,000 लोगों की जान जा सकती है और हर साल 1,01,000 नशे की लत के मामलों तथा 1,38,000 मधुमेह के मामलों का भी इलाज नहीं हो पाएगा। उदारवादी लोग शायद ट्रंप की कमियों पर ध्यान दिलाना चाहें। लेकिन यहां कुछ और भी बड़ा हो रहा है: लगभग 1970 से, अमेरिका जीवन की गुणवत्ता के पैमानों पर दूसरे देशों से पीछे चल रहा है। ग्रीन कहते हैं कि 'इसके जिम्मेदार सिर्फ ट्रंप नहीं हैं।'

ओबामा और बाइडन ने भी इस गिरावट को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया, और न ही बुश या क्लिंटन ने। यह कई राष्ट्रपतियों की निष्क्रियता से हुआ धीमा पतन है। फिर भी, ऐसा लगता है कि बढ़ते शेयर बाजार और आर्थिक विकास से मतदाता सुन्न हो गए थे, जब तक कि हाल के वर्षों में लोगों को यह स्पष्ट नहीं हो गया कि उनके जीवन का स्तर ठहर गया है और इसीलिए उन्होंने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' और ट्रंप के लोकलुभावन वादे का रुख किया।

तो इसका समाधान क्या है? इसका एक हिस्सा मानव पूंजी में निवेश हो सकता है-बच्चों, शिक्षा और कौशल स्तर के उन्नयन में। इसमें बचपन की शुरुआती पहलों से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण तक, ड्रग उपचार से लेकर सामुदायिक कॉलेजों तक, सब कुछ शामिल हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की लगातार गिरती साख अमेरिकियों के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। अमेरिका वैसा देश नहीं है, जैसा वह खुद को समझता है। उसे इस आत्मसंतुष्टि को छोड़ देना चाहिए। हालांकि, वह इस बात पर खुश हो सकता है कि देशभक्ति के मामले में वह 32वें स्थान पर है।

©The New York Times 2026

जीवन धारा

दलाई लामा

मन आपका शत्रु नहीं है, बल्कि वह तो केवल प्रशिक्षित होना चाहता है। जब आप मानसिक अभ्यास शुरू करते हैं, तो अपने ही मन के भीतर एक गहरी यात्रा पर निकलते हैं। यहां मन ही साधन होता है और लक्ष्य भी।

विचारों के साथ युद्ध नहीं, संवाद करें

अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मन को प्रशिक्षित करना इतना कठिन क्यों है? सच तो यह है कि यह दुनिया की सबसे सुंदर कला है, लेकिन इसके लिए थोड़े धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम मानसिक अभ्यास शुरू करते हैं, तो हम अपने ही मन के भीतर एक गहरी यात्रा पर निकलते हैं। यहां मन ही हमारा साधन होता है और लक्ष्य भी। इसलिए चुनौतियां आना स्वाभाविक है।

मुख्य रूप से दो ऐसी बाधाएं हैं, जो एक नौसिखिए और अनुभवी, दोनों के मार्ग में आती हैं: पहली है भटकाव और दूसरी है मानसिक सुस्ती, यानी आलस्य।

शुरुआत में हमारा मन एक चंचल बच्चे की तरह होता है। वह यहां-वहां भागता रहता है। लेकिन धीरे-धीरे यही भटकाव उत्तेजना का रूप ले लेता है और हम अपने शांति हासिल करने के लक्ष्य को भूल जाते हैं। ऐसे क्षणों में खुद से संघर्ष करना व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में, गहरी और छोटी-छोटी सांसें लें। सकारात्मक वाक्यों-जैसे, 'मैं तनाव से मुक्त हो रहा हूं' का सहारा लें और इसे बार-बार दोहराएं। यदि मन फिर भी न माने, तो अभ्यास रोक दें। एक बात हमेशा याद रखें कि मन आपका शत्रु नहीं है, बल्कि वह तो केवल प्रशिक्षित होना चाहता है। इसलिए, कभी-कभी केवल अपने अभ्यास के उद्देश्य को स्मरण करना ही पर्याप्त होता है। और कभी-कभी करुणा के साथ अभ्यास को कुछ समय के लिए छोड़ देना भी बुद्धिमानी होती है। अभ्यास का अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि जागरूक लचीलापन है।

दूसरी बाधा है आलस्य, जिसे मैं 'मानसिक गोता' कहता हूं। कभी-कभी हमारा मन इतना शांत और शिथिल हो जाता है कि हमारी ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है। हमें लगता है कि हम बहुत शांत हैं, लेकिन असल में हम 'जागरूक' नहीं होते। याद रखें, केवल शांति ही हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य स्थिरता के साथ सतर्कता होना चाहिए। बिना पैनेपन की शांति वैसी ही है, जैसे कोई गहरी नींद में हो। यदि हम बहुत देर तक शिथिल अवस्था में रहते हैं, तो मन की तीक्ष्णता कम होने लगती है और हम वर्तमान क्षण से दूर जाने लगते हैं। इस स्थिति से बाहर निकलने के उपाय भी करुणा से भरे होने चाहिए। ऐसे में, उज्ज्वल प्रकाश की कल्पना करें, मानो चेतना भीतर से प्रकाशित हो रही हो। आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले लोग किसी श्रेष्ठ व पवित्र आकृति का स्मरण कर सकते हैं। या फिर यह कल्पना करें कि आपकी चेतना हल्की होकर आकाश की ओर उछल रही है।

हर व्यक्ति के लिए अभ्यास का मार्ग अलग-अलग हो सकता है। लेकिन अभ्यास का सौंदर्य इसी में है कि आप सबसे पहले खुद को जानें कि कौन-सा उपाय आपके लिए उपयोगी है, और इसे धैर्य से खोजें। जब भी आपको लगे कि आप मार्ग से भटक रहे हैं या आलस्य आपको घेर रहा है, तो रुकें और अपनी मानसिक अवस्था को फिर से सक्रिय और जागरूक बनाएं।

मन को बेहतर करते रहें

सूत्र

जीवन में आगे बढ़ने के लिए मन को दबाना नहीं, समझना पड़ता है। स्वयं के प्रति उदार रहना और हर पल जागरूक बने रहना ही आत्म-साक्षात्कार का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। अभ्यास का अर्थ हर दिन खुद से ईमानदार संवाद करना है। धैर्य, करुणा और सतर्क अभ्यास से मन मित्र बन जाता है।

दूसरा पहलू

गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथियों की परंपरा 1950 से जारी है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो पहले मुख्य अतिथि थे।

गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथियों की परंपरा

देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथियों की परंपरा 1950 से जारी है। बेशक, मुख्य अतिथि की उपस्थिति न केवल 26 जनवरी को निकलने वाली परेड की शोभा बढ़ाती है, बल्कि द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को गति देती है।

विवेक शुक्ला

पहले परेड इर्विन स्टेडियम (दादा ध्यानचंद स्टेडियम) में आयोजित होती थी। 1955 से यह राजपथ (कर्तव्य पथ) पर आयोजित होने लगी।

इस परंपरा का महत्व भारत की विदेश नीति के साथ गहराई से जुड़ा है। मुख्य अतिथि के चयन से भारत अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाता है। यह भारत की सैन्य शक्ति प्रदर्शन का जरिया भी है।

भारत जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उस समय परेड इर्विन स्टेडियम (अब दादा ध्यानचंद स्टेडियम) में आयोजित की गई थी। हालांकि, 1952 और 1953 के गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न कारणों से कोई मुख्य अतिथि नहीं था। 1955 से परेड राजपथ (अब कर्तव्य पथ) पर स्थायी रूप से आयोजित होने लगी। 1955 में पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया। वह महिंद्रा एंड महिंद्रा के संस्थापकों में से एक थे।

1960 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति क्लिमेंट वोरोशिलोव और 1961 में ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ द्वितीय जैसे नेता गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए। 1966 में कोई अतिथि नहीं था। अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों का 1970 के दशक में प्रतिनिधित्व बढ़ा। 1980 के दशक में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, और मुख्य अतिथियों के चयन में विकसित देशों पर जोर दिया गया। 1995 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला आए। इस दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और पूर्वी यूरोप के देशों पर ध्यान केंद्रित हुआ। 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और 2010 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली म्युंग-बाक जैसे नेता मुख्य अतिथि बने। इस दशक में भारत की 'लुक ईस्ट' नीति पर जोर दिया गया। 2015 में बराक ओबामा, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति, मुख्य अतिथि थे। यह भारत-अमेरिका संबंधों में मील का पत्थर था। 2018 में आसियान के 10 नेता (पहली बार सामूहिक आमंत्रण) मुख्य अतिथि बने। 2021 व 2022 में कोविड के कारण कोई मुख्य अतिथि नहीं था। मिस्र के राष्ट्रपति 2023 में, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 2024 में, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 2025 में मुख्य अतिथि बने।

इस परंपरा का महत्व भारत की विदेश नीति के साथ गहराई से जुड़ा है। मुख्य अतिथि के चयन से भारत अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाता है। यह परंपरा न केवल सैन्य शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम भी है, जहां मुख्य अतिथि भारतीय संस्कृति, विविधता और प्रगति से परिचित होते हैं।

आंकड़े

यूएई के साथ व्यापार

भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसे 2032 तक दोगुना करने का लक्ष्य है।

2025	8.63
2024	7.50
2023	7.27
2022	7.04
2021	6.31

आंकड़े दोनों देशों के बीच साल दर साल बढ़ते व्यापार के, प्रतिशत में। | स्रोत : वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

सारा भोजन खत्म होने वाला था, पर विघ्नहर्ता का पेट नहीं भरा। तब माता अनुसूया ने सिद्धिविनायक को मोदक का भोग लगाया, जिससे उनकी भूख शांत हुई।

मोदक का भोग

अंतर्यात्रा
संकलित

हिंदू परंपरा में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ विघ्नहर्ता श्री गणेश के स्मरण से किया जाता है। आज गणेश जयंती का पावन पर्व है, जिसे तिलकुंड चतुर्थी व वरद चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है।

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक बार महर्षि अत्रि और माता अनसूया के आश्रम में भोलेनाथ और माता पार्वती अपने पुत्र बाल गणेश के साथ अतिथि के रूप में पधारे। बाल गणेश ने कहा कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। माता अनसूया ने पहले बाल गणेश को भोजन कराने का निश्चय किया और भगवान शिव से प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। पार्वतीनंदन को जितना भोजन परोसा जाता, वह समाप्त हो जाता। लेकिन उनकी भूख शांत न होती। यह देखकर माता अनसूया, भगवान शिव और माता पार्वती सभी आश्चर्य में पड़ गए। माता अनसूया को चिंता हुई कि यदि सारा भोजन इसी तरह समाप्त हो गया, तो शेष अतिथियों के लिए कुछ नहीं बचेगा।

तभी माता अनसूया ने सोचा कि शायद मीठा खाने से गजानन की भूख शांत हो जाए। उन्होंने प्रेमपूर्वक मोदक का भोग लंबोदर को अर्पित किया। मोदक खाते ही गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हो गए, उनकी भूख शांत हो गई और उन्होंने आनंद से जोरदार डकार ली। महादेव ने भी कहा कि उनका भी पेट भर गया है।

मान्यता है कि इसी कारण मोदक सिद्धिविनायक का प्रिय भोग बना और तभी से उन्हें मोदक अर्पित करने की परंपरा चली आ रही है।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 22 जनवरी, 1952

जेलों में क्रांतिकारी सुधार, डंडा-बेड़ी बंद

यू०पी० की जेलों में क्रांतिकारी सुधार, डंडा-बेड़ी बन्द हुई

उत्तर प्रदेश की सरकार ने जेलों में कई क्रांतिकारी सुधार किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाने लगा है। जेलों में डंडा-बेड़ी की घातक सजा देने की प्रथा हमेशा के लिए बंद कर दी गई है।

क्या इस ठंड बारिश नहीं होगी

ठंड के मौसम में अब तक बारिश का न होना, एक घटना नहीं, बल्कि एक वैश्विक संकट का स्थानीय संकेत है।

पंकज चतुर्वेदी | **मुद्दा**

लाख जतन करने के बाद भी दिल्ली और उसके 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे की हवा प्रदूषण से जकड़ी हुई है और इसके निदान के लिए जिस बरसात का इंतजार है, वह कोई ढाई महीने से नदारद है। उत्तर भारत इस समय जिस तरह की मौसमी विसंगति के दौर से गुजर रहा है, यह भविष्य की भयावहता का गहरा संकेत है। हिमालय की गोदी में बसे आठ राज्य शून्य बरसात और कम बर्फबारी से हैरान हैं।

उत्तराखंड में ऐसा वर्ष 2016 के बाद पहली बार हुआ, जब दिसंबर में बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। इस वर्ष समूचे उत्तरी भारत में जाड़ा अपनी पूरी ठिठुरन के साथ उपस्थित तो है, लेकिन इसमें वह नमी और सौम्यता गायब है, जो जीवन का आधार होती है। कड़ाके की ठंड के बावजूद आसमान का साफ होना और पहाड़ों का भूरा दिखना केवल मौसम का मिजाज भर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी 'मौन आपदा' है, जिसका प्रभाव आने वाले कई महीनों तक हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और खाद्य

सुरक्षा पर पड़ने वाला है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैले इस पारिस्थितिकी तंत्र में उत्तर का हिमालयी क्षेत्र एक 'जल मीनार' की तरह कार्य करता है, लेकिन इस बार मीनारें सूखे की चपेट में हैं।

कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सर्दी के मौसम में वर्षा का घाटा 95 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच गया है। पहाड़ों पर होने वाली इस 'सूखी ठंड' का सीधा असर बागवानी पर पड़ रहा है। सेब के बागानों को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए जिन 'चिलिंग आवर्स' की आवश्यकता होती है, वे पर्याप्त नमी और बर्फ के बिना अधूरे हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नमी की इस कमी के कारण सेब की पैदावार और गुणवत्ता में 20 से 25 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। मैदानी इलाकों, विशेषकर दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में यह सूखी ठंड एक 'विषाक्त जाल' बन गई है।

सामान्यतया सर्दियों की बारिश (मावठ) हवा में मौजूद धूल और धुएं के कणों को साफ कर देती है, लेकिन इस बार बारिश न होने से प्रदूषण के कण जमीन के करीब ही ठहरे हुए हैं। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार 'बेहद खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है। नमी रहित यह ठंडी हवा शरीर से प्राकृतिक पानी सोख लेती है, जिससे न केवल त्वचा और आंखों से जुड़े रोग बढ़ रहे हैं, बल्कि अस्पतालों में श्वसन और हृदय संबंधी रोगियों की संख्या में भी 30 से 40 प्रतिशत का उछाल देखा गया है।

कृषि प्रधान भारत के लिए पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रबी की फसल, विशेषकर गेहूं, इस समय नाजुक दौर में है। प्रकृति की ओर से मिलने वाली बारिश के अभाव में किसानों को बार-बार सिंचाई का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है। यदि तापमान में इसी तरह उतार-चढ़ाव बना रहा और नमी नहीं लौटी, तो गेहूं के दाने समय से पहले पक कर छोटे रह सकते हैं, जो देश के अन्न भंडार के लिए चिंता का विषय है।

बरसात न होने से कश्मीर में झेलम जैसी सदानीरा नदी सूख रही है और राज्य के कई पनबिजली संयंत्र अपनी क्षमता का 40 फीसदी उत्पादन ही कर पा रहे हैं। इस तरह के मौसम से हिमाचली राज्यों के जंगलों में कई जगहों पर आग की घटनाएं समय से पहले और बड़ी संख्या में देखने को मिल सकती हैं और इसका सीधा असर जंगली जीवों और इन्सानों के बीच टकराव के रूप में दिखाई पड़ रहा है।

हिमालयी क्षेत्रों में इस वर्ष सर्दियों के दौरान बारिश और पर्याप्त बर्फबारी न होने से बागवानी पर भी असर पड़ रहा है। नैनीताल जिले के रामगढ़, सूपी, सतबुंगा, धानाचूली सहित फलपट्टी क्षेत्र में बड़ी संख्या में फलदार वृक्षों पर बेमौसम फल और फूल आ गए। आमतौर पर यह मौसम पेड़ों के लिए डॉरमेंसी (शीतविराम) अवस्था का होता है, जब ठंड, बारिश व बर्फबारी के चलते पेड़ सुप्तावस्था में रहते हैं। लेकिन अभी जाड़े में न तो बरसात हुई न ही बर्फ गिरी, सो मिट्टी में नमी कम हो गई। इस जैविक संतुलन के बिगड़ने से पौधों का फेनोलॉजिकल कैलेंडर प्रभावित हुआ है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, तो अल-नीनो का बढ़ता प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के कारण बदलते वायुमंडलीय दबाव ने 'पश्चिमी विक्षोभ' की धार कुंद कर दी है। यह एक वैश्विक संकट का स्थानीय स्वरूप है। समझना होगा कि बर्फ का पर्याप्त मात्रा में न गिरना और बादलों का न बरसना केवल एक वर्ष की घटना नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की एक गंभीर चेतावनी है।

अब समय आ गया है कि हमारी नीतियों में जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल कृषि को सर्वोपरि रखा जाए। प्रकृति अपना संतुलन खो रही है, और यदि मानवीय हस्तक्षेप ने इसे सुधारने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, तो ये 'सूखे जाड़े' भविष्य की स्थायी पहचान बन सकते हैं।

edit@amarujala.com

दीपक कुमार
- कक्षा : 2
- स्कूल : भारत राम ग्लोबल स्कूल, नॉलेज पार्क 3, ग्रेटर नोएडा

शिवांश
- कक्षा : 2
- स्कूल : रामाग्या स्कूल, नोएडा

बच्चो! एक कोना सिर्फ आपके लिए

अपनी प्रविष्टियां भेजें-

प्रविष्टियां अपने फोटो के साथ हमें del-cityincharge@del.amarujala.com पर भेजें। साथ में अपना पूरा पता, संपर्क नंबर, स्कूल का नाम, कक्षा भी लिखें।

आप अपनी प्रविष्टियां हमें डाक के जरिये भी भेज सकते हैं। हमारा पता है- अमर उजाला लिमिटेड, सी-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301

नोट : प्रकाशन का अधिकार अमर उजाला के पास सुरक्षित।

बच्चों ये भी जानो

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इससे पहले भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन तब तक अपना संविधान लागू नहीं हुआ था। यह दिन हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी बोध कराता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं की झांकियां और राज्यों की सांस्कृतिक झांकियां निकलती हैं।

पन्नों पर सवार बचपन की सबसे खूबसूरत यात्रा

हाल ही खत्म हुए विश्व पुस्तक मेले से लौटे कुछ बच्चों ने अमर उजाला ने अपने जीवंत अनुभव को साझा किया। कई तो किताबों की दुनिया देखकर अवाक रह गए। कोई अपने पापा तो कोई अपनी मम्मी के साथ पिकनिक मनाने के इरादे से पहुंचा लेकिन किताबों के संसार में पहले तो अपने परिजनों के साथ घूमते रहे। फिर अचानक जब बच्चें अपनी मनपसंद किताबों के स्टॉल पर पहुंचे तो चहक उठे। उनकी इस खुशी में मम्मी-पापा भी शरीक हुए क्योंकि वह भी चंपक, कॉमिक्स के जरिये अपने बचपन से रुबरु हुए। बच्चों की चहक किड्स एक्सप्रेस में जाकर खिलखिलाहट में बदल गई...इस थीम पर तीनों का जीवंत अनुभव साझा कर दीजिए। तीनों की बातें मिलती न हों और अलग-अलग हों...

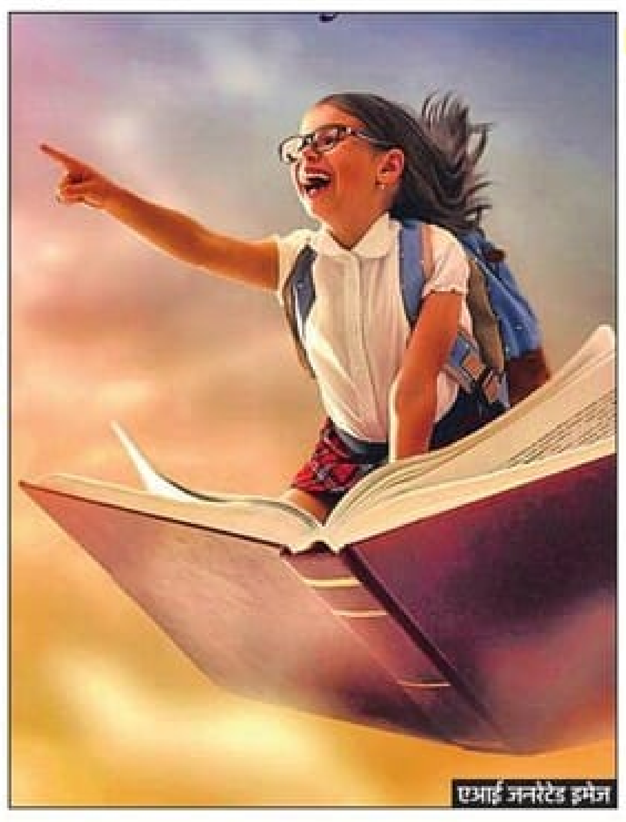

एआई जनरेटेड इमेज

बात तुम्हारी

आलोक का उत्साह

मैं पापा के साथ ऐसे ही घूमने निकला था। उन्होंने कहा था–आज पिकनिक मनाएंगे। मुझे लगा, कार से घूमने में मजा आएगा लेकिन पापा मेट्रो की ओर चल पड़े उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के पास मेट्रो स्टेशन पर उतरा फिर 10 नंबर गेट पर पहुंचा। यहां शटल सेवा से पुस्तक मेला पहुंचे। पहले लगा कहां ले आए पापा। हॉल में प्रवेश करते ही किताबों के बड़े-बड़े स्टॉल दिखें। पापा तो अपनी पसंद की किताब देखने लगे। मैं भी पेज पलटने लगा। इस बीच कॉमिक्स वाले स्टॉल पर पहुंचा तो मैं उछल पड़ा। पापा मुस्कुराए और बोले, ये तो हम भी पढ़ते थे। उन्होंने मुझे चंपक दिलाई और खुद पुरानी कॉमिक्स पलटने लगे। हम जब किड्स एक्सप्रेस पहुंचे तो मेरी खुशी दोगुनी हो गई। ट्रेन जैसी जगह, टिकट चेकर और रंगीन खिड़कियां देखकर लगा–यहां पढ़ाई भी मस्ती है।

- कक्षा : 9
- स्कूल : सर्वोदय विद्यालय प्रशांत विहार, दिल्ली

अराध्या का अनुभव

मैं मम्मी के साथ आई थी। शुरू में हम साथ-साथ घूमते रहे, तस्वीरें लीं। हर तरफ किताबें देखकर मैं थोड़ी हैरान भी थी। फिर बच्चों की कहानियों वाले स्टॉल पर पहुंची और वहीं रुक गई। तभी मम्मी भी कॉमिक्स देखने लगीं और बताने लगीं कि उन्हें कैप्टन ध्रुव बेहद पसंद था। उनकी आखों में चमक देखकर मुझे अच्छा लगा। फिर तो मम्मी अपनी बचपन की शरारतें ऐसे बताने लगीं कि जैसे मैं उनकी बेटी नहीं सहेली हूं। कहने लगीं किताबों के बीच में कॉमिक्स छिपाकर पढ़ती थी और खत्म करने के बाद ही अपने कोर्स की किताबें पढ़ती थी। इस चक्कर में उन्हें भी अपनी मम्मी यानी मेरी नानी से डांट और पिटाई भी लगी है। हम अच्छे हैं कि हमें कोई नहीं पीटता है। किड्स एक्सप्रेस में जाकर समय का पता ही नहीं चला। कठपुतली शो देखकर मजा आया।

- कक्षा : 8
- स्कूल : केंद्रीय विद्यालय मयूर विहार, दिल्ली

रुद्राक्ष की सीख

मैं मम्मी-पापा दोनों के साथ गया था। शुरू में हम हर हॉल देखते हुए आगे बढ़ते रहे। मुझे किताबें अच्छी लगती हैं, लेकिन इतनी सारी किताबें एक साथ देखकर मैं चुप हो गया। फिर विज्ञान और कार्टून वाली किताबों के स्टॉल दिखे। मम्मी ने कहा–जो अच्छा लगे, चुन लो। पापा भी साथ खड़े होकर किताबें देखने लगे। किड्स एक्सप्रेस में पहुंचकर माहौल बिल्कुल बदल गया। वहां सीखना खेल जैसा था। बच्चों की हंसी, रचनात्मक गतिविधियां और किताबों के बीच घूमना–सब कुछ यादगार बन गया। किताबों की दुनिया से बाहर निकले तो पापा के साथ नाटक की दुनिया में पहुंच गए। फिल्म स्क्रीन से अलग हटकर प्ले देखकर लगा कि कैसे सारे डॉयलॉग याद करते होंगे। फिल्मो में तो रिटेक का भी मौका होता लेकिन यहां तो आपकी एक गलती और पूरा प्ले खराब।

- कक्षा : 3
- स्कूल : राघव राव कसल पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली

नविशा झा
- कक्षा : 4
- पता : ईको विलेज, ग्रेटर नोएडा वेस्ट

मां का दूध

निजात का पहला मधुर स्रोत,
मां का दूध, संजीवनी की बोत।
संपोषण, सुरक्षा, स्नेह का सार,
शिशु जीवन का यह पहला उपहार।

चलें शोधों की बात करें,
बड़े-बड़े डाक्टर भी यही कहें–
जच्चा-बच्चा का पहला स्पर्श,
इस बंधन में छुपा है प्रेम का हर्ष।

बाजार की डिब्बाबंद चीजें नहीं,
प्राकृतिक अमृत से बढ़कर कहीं?
सलाह है यही हर मां को प्यारी,
छह महीने तक दूध न हो कोई दुश्वारी।

केवल मां का दूध ही पिलाएं,
शिशु को रोगों से दूर ले जाएं।
इसमें पोषण, इसमें शक्ति,
इसमें छुपी हर जीवन भक्ति।

तो हे मां, इस धरोहर को जानो,
अपने शिशु को इसका स्वाद चखाओ।
मां का दूध ही सबसे बड़ा उपहार,
इससे सुंदर नहीं कोई संसार।

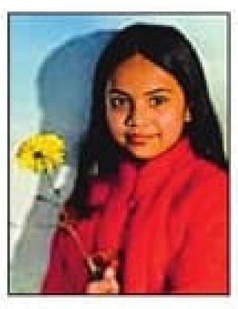

नविशा झा
- कक्षा : 5
- पता : गोल मार्केट, नई दिल्ली

नजर या है दूरबीन

पछियों की आंखें हम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। कुछ तो हमें किलोमीटरों दूर से भी पहचान लेते हैं। अगर प्रतियोगिता दूर देखने की हो तो चील को गोल्ड मेडल मिलेगा।

नन्ही कलम

आसमान में एक तितली उड़ने लगी है,
अपने पंख फड़फड़ाने लगी है।
इतना सुंदर है नीला आसमान,
आज बन गई है आसमान की मेहमान।
पहले वह डर रही थी,
डर से घबराई थी,
फिर उसने हिम्मत दिखाई।
तितलियों और फूलों ने की उसकी विदाई।
अब आसमान में तितलियां उड़ने लगी हैं,
अपने पंख फड़फड़ाने लगी हैं।

आद्या श्रीवास्तव
- कक्षा : 5
- स्कूल : सेंट फ्रांसिस स्कूल, ग्रेटर नोएडा

बताओ तो जानें

1. हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया है?
A अमेरिका B जापान C यूएई D नेपाल
2. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं?
A राजनाथ सिंह B नितिन नवीन C जेपी नड्डा D नितिन गडकरी
3. बैडमिंटन की किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल में संन्यास लिया?
(A) साइना नेहवाल (B) ज्वाला गुट्टा (C) पीवी संधू (D) अश्वनी

इन प्रश्नों के उत्तर अमर उजाला के पिछले एक सप्ताह के अखबार में छपे हैं। आप अपने जवाब हमें 98368563 भेज सकते हैं। जवाब के साथ अपना नाम, स्कूल का नाम, पता, कक्षा और मोबाइल नंबर और फोटो जरूर भेजें। सबसे पहले सही जवाब देने वाले किन्हीं तीन विजेताओं की फोटो अगले अंक में प्रकाशित की जाएगी।

एक करोड़ रुपये की सिगरेट लूटने के मामले में 7 बदमाश गिरफ्तार

जेल में रची लूट की साजिश, भूदत्त कॉलोनी में दिया था वारदात को अंजाम

संवाद न्यूज एजेंसी

बल्लभगढ़। भूदत्त कॉलोनी में सिगरेट के वेयरहाउस से हुई एक करोड़ रुपये के सामान की लूट की साजिश करने वाले आरोपियों ने जेल में रहते ही लूट की साजिश रची थी। सभी आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे और सभी की मुलाकात जेल में हुई थी। वहां से बाहर आने के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था।

इस मामले में क्राइम ब्रांच ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस वारदात में शामिल एक आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। आरोपियों की पहचान दीपक निवासी चमन विहार गाजियाबाद, वीरेंद्र निवासी सोनिया विहार दिल्ली, मोहम्मद उमर निवासी संगम विहार दिल्ली, राहुल निवासी सोनिया विहार दिल्ली, विनय निवासी जैन नगर दिल्ली, मुकेश कुमार निवासी शिव विहार गाजियाबाद और बब्लू निवासी गजरौला जिला अमरोहा यूपी के रूप में हुई है।

मामले का खुलासा सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) क्राइम वरुण कुमार दहिया ने बताया कि 28-29 दिसंबर की रात आरोपियों ने बल्लभगढ़ की भूदत्त कॉलोनी स्थित सिगरेट के वेयरहाउस की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया। वेयरहाउस में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड सुनील को आरोपियों ने बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद गोदाम के अंदर बने कमरों के ताले तोड़कर करीब 60 हजार सिगरेट के डिब्बों से भरी पेटियां को लूट कर ले गए थे। उस माल की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही थी।

पहले से दर्ज हैं लूट के मामले : एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि आरोपियों के साथ वीरेंद्र नाम का एक अन्य साथी भी शामिल था, जो वाहन चलाने और माल को एक वाहन से दूसरे वाहन में लोड करने का काम करता था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ के खिलाफ पहले से ही चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। सभी आरोपी एक-दूसरे के जानकार हैं और कुछ की पहचान जेल में रहने के दौरान हुई थी, वहां से इस वारदात की साजिश रची गई।

पुलिस की गिरफ्त में लूट के आरोपी। स्रोत: पुलिस

जेल में मिले थे एक दूसरे से

एसीपी वरुण ने बताया कि इस गिरोह का मुख्य आरोपी उमर है जो दिल्ली का रहने वाला है। उसके साथ बबलू, राहुल, दीपक और राकेश ने मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। सभी आरोपी दिल्ली के निवासी हैं, जबकि चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी मुकेश गाजियाबाद के रहने वाले हैं।

7 दिन की रिमांड पर है आरोपी

अपराध शाखा सेक्टर 30 की टीम ने तकनीकी सहायता व गुप्त सूत्रों की सूचना के आधार पर घटनाक्रम में शामिल पांच आरोपियों को 17 जनवरी को गिरफ्तार किया सा। जिनको 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसके बाद 20 जनवरी को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिनको 21 जनवरी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अधिसूचना आज

बुलंदशहर। गंगा एक्सप्रेस-वे को जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ने वाला ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए प्रशासन बृहस्पतिवार को अधिसूचना जारी कर सकता है। जिले में 39 गांवों के करीब 8700 किसानों की 677 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।

ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे का निर्माण करीब 4500 करोड़ रुपये की लागत से होगा। यह एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर व बुलंदशहर की सीमा से होकर कुल 39 गांवों से होकर गुजरेगा। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, इसके लिए जिले के 8700 किसानों की 677 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहीत की जाएगी। भूमि अधिग्रहण पर लगभग 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन को 950 करोड़ रुपए की पहली किश्त मिल चुकी है। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर जनपद की तहसील स्याना, बुलंदशहर, अनूपशहर, शिकारपुर और सिकंदराबाद से होकर गुजरेगा।

एडीएम प्रशासन प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि किसानों को नियमानुसार भूमि का मुआवजा दिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आपत्तियों और सुझावों के निस्तारण के बाद अंतिम अधिग्रहण किया जाएगा। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस-वे के निर्माण से न केवल बुलंदशहर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। संवाद

जेईई मेन पेपर लीक के दावे गुमराह करने वाले : एनटीए

कहा- यह पूरी तरह से फर्जी, छात्रों को निजी जानकारी साझा न करने की दी गई है सलाह

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। जेईई मेन 2026 के जनवरी सत्र की परीक्षा के पहले दिन बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने फर्जी और गुमराह करने वाला बताया है। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी निजी जानकारी साझा न करें और भुगतान करने से भी बचें। साथ ही सही जानकारी के लिए केवल एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट को देखने की सलाह दी है। एनटीए ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि टेलीग्राम, व्हाटसएप या सोशल मीडिया पर अपलोड प्रश्नपत्र पूरी तरह फर्जी हैं।

दरअसल जेईई मेन की पहले दिन की परीक्षा शुरू होने से पहले ही टेलीग्राम और व्हाटसएप पर परीक्षा के आगामी प्रश्नपत्र अपलोड होने का दावा किया जाने लगा। प्रश्नपत्र प्राप्त करने के लिए छात्रों को पहले अपने नाम, नंबर, ईमेल के बाद भुगतान करने के लिए कहा गया। जैसे ही टेलीग्राम और व्हाटसएप पर प्रश्नपत्र उपलब्ध होने की सूचना फैली, छात्रों ने एनटीए हेल्पलाइन पर जानकारी मांगनी शुरू की।

हैदराबाद के एक केंद्र पर परीक्षा देने पहुंचे छात्र।

शुचिता को फेस ऑथेंटिकेशन
राष्ट्रीय परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और नकल कराने वाले गिरोह पर नकेल कसने के लिए एनटीए ने पहली बार परीक्षा से पहले आधार बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है। इस सत्यापन के बाद ही उम्मीदवार को कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के बीच में भी दोबारा सत्यापन किया जा रहा है।

रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर मनोज भावुक का गीत मेरे राम रिलीज

दिल्ली। रामलला प्रतिष्ठा दिवस की तीसरी वर्षगांठ पर भगवान राम को समर्पित एक भावपूर्ण हिंदी गीत 'मेरे राम' रिलीज किया गया है। यह गीत भले ही अयोध्या या मूर्ति स्थापना से सीधे तौर पर जुड़ा न हो, लेकिन इसमें उस राम की अनुभूति है, जो हर पल भक्तों के साथ रहते हैं और मन से पुकारने पर मार्गदर्शक बनते हैं। इसके गीतकार हिंदी-भोजपुरी के चर्चित कवि मनोज भावुक हैं। 'मेरे राम' भोजपुरी फिल्म 'मेहमान' का हिस्सा है और इसे एस आर के म्यूजिक चैनल पर जारी किया गया है। दिसंबर 2025 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के नायक अरविंद अकेला कल्लू हैं और यही गीत उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया है। खास बात यह है कि फिल्म के 9-10 गीतों में यह इकलौता हिंदी गीत है, जिसे राम की व्यापक स्वीकार्यता को ध्यान में रखकर हिंदी में रखा गया है। गीत के बोल जीवन की उलझनों, भटकाव और आस्था के सहारे को सरल शब्दों में सामने रखते हैं। गीत में राम को मन का संबल और हर अधूरेपन को पूरा करने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका संगीत भोजपुरी फिल्मों के जाने-माने लेखक-निर्देशक-संगीतकार रजनीश मिश्रा ने दिया है। मनोज और रजनीश मिश्रा की जोड़ी पहले भी कई यादगार गीत दे चुकी है। ब्यूरो

मनोज भावुक

मणिपुर : कांगला फोर्ट में 200वां विशाल राष्ट्रीय ध्वज लहराया

इंफाल/नई दिल्ली। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने मणिपुर के ऐतिहासिक कांगला फोर्ट में अपना 200वां विशाल राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के उस ऐतिहासिक फैसले के 22 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसने तिरंगा फहराने को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित किया था। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार देने के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

फाउंडेशन के अध्यक्ष नवीन जिंदल के एक दशक लंबे कानूनी संघर्ष के कारण ही आज हर भारतीय को साल के 365 दिन ससम्मान ध्वज फहराने का अधिकार प्राप्त है। नवीन जिंदल ने अपने संदेश में कहा कि तिरंगा केवल गर्व का विषय नहीं, बल्कि देश के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाने वाला प्रतीक है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ ही फाउंडेशन ने 23 जनवरी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करने का प्रस्ताव भी रखा है। अपनी अधिकार से जिम्मेदारी पहल के जरिये संस्था अब युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और पर्यावरण अनुकूल ध्वज प्रबंधन के प्रति शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ब्यूरो

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने किया स्थापित

उत्तर रेलवे का मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित

नई दिल्ली (वि)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन कर्मयोगी के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए ''''प्रशिक्षण से दक्षता की ओर'''' तीन दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (विचारों के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं और रैंकों में इंटरैक्टिव प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से अपनी तरह का पहला गहन क्षमता निर्माण कार्यक्रम) 15, 16 और 19 जनवरी को उत्तर रेलवे के लेखा विभाग द्वारा आयोजित किया गया। 20 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आयोजित समापन समारोह में रेलवे बोर्ड के लेखा विभाग के शीर्ष नेतृत्व और उत्तर रेलवे के शीर्ष प्रबंधन की उपस्थिति रही। कार्यक्रम माननीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के 52 सप्ताह में 52 सुधारों के विजन से प्रेरित था। कार्यक्रम में उत्तर रेलवे के प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर संजय उप्रेती, रेलवे बोर्ड की मेंबर फाइनेंस श्रीमती अपर्णा गर्ग, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एके वर्मा, रेलवे बोर्ड की एडिशनल मेंबर (बजट) मैडम मंजुषा जैन ने अपने विचार व्यक्त किए।

वफादारी को आखिरी विदाई... कुत्तों के लिए बना श्मशान घाट

फरीदाबाद में लावारिस कुत्तों के लिए देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था, नगर निगम करेगा संचालन

फरीदाबाद में बना श्मशान घाट।

फरीदाबाद। स्मार्ट सिटी में देश का पहला कुत्तों का श्मशान घाट तैयार किया गया है। यह शहर की स्वच्छता को मजबूती देने के साथ लावारिस और पालतू कुत्तों के प्रति मानवीय जिम्मेदारी का भी उदाहरण बनेगा।

बूढ़ेना गांव में यह श्मशान घाट तैयार हो चुका है। यहां उपलों से कुत्तों का अंतिम संस्कार होगा। यह श्मशान घाट पूर्व आईएएस और सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुनील गुलाटी के सहयोग से तैयार किया गया है। नगर निगम के साथ इसका संचालन किया जाएगा। सड़क किनारे, खाली प्लॉट या कूड़े के ढेर पर पड़े कुत्तों के शव दुर्गंध फैलाने के साथ बीमारी व संक्रमण का खतरा बढ़ाते थे। ऐसे में यह पहल शहर के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी नीतीश परवाल ने बताया, निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के निर्देश पर निगम तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने बताया, यह देश का पहला ऐसा श्मशान घाट होगा, जहां कुत्तों का अंतिम संस्कार उपलों से किया जाएगा। ब्यूरो

मोर्चरी वैन की सुविधा : इस श्मशान घाट की एक खास बात यह है कि कुत्तों के शव को लाने के लिए मोर्चरी वैन की भी व्यवस्था की गई है। अब किसी इलाके में कुत्ते की मौत होने पर लोग शव को इधर-उधर फेंकने को मजबूर नहीं होंगे। निगम की टीम सूचना मिलने पर शव को सुरक्षित तरीके से श्मशान घाट पहुंचाएगी।

अमृत उद्यान जनता के लिए 3 फरवरी से खुलेगा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च, 2026 तक आम जनता के लिए खुलेगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को घोषणा की कि लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भ्रमण कर सकते हैं। खरखाव के कारण सोमवार को और 4 मार्च को होली के अवसर पर अमृत उद्यान बंद रहेगा। ब्यूरो

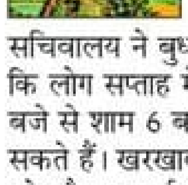

एजुकेशन & कॅरिअर

गलतियां रुकावट नहीं, सही रास्ता दिखाने वाले संकेत हैं।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड

जूनियर रेजिडेंट के पद खाली

1445 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 06 फरवरी, 2026
योग्यताएं : एमबीबीएस व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : bceceboard.bihar.gov.in

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली ■ 225 पद

बीमा चिकित्सा अधिकारी के पदों पर नौकरी के मौके
आवेदन की अंतिम तिथि
17 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
अधिकतम उम्र 35 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें
esic.gov.in

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ■ 90 पद

लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि
07 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम आयु 20 वर्ष व अधिकतम आयु 32 वर्ष
यहां आवेदन करें
sci.gov.in

हारट्रॉन में नौकरी के अवसर ■ 300 पद

मूल्यांकनकर्ता के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 05 फरवरी, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : hartron.org.in/

आरआईआईसीओ में निकली भर्ती ■ 98 पद

कंपनी सचिव, प्रोग्रामर, सहायक लेखा व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि
20 फरवरी, 2026
आयु-सीमा
न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष
यहां आवेदन करें
riico.rajasthan.gov.in

ईसीएचएस में रोजगार के मौके ■ 25 पद

मेडिकल स्पेशलिस्ट, डेंटल ऑफिसर आदि पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि
31 जनवरी, 2026
वेतनमान
रुपये 21,800 से लेकर रुपये 1,30,000 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें
echs.gov.in/

विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी...

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र : जूनियर रिसर्च फेलो का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 13 फरवरी, 2026
- nitkkr.ac.in
- ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी : प्रोजेक्ट साइंटिस्ट व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 04 फरवरी, 2026
- thsti.res.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

मदद मांगने में झिझक कैसी

सही समय पर सही व्यक्ति से मदद लेना आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, न कि आपको छोटा बनाता है

मेलोडी वाइल्डिंग
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

Harvard Business Review

कई बार जिंदगी में ऐसी मुश्किल या बिल्कुल नई परिस्थितियां आ जाती हैं, जहां हमें लगता है कि 'मैं यह सब अकेले ही संभाल लूंगा।' खासकर तब, जब कार्यस्थल पर कोई काम या प्रोजेक्ट हमारे लिए नया हो। लेकिन सच यह है कि हर काम अकेले करने की कोशिश करने से न सिर्फ तनाव बढ़ता है, बल्कि गलतियां होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। ऐसे समय में चुपचाप अकेले जूझने के बजाय सही व्यक्ति से मदद मांग लेना ज्यादा समझदारी भरा कदम होता है। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मविश्वास की निशानी है। जब आप स्पष्ट और सोच-समझकर अपनी जरूरत बताते हुए किसी से सहायता मांगते हैं, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है और काम आसान हो जाता है। याद रखें, सही समय पर सही व्यक्ति से मदद लेना आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, न कि आपको छोटा बनाता है।

■ सीधे मुद्दे की बात करें
किसी से मदद मांगते समय आपके बोलने का तरीका बहुत अहम होता है। सीधे और साफ बात करें, ऐसे नहीं कि आप एहसान मांग रहे हों। मदद मांगने के बजाय सलाह या जानकारी मांगें, जैसे-इस चुनौती पर आपके विचार जानना चाहता हूं। इससे सामने वाले को सम्मान महसूस होता है और बातचीत आसान हो जाती है।

■ कम काबिल दिखने से बचें
इस दौरान खुद को कमजोर या कम काबिल दिखाने की जरूरत नहीं होती। अपनी कमियों पर जोर देने के बजाय इस पर ध्यान दें कि सामने वाले का अनुभव आपके काम में कैसे मदद कर सकता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप इस काम में काफी माहिर हैं, आपके सुझाव से यह और बेहतर हो जाएगा। इस तरह आप खुद को भी आत्मविश्वासी दिखाते हैं और सामने वाले को सम्मान भी देते हैं।

■ आत्मविश्वास के साथ बोलें
मदद मांगते समय आपका बोलने का तरीका आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। इसलिए बातचीत की शुरुआत ऐसे करें कि सामने वाला समझे कि आप सोच-समझकर आए हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी समस्या को अच्छी तरह समझते हों और कुछ संभावित समाधान भी आपके पास हों। इससे पता चलता है कि आप पूरी तरह किसी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि बस सलाह या मार्गदर्शन चाहते हैं।

■ सलाह मांगें
किसी से सीधे मदद मांगने के बजाय उनसे सलाह लेने की कोशिश करना ज्यादा प्रभावी होता है। जब आप अपनी समस्या के बारे में बात करते हुए उनसे यह पूछते हैं कि वे ऐसी स्थिति में क्या तरीका अपनाते या कैसे समाधान निकालते, तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि आप केवल सहारे की तलाश में नहीं हैं, बल्कि सच में सीखना चाहते हैं। इससे बातचीत का स्तर भी बेहतर होता है और आप उनके अनुभव व समझ से कुछ नया सीख पाते हैं।

खुद को परखें

1. हाल ही में, गिलियन-बैरे सिंड्रोम को किस प्रकार के रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है?
   (a) स्वप्रतिरक्षित तंत्रिका संबंधी विकार
   (b) श्वसन रोग
   (c) हृदय रोग
   (d) संक्रामक जीवाणु रोग
2. किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में ब्रांट हेजहोग नामक हेजहोग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है?
   (a) उत्तराखंड
   (b) जम्मू और कश्मीर
   (c) हिमाचल प्रदेश
   (d) लक्षद्वीप
3. चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था?
   (a) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   (b) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
   (c) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   (d) वित्त मंत्रालय

उत्तर : 1.a, 2.b, 3.c

सामान्य ज्ञान

इंडियाफोन्टे बिजोयी

■ क्या है
यह समुद्र में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव है, जो कोपेपोडा वर्ग के लाओफोंटिडी परिवार से संबंधित है।

■ चर्चा में क्यों
हाल ही में, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में इस छोटे जलीय जीव (सूक्ष्म क्रस्टेशियन) की खोज की गई है।

■ विशेषताएं
इसका शरीर अर्ध-बेलनाकार और चपटा होता है, जो बीच में चौड़ा और पीछे की ओर पतला हो जाता है। आगे की ओर एंटीना जैसे छोटे उपांग होते हैं और मादा आकार में नर से थोड़ी बड़ी होती है। यह मीयोफौना का हिस्सा है, यानी एक मिलीमीटर से भी छोटे नन्हे अकशेरुकी जीवों में शामिल होता है। यह जलीय वातावरण में तलछट में रहता है।

■ लाओफोंटिडी परिवार
यह हार्पेक्टिकोइडा गण का सबसे विविध परिवार है, जिसमें 77 वंशों की लगभग 350 प्रजातियां शामिल हैं। ये सूक्ष्म जीव समुद्री और मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखते हैं और प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होने के कारण अच्छे जैव-सूचक माने जाते हैं।

आवेदन आमंत्रित

नेशनल आइडियाथॉन चैलेंज-2026

नेशनल आइडियाथॉन-2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर का इनोवेशन चैलेंज है, जो छात्रों, पेशेवरों और इनोवेटर्स को एक मंच पर लाकर वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए रचनात्मक समाधान तैयार करने का अवसर प्रदान करता है। इसका आयोजन कॉमसिया और डीओएससीआई द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है तथा इसे एआईसीटीई आइडिया लैब का समर्थन प्राप्त है। इस चैलेंज की थीम 'नवाचार करें, सहयोग करें, सृजन करें, भविष्य को आकार दें' रखी गई है। प्रतिभागी इसमें व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम तीन सदस्यों की टीम के रूप में भाग ले सकते हैं। यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित होगा, जिसमें प्रतिभागी ऑनलाइन या निर्धारित आयोजन स्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हिस्सा ले सकेंगे। चैलेंज के विजेताओं को क्रमशः 31,000 रुपये, 21,000 रुपये और 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रत्येक विजेता को एंड्रॉइड रिसर्च कोर्स की सदस्यता भी दी जाएगी। आवेदक अपनी अर्हता की जांच करते हुए आधिकारिक लिंक comsia.in/ideathon.html पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से 30 जनवरी, 2026 तक अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

स्पेशल पुस्तक
आईएएस 2025-26
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा

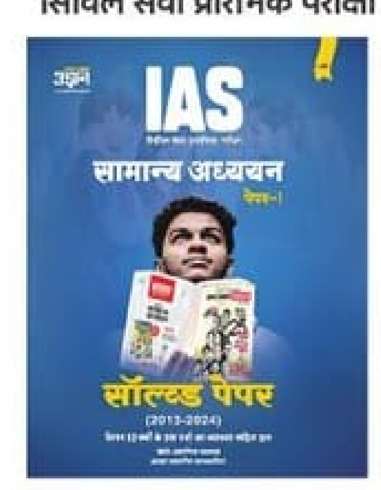

ऑनलाइन खरीदने के लिए QR कोड को तुरंत स्कैन करें।
05 किताबों का संग्रह
पूरी तरह एनसीईआरटी आधारित पुस्तकें
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001211166 या व्हाट्सएप नंबर 7065047252 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ मोटिवेशनल किताबें amazon.in और udaan.amarujala.com पर उपलब्ध।

एग्जाम अलर्ट – हफ्ते की परीक्षाएं

आईबी एमटीएस टीयर-1 परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 27 जनवरी, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य जागरूकता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, संख्यात्मक/विश्लेषणात्मक/तार्किक क्षमता और तर्कशक्ति और इंग्लिश लैंग्वेज से 100 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि एक घंटे निर्धारित की गई है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** mha.gov.in/

एनटीए कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट-2026

- **परीक्षा की तिथि :** 25 जनवरी, 2026
- इस परीक्षा में मात्रात्मक तकनीकें और डाटा व्याख्या, तार्किक तर्क, भाषा बोध, सामान्य ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता से 400 अंकों के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 180 मिनट की है।
- **यहां से परीक्षा केंद्र देख सकते हैं** cmat.nta.nic.in/

कल्पवृक्ष FAITH & WISDOM

वसंत के साथ अक्षर अभ्यास

वसंत पंचमी के दिन चंद्रमा ज्ञान के कारक गुरु की राशि में होने से गजकेसरी योग बन रहा है। यह तिथि छात्रों के लिए उत्तम संयोग बना रही है। यह पर्व वसंत के आगमन का संदेश देता है।

आशुतोष वार्ष्णेय
ज्योतिषाचार्य

मां सरस्वती की कृपा से जिनके पास ज्ञान होता है, वह परिस्थितियों से हारते नहीं हैं, उन्हें अवसरों में बदल लेते हैं। ज्ञान ही सही कर्म और सही दिशा का बोध कराता है, यही कारण है कि मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस, वसंत पंचमी को भारतीय परंपरा में ज्ञान का महापर्व माना गया है। माघ मास, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, वसंत पंचमी का पर्व इस बार 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को है। वसंत पंचमी पर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र तदोपरांत उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा। प्रातः 7 बजकर 41 मिनट से चंद्रमा का संचरण मीन राशि में होगा। पंचमी तिथि देर रात तक रहेगी, जिसके चलते स्नान, दान, पूजा-पाठ का क्रम पवित्र नदियों के तट पर सूर्योदय से देर रात तक रहेगा। दोपहर 11:30 से 12:30 तक पूजन का श्रेयस्कर मुहूर्त है।

ज्योतिष के मुहूर्त ग्रंथों के अनुसार, पंचमी तिथि पूर्ण फल देने वाली होती है, माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, यानी वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का आशीर्वाद सभी प्राणियों में ज्ञान का संचार करता है, इसलिए जनमानस संयुक्त रूप से सरस्वती वंदन, पूजन एवं स्नान, ध्यान और आराधना से सरस्वती कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन अग्रसर रहता है। वसंत पंचमी का दिन विद्यारंभ आदि कार्यों के लिए अतिशुभ माना गया है, लेखन, कला एवं साहित्य के लिए यह विशेष शुभ दिन है।

■ पूजन विधि : प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल में पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके मां सरस्वती का ध्यान करें। वसंत पंचमी को भगवान श्रीविष्णु एवं मां सरस्वती की पूजा पीले पुष्पों, गुलाल, अर्क, धूप, दीप, नैवेद्य आदि द्वारा करनी चाहिए, तदुपरांत पीले एवं मीठे चावलों तथा पीले हलुए आदि का भोग लगाकर प्रसाद वितरण के साथ स्वयं सेवन करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार, कहीं-कहीं श्रीकृष्ण एवं राधा का पूजन करने की भी परंपरा है।

■ दिव्य पर्व है वसंत पंचमी : प्रचलित मान्यताओं के अनुसार, वसंत पंचमी का महत्व पांच प्रमुख कारणों से सर्वोपरि है। सर्वप्रथम मां सरस्वती का जन्म इस दिन हुआ था और इसी दिन श्रीकृष्ण ने मां सरस्वती की पूजा सर्वप्रथम की थी। दूसरा, इस दिन शंकर जी की लगुन लिखी गई थी, तभी जाकर उनका विवाह महाशिवरात्रि पर संपन्न हुआ था। तीसरा, इस दिन को श्री पंचमी भी कहते हैं, इस दिन मां सरस्वती के साथ मां लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। चौथा, कामदेव एवं रती की पूजा कर मदनोत्सव मनाया जाता है। पांचवा, यह पर्व वसंत के आने की सूचना देता है।

■ बिना सरस्वती अधूरी है त्रिवेणी : प्रयागराज में गंगा और यमुना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती हैं, किंतु सरस्वती अदृश्य रूप में हैं। ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती के बिना त्रिवेणी पूर्ण नहीं होती, सरस्वती पूजा का खास दिन होने के कारण वसंत पंचमी के दिन श्रद्धालु सरस्वती पूजन के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान-दान करते हैं।

■ विशेष उपाय : वसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ कर पीले पुष्पों से शिवलिंग की पूजा करने से अल्पायु योग की समाप्ति होकर दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती के द्वादश नामावली का पाठ करने से मां भगवती प्रसन्न होकर ज्ञान वृद्धि के साथ सुख-समृद्धि प्रदान करती हैं। इस दिन कन्याओं को पीले चावल आदि का भोजन कराने व पीले वस्त्र दान करने का विधान है। इस दिन विद्यार्थियों को सरस्वती जी की पूजा कर सरस्वती यंत्र धारण करने पर मनोवांछित परिणाम प्राप्त होते हैं।

अचला सप्तमी 25 जनवरी — भगवान सूर्य के जन्मोत्सव का दिन

माघी सप्तमी को लोग अचला सप्तमी, रथ सप्तमी और आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। इस बार माघी सप्तमी का व्रत माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 25 जनवरी को रखा जाएगा। यह दिन भगवान सूर्य देव के जन्मोत्सव का दिन माना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व आक और बेर के पत्तों के साथ स्नान करने से मनचाही इच्छा पूरी होती है।

माघ महीने में शिशिर नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाती है, इसलिए माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का महत्व और बढ़ जाता है। इस पर्व पर घर, आंगन और दरवाजे पर साफ-सफाई रखनी चाहिए. माघी स्नान की बात करें तो माघ महीने की सप्तमी तिथि के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से आरोग्य, धन, ऐश्वर्य और सुख-संपदा की प्राप्ति होती है। माघी स्नान से लोगों को हर बीमारी से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि माघ सप्तमी में सूर्योदय से पहले स्नान करने से हर पाप से मुक्ति मिलती है। चूंकि यह दिन भगवान सूर्य के जन्मोत्सव का दिन है, इसलिए उनकी आराधना के साथ अर्घ्य देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। तांबे के पात्र में लाल पुष्प और गुड़ डालकर जल अर्पित करने से सूर्य देव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं। माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, तेज और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है।

सप्ताह का मंत्र

स्वाहादेवी वह्निपत्नी त्रिषु लोकेषु पूजिता।
यया विना हविर्दत्तं न ग्रहीतुं सुराः क्षमाः।।
दक्षिणा यज्ञपत्नी च दीक्षा सर्वत्र पूजिता।
यया विना च विश्वेषु सर्वं कर्म च निष्फलम्।।
स्वधा पितृणां पत्नी च मुनिभिर्मनुभिर्नरैः।
पूजिता पैतृकं दानं निष्फलं च यया विना ।।
स्वस्तिदेवी वायुपत्नी प्रतिविश्वेषु पूजिता।
आदानं च प्रदानं च निष्फलं च यया विना।।
पुष्टिर्गणपतेः पत्नी पूजिता जगतीतले।
यया विना परिक्षीणाः पुमांसो योषितोऽपि च।।
अनन्तपत्नी तुष्टिश्च पूजिता वन्दिता सदा।
यथा विना न संतुष्टाः सर्वलोकाच सर्वतः।।
ईशानपत्नी संपत्तिः पूजिता च सुरैर्नरैः।
सर्वे लोका दरिद्राश्च विश्वेषु च यया विना।।

स्रोत : ब्रह्मवैवर्त पुराण

पुरुष-प्रकृति श्रीविष्णु के ही रूप

संकेत : प्रस्तुत मंत्र ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड के प्रथम अध्याय से लिया गया है, जिसमें भगवान श्रीनारायण ने देवर्षि नारद को प्रकृति की कलाएं किन-किन देवों की पत्नी हैं, उनके विषय में बताया है।

मंत्रार्थ : भगवान श्रीनारायण कहते हैं, हे नारद! प्रकृति की कलास्वरूपा देवियों में 'स्वाहा देवी' अग्निपत्नी हैं। ये त्रैलोक्य पूजिता हैं। जब तक 'स्वाहा' नहीं कहा जाता तब तक प्रदत्त हवि देवगण ग्रहण नहीं कर पाते। 'दक्षिणा देवी' यज्ञपत्नी हैं। ये सर्वत्र पूज्या हैं। इनके बिना सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। 'स्वधा देवी' पितरों की पत्नी हैं। मुनि तथा मनुगण निरंतर उनकी पूजा करते हैं। इनके बिना प्रदत्त दान निष्फल होता है। 'स्वस्ति देवी' वायु की पत्नी हैं, ये अखिल विश्व में पूजिता हैं। इन देवी के बिना दान लेना-देना निष्फल हो जाता है। 'पुष्टि देवी' गणेश पत्नी हैं। इनके बिना स्त्री-पुत्रादि सभी अत्यंत क्षीण हो जाते हैं। सभी लोकों में अनंत पत्नी 'तुष्टि' पूज्या एवं वंदनीया हैं। इनके अभाव से सभी असंतुष्ट हो जाते हैं। 'संपत्ति देवी' ईशान देव की पत्नी हैं। इनके अभाव में लोग दरिद्रता रूपी महादुःख का भोग करते हैं।

तात्पर्य: सृष्टि कार्य में दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री ये पंच प्रकार की प्रकृति कही गई हैं। भगवान शिव कहते हैं, 'प्र' शब्द का अर्थ है, प्रथमा और 'कृति' का अर्थ है सृष्टि। अतएव जो सृष्टि की आदिभूता हैं, वे ही प्रकृति हैं। प्रधान पुरुष परमात्मा योग द्वारा स्वयं ही दो भाग में विभक्त हैं। उनका दाहिना भाग पुरुष तथा वाम भाग प्रकृतिरूप हो गया। वह प्रकृति ब्रह्मरूपा, मायामयी, नित्य तथा सनातनी है। अग्नि की दाहिका शक्ति जैसे अग्नि के साथ रहती है, उसी प्रकार जहां आत्मा है, वहीं पर प्रकृति भी विराजमान है।

-पं. जयगोविंद शास्त्री

आज का दिन

22 जनवरी, 1901

ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ था। उन्होंने 20 जून, 1837 को ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी के रुप में सिंहासन संभाला और अपनी मृत्यु तक, 63 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया।

- **1561 :** ब्रिटिश राजनेता और दार्शनिक फ्रांसिस बेकन का जन्म लंदन में हुआ था।
- **1963 :** देहरादून में दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी।
- **1976 :** कर्नाटक के गायक टीएम कृष्णा का जन्म हुआ था।
- **2018 :** अमेरिकी लेखिका उर्सुला के. ले गुइन का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी। **कल :** वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, शिशिर ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, दक्षिण गोले।
राहुकाल : प्रातः 10.30 से 12.00 तक।

■ सूर्योदय : 07.17
■ सूर्यास्त : 17.48
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 03 माघ मास शक 1947, माघ मास 10 प्रविष्टे, 03 सावान हिजरी 1447, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी 25.45 तक उपरांत षष्ठी, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र 14.32 तक उपरांत उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, परिध योग 15.58 तक उपरांत शिव योग, बव करण 14.06 तक उपरांत बालव करण, चंद्रमा मीन राशि में 08.31 बजे।

राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

मेष : समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। अटका कार्य बनेगा। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा। यात्रा से कार्य बन सकता है।

वृष : शुभ सूचना मिल सकती है। नौकरी में उन्नति हो सकती है। व्यवसाय में उतावलेपन से बचें।

मिथुन : दिनमान अनुकूल रहेगा। विरोधी पक्ष से सावधानी बरतें। अचानक अर्थ प्राप्ति हो सकती है।

कर्क : परिवार के किसी सदस्य की चिंता रहेगी। अचानक व्यय संभव है। व्यवसाय में लाभ होगा।

सिंह : सामाजिक प्रतिष्ठा बनी रहेगी। शत्रु शांत रहेंगे। नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा। न्याय क्षेत्र में विजय मिलेगी।

कन्या : नई योजना में व्यस्त रहेंगे। शुभचिंतकों का सहयोग मिल सकता है। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी।

तुला : अटके कार्य में सफलता मिलेगी। नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय में लाभ होगा।

वृश्चिक : पूर्व नियोजित कार्य में अवरोध आएंगे। स्वजन से मनमुटाव हो सकता है। नौकरी में मन नहीं लगेगा।

धनु : व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे। अटके कार्य में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सुखद रहेगी।

मकर : आजीविका प्राप्ति में सफलता मिलेगी। नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा। अर्थ प्राप्ति हो सकती है।

कुंभ : परिश्रम के चलते स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा। छोटी यात्रा संभव है।

मीन : स्वजनों से मनमुटाव संभव है। नौकरी में वाद-विवाद से बचें। व्यवसाय में आय-व्यय सम रहेंगे। चोट-चपेट से बचें।

जन्मदिन

भुवन बाम, अभिनेता

इस वर्ष प्रत्येक कार्य में पूर्ण सावधानी बरतें। बनते कार्य में निराशा होगी। विश्वासपात्र से धोखा हो सकता है। वर्ष मध्योपरांत समय अनुकूल रहेगा। विरोधी परास्त होंगे। न्याय क्षेत्र में विजय मिलेगी। स्वजन सहयोग मिलेगा। रोजगारपरक परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। परिवार में सौहार्द बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

सुडोकू

7						2	3	
9		1						7
			4					
		4		7		9	2	
		9	3		4	1		
	6	8		2		5		
					1			
6						7		5
	1	7						6

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

7	4	6	9	8	5	2	3	1
9	8	1	2	3	6	4	5	7
5	2	3	4	1	7	6	8	9
1	5	4	6	7	8	9	2	3
2	7	9	3	5	4	1	6	8
3	6	8	1	2	9	5	7	4
4	3	5	7	6	1	8	9	2
6	9	2	8	4	3	7	1	5
8	1	7	5	9	2	3	4	6

डेली हेल्थ कैप्सूल

सेहत की संजीवनी बैंगनी गांठ गोभी

बैंगनी गांठ गोभी में मौजूद तत्व शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके बीमारियों के जोखिम को कम करते हैं।

बैंगनी गांठ गोभी शरीर के लिए काफी गुणकारी मानी जाती है। इसमें सामान्य रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इस गोभी में फाइबर, विटामिन सी, के, पोटैशियम और एंटीऑक्सिडेंट होते हैं। इस गोभी में कैलोरी कम और फाइबर अधिक मात्रा में होता है, जिससे कम कैलोरी में भी आपको पेट भरा हुआ महसूस होता है। इससे धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज और सूजन जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो इम्युनिटी को मजबूत बनाता है। बैंगनी गांठ गोभी में पोटैशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह सूजन कम करने और शुगर लेवल नियंत्रित करने में भी फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट धमनियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस गोभी में विटामिन के, कैल्शियम, मैंगनीज और आयरन होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद एंथोसाइनिन त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस गोभी में मौजूद हाई फाइबर और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसे डायबिटीज के रोगियों के लिए भी उपयोगी बनाता है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

बैंगनी गांठ गोभी को कच्चा या अधिक खाने से पाचन की समस्या हो सकती है। इसमें मौजूद गोइट्रोजन्स थायराइड हार्मोन के कार्य को प्रभावित कर सकता है। इसे सीमित मात्रा में या चिकित्सक की सलाह से खाएं।

-प्रीता जैन, आहार विशेषज्ञ

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

नफरती बोल पर चोट

देश में कुछ नेता और संगठन ऐसे हैं, जो अक्सर नफरती बोल के सहारे अपनी सियासत को अंजाम देते रहते हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु के उप-मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी शामिल हैं, जिन्होंने सनातन पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने उदयनिधि की उस टिप्पणी को 'हेट स्पीच' या नफरती बोल माना है। नफरती बोल का यह मामला साल 2023 का है और इसका ऐसा संज्ञान पहले ही लिया जाना चाहिए था। विशेष रूप से राजनीति और सोशल मीडिया पर जब उदयनिधि के नफरती बोल की निंदा हुई, तब तमिलनाडु में भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने उसे अब रद्द कर दिया है। लगे हाथ, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि किसी नफरती भाषण पर प्रतिक्रिया देने वाले को दंडित करना अनुचित है, जबकि भाषण देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने माना है कि नफरती बोल की आलोचना के खिलाफ मामला दर्ज करना खराब मिसाल है।

वास्तव में, किसी भी नफरती बोल को देखने की दृष्टि समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी समुदाय की सहानुभूति के लिए किसी अन्य समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। किसी समुदाय के साथ सख्ती और किसी के साथ नरमी नाजायज ही कही जाएगी। अच्छा समाज तर्कपूर्ण भी होना चाहिए। दुर्भाग्य से, समाज में यह आम ध्वनि देखी जाती है कि सनातन या उसके तत्वों को बहुत आसानी से निशाना बना दिया जाता है। परिपक्व हो रहे गणतंत्र देश की स्वस्थ राजनीति के लिए जरूरी है कि किसी भी जाति-धर्म को निशाना न बनाया जाए। कहीं कमी है, तो मिल-जुलकर दूर की जाए। ध्यान रहे, निशाना न बनाने का संयम सबसे पहले नेताओं को बरतना होगा। कोई राजनीतिक दल हो या कोई नेता, नफरती बोल से तौबा करने में ही सबकी भलाई है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस श्रीमाथी की अवश्य प्रशंसा होनी चाहिए। स्वयं उप-मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ भी बोल देना और दूसरों को आलोचना से रोकना कानून-व्यवस्था का दुरुपयोग है। अदालत ने उचित ही इस चिंताजनक प्रवृत्ति पर गहरी निराशा व्यक्त की है। अदालत ने अफसोस भी जताया है कि मंत्री के भाषण के लिए उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। यहां यह गुहार या उम्मीद अदालतों से अवश्य होनी चाहिए कि नफरती बोल को इतनी आसानी से कतई बरी न किया जाए। ऐसे लोगों को यथोचित दंड देकर ही हम सभ्य समाज का बल बढ़ा सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि किसी नफरती भाषण पर प्रतिक्रिया देने वाले को दंडित करना अनुचित है, जबकि भाषण देने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

नफरती बोल के इस स्याह इतिहास को याद रखने की जरूरत है। साल 2023 में तमिलनाडु में दुखद ढंग से एक सनातन उन्मूलन सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना कुछ बीमारियों से की थी और इसे खत्म करने तक की बात कही थी। द्रविड़ राजनीति के अपने मुखर विचार रहे हैं, जिनको भारतीय समाज अच्छी तरह समझता है, पर आज के बदलते दौर में पेरियार के विचार वाली इकतरफा तल्खी से भारतीय समाज का कतई भला नहीं हो सकता। आज तमाम अल्पसंख्यक समूहों का संरक्षण जरूरी है, तो बहुसंख्यकों की भावनाओं का आदर भी, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नफरती बोल पर संविधान स्वयं लगाम लगाता है, मगर उसे लागू करने की सर्वाधिक जिम्मेदारी जिन नेताओं पर है, उन्हें कुछ बोलने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं?

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले | 22 जनवरी, 1951

ठक्कर बापा

ठक्कर बापा के निधन से दरिद्रनारायण का एक सच्चा उपासक हमारे बीच से उठ गया। सेवा का ढोल पीटने वाले तो इस जमाने में बहुत मिल जायेंगे, किन्तु वास्तविक अर्थों में सेवा की खातिर सेवा करने वाला ठक्कर बापा जैसा महापुरुष बिरला ही मिलेगा।

ठक्कर बापा निस्स्वार्थ और मूक सेवा की जीती-जागती मूर्ति थे। उन्होंने भारतीय मानवता के सबसे अधिक पीड़ित और अभावग्रस्त अंग को अपनी पूजा-अर्चना का लक्ष्य बनाया था। आदिवासी और हरिजन उनके प्रिय पात्र थे और समाज के इन दोनों उपेक्षित और पीड़ित वर्गों के लिए ठक्कर बापा की सेवायें बेजोड़ हैं। उन्होंने 45 वर्ष की अवस्था में अपना शेष जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित करने का निश्चय किया और तब से वह जीवन के अन्तिम दिनों तक अंगीकृत सेवा-कार्य में जुटे रहे। वृद्धावस्था में भी जिस निष्ठा और परिश्रम के साथ वह काम करते थे, उसे देखकर हैरानी होती थी। जहां कहीं पीड़ित मानवता की पुकार होती थी, वहीं ठक्कर बापा तत्काल पहुंच जाते थे। उड़ीसा में दुष्काल पड़ा, बिहार में भूकम्प आया; गुजरात में बाढ़ आई अथवा नोआखाली में साम्प्रदायिकता का ताण्डव हुआ, ठक्कर बापा सर्वत्र अपने हृदय की समस्त करुणा बटोरे घूमते नजर आते। उन्होंने जीवन में विश्राम की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं की। सवेरे से रात्रि को सोते समय तक उनके जीवन का प्रत्येक क्षण शुभ कर्म में व्यतीत होता था।

आदिवासियों और हरिजनों की स्थिति पर ठक्कर बापा का अध्ययन बहुत गहरा था। उन्होंने इस कार्य के निमित्त उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सारे देश का भ्रमण किया था। पहाड़ों और जंगलों की खाक छानी थी और ऐसे-ऐसे दुर्गम स्थानों की यात्रा की थी, जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। आदिवासियों और हरिजनों की भलाई के देश में अनेक स्थायी केन्द्र चल रहे हैं और उनमें शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसने ठक्कर बापा के हाथों पोषण और प्रेरणा न पाई हो। गुजरात के पंचमहाल जिले में भील-सेवा का जो आदर्श काम चल रहा है, उसकी नींव तो स्वयं ठक्कर बापा ने ही डाली थी। जब गांधीजी ने अस्पृश्यता निवारण के अखिल भारतीय आन्दोलन का सूत्रपात किया, तो ठक्कर बापा उसके मुख्य स्तम्भ बन गये।

छोटे शहरों की बड़ी समस्या बना प्रदूषण

सुनीता नारायण | पर्यावरणविद और महानिदेशक, सीएसई

यहां स्कैन करें

कई शहरों में लोगों को यह पता ही नहीं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर उन्हें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और स्थानीय प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए?

यह धारणा अब बदलनी चाहिए कि वायु प्रदूषण सिर्फ 'महानगरों और बड़े शहरों की समस्या' है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े तस्दीक करते हैं कि हमारे छोटे शहर भी अब दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। कुछ मामलों में तो स्थिति कहीं अधिक गंभीर है।

देशव्यापी प्रदूषण पर पिछले साल हमारी एक सहयोगी ने अध्ययन किया था, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। वह रिपोर्ट बताती है कि वायु प्रदूषण के नए हॉटस्पॉट बर्नीहाट जैसे छोटे शहर बनने लगे हैं। यह पूर्वोत्तर में असम-मेघालय सीमा पर स्थित है। पीएम 2.5 के सालाना स्तर के मामले में इसने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया था। इसी तरह, गुरुग्राम, श्रीगंगानगर, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर भी उन शहरों में शामिल दिखे, जहां वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के पार बना रहता है। यह भारत में वायु प्रदूषण में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जिसका अर्थ है कि छोटे शहरों में भी सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की दरकार है।

जाहिर है, हमें नियामक ढांचा मजबूत बनाना होगा, निगरानी व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी और रोकथाम के सख्त उपाय अपनाने होंगे। हालांकि, ये तमाम प्रयास तभी सफल होंगे, जब नागरिकों को पता होगा कि हमारी हवा कितनी खराब है? दिक्कत वास्तव में यही है। दरअसल, देश के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके यहां हवा कितनी दूषित है? अपने यहां वायु प्रदूषण से निपटने का सबसे आसान तरीका यही अपनाया जाता है कि लोगों को असलियत न बताओ। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उसे 'मॉनिटर' करने की पर्याप्त व्यवस्था देश के अधिकतर हिस्सों में नहीं है। नतीजतन, लोग न सिर्फ वायु प्रदूषण की जानकारी से अनभिज्ञ रह जाते हैं, बल्कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर उनको क्या-क्या करना चाहिए, ताकि सेहत को कम-से-कम नुकसान पहुंचे।

दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) का इस्तेमाल होता है। वहां इस आंकड़े का इस्तेमाल जानकारी देने और फिर कार्रवाई करने के लिए किया जाता है। लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और स्थानीय प्रशासन को प्रदूषण से लड़ने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इसीलिए, बीजिंग में 'रेड अलर्ट' के दिनों में स्कूल बंद हो जाते हैं, तो पेरिस 'स्मॉग' के दिनों में शहर में डीजल कारों को आने नहीं देता।

भारत ऐसा नहीं कर पाता। कुछ अपवादों को छोड़ दें, तो हमारे पास स्टेशनों का ऐसा नेटवर्क नहीं है, जो हमें रियल टाइम में खतरों के बारे में बता सके। हमारे पास 966 मैन्युअल स्टेशन हैं, जो सैंपल इकट्ठा करते हैं और उन्हें प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजते हैं। ये स्टेशन करीब 24 घंटे के बाद रोजाना का औसत आंकड़ा दे सकते हैं, वह भी तब, जब कोई व्यक्ति उस जानकारी को इकट्ठा करे, उसका विश्लेषण करे और लोगों से साझा करे। नियमित तौर पर ऐसा कर पाना कठिन होता है, इसलिए ज्यादातर आंकड़े पुराने मिलते हैं। अधिकतर मैन्युअल स्टेशन एक साल में 104 दिन निगरानी की न्यूनतम जरूरत भी पूरी करते नहीं दिखते।

तात्कालिक समय पर निगरानी करने वाले स्टेशनों की बात करें, तो देश के 296 शहरों में 567 रियल टाइम स्टेशन काम कर रहे हैं। यह स्थिति तब है, जब देश में 4,000 से अधिक शहर और नगर हैं। बेशक, 2010 की तुलना में मैन्युअल स्टेशनों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है और रियल टाइम स्टेशनों में भी 20 गुना की वृद्धि हुई है, लेकिन 40 फीसदी से अधिक आबादी अब भी वायु प्रदूषण की निगरानी व्यवस्था से बाहर है और करीब 60 फीसदी लोगों को अपने इलाके के वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी नहीं होती। ऐसे शहरों की संख्या तो 200 से भी कम है, जो सभी छह मुख्य प्रदूषकों की निगरानी करते हैं।

कोई चाहे, तो इन स्टेशनों (मैन्युअल और रियल टाइम, दोनों) की लागत को मुद्दा बना सकता है, जो गलत भी नहीं है। एक रियल टाइम स्टेशन बनाने में करीब एक करोड़ रुपये की जरूरत होती है, जिसके सालाना रखरखाव पर 18 से 20 लाख रुपये का खर्च आता है। इसी तरह, मैन्युअल स्टेशन बनाने में आठ से दस लाख रुपये की लागत आती है। ऐसे में, हमें हवा की निगरानी के लिए नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे नौजवान जब 'स्टार्ट अप' के मामले में दुनिया भर में अपनी योग्यता का लोहा मनवा सकते हैं, तो क्या उनकी मेधा का इस्तेमाल इस काम में नहीं किया जा सकता?

इसी तरह, निवारक उपायों को लेकर भी रणनीतियों में सुधार होना चाहिए। निर्माण-कार्य छोटे शहरों की मजबूरियां हैं, लेकिन पर्यावरण-हितैषी निर्माण-कार्यों को बढ़ावा देकर हम वहां की हवा को काफी हद तक बचा सकते हैं। अब ऐसी निर्माण-सामग्रियों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिनका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम-से-कम पड़े। नवीकरणीय सामग्रियों के उपयोग के साथ-साथ ऊर्जा-कुशल डिजाइन तैयार करने को लेकर भी लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि कार्बन फुटप्रिंट कम हों।

इसी तरह, गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर भी जागरूकता बननी चाहिए। किसी भी शहर का आंकड़ा ले लीजिए, गाड़ियों की संख्या में वृद्धि इंसानी आबादी में बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा दिखेगी। यह कोई इत्तफाक नहीं है। असल में, सार्वजनिक परिवहन की कमी के कारण लोगों के पास निजी गाड़ियों की तरफ जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। जैसे-जैसे सार्वजनिक परिवहन कम हुए हैं, लोग दोपहिया या कारों की तरफ बढ़े हैं। कई साल पहले मैंने पढ़ा था कि अमेरिका में किस तरह ऑटोमोबाइल उद्योग ने जान-बूझकर रेलवे और ट्रॉम-वे खरीद लिया था, ताकि वे उनको खत्म कर सकें। भारत में यह कहानी ज्यादा आसान रही। सार्वजनिक परिवहन को बर्बाद करने के लिए निजी कंपनियों को 'निवेश' नहीं करना पड़ा। यह काम सरकारों द्वारा खुद किया गया। ज्यादातर शहरों में, बसें ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरह नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली सेवा के रूप में चलती हैं। फिर, सरकारों ने सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी निवेश भी नहीं किया।

जाहिर है, छोटे शहरों पर अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुनिया की पांच बड़ी आर्थिक ताकतों में शुमार भारत इसे अब नजरंदाज नहीं कर सकता। वह भी तब, जब वायु प्रदूषण से देश में हर साल 15 से 17 लाख लोगों की जान जाती हो।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

भारत को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़े अमेरिका

सुरेंद्र कुमार | पूर्व राजदूत

यहां स्कैन करें

भारत में नवनियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर नई दिल्ली पहुंचने के बाद से ही कूटनीतिक तौर पर बेहद नरम और मैत्रीपूर्ण बयान दे रहे हैं। उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों, नेताओं, आरबीआई गवर्नर आदि से भी मुलाकात की है। यकीनन, यह स्वागत के योग्य बात है। जरूरत इस बात की है कि ट्रंप प्रशासन इसके अनुरूप व्यवहार करे। हो उल्टा रहा है। ट्रंप प्रशासन के कुछ सदस्य भारत व भारतीय नेताओं के बारे में अहंकारी, आक्रामक और कूटनीतिक रूप से अनुचित टिप्पणियां कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी निकटता और उनका विश्वासपात्र होने के कारण सर्जियो गोर संबंधों में आई शिथिलता को दूर कर सकते हैं।

गोर ने कहा है, 'भारत से अधिक जरूरी कोई और साझेदारी नहीं है' और भारत-अमेरिका संबंध 'इस सदी की सबसे फलदायक वैश्विक साझेदारी' है। यह राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, राष्ट्रपति ओबामा और राष्ट्रपति बाइडन के कार्यकाल में व्यक्त भावनाओं की याद दिलाती है। यदि यह सच है, तो भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगाया गया और ईरान के साथ व्यापार करने पर दंडात्मक 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी क्यों दी जा रही? ईरान पर प्रतिबंध से भारत को चाबहार बंदरगाह का संचालन बंद करना पड़ा है और अफगानिस्तान व मध्य एशियाई देशों तक भारत की पहुंच बाधित हो रही है। यदि साझेदारी को बढ़ाना और मजबूत ही करना है, तो कथनी-करनी में यह फर्क क्यों?

राष्ट्रपति ट्रंप का विश्वासपात्र होने के कारण अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर संबंधों में आई शिथिलता को दूर कर सकते हैं।

विगत 14 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को अपना परिचय-पत्र सौंपने के बाद सर्जियो गोर ने बयान दिया, 'मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती असली है। सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंततः वे अपने मतभेद सुलझा लेते हैं।' मित्रता को टिकाऊ बनाने के लिए पारस्परिक समायोजन, कुछ लेन-देन और एक-दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहना जरूरी शर्तें हैं। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है?

अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति ट्रंप ने पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की थी। इसके बाद से ट्रंप के व्यापार व विनिर्माण सलाहकार पीटर केंट नवारो और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक जैसे नेताओं ने भारत के खिलाफ उत्तेजक व नफरती टिप्पणियां शुरू कर दीं। इसके बावजूद भारत ने संयम का परिचय दिया। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कोई कठोर टिप्पणी नहीं की। भारतीय वार्ताकारों ने अमेरिकी समकक्षों के साथ छह दौर की वार्ताएं की हैं। इसमें काफी प्रगति हुई है, हालांकि हम अभी तक करार पर नहीं पहुंचे हैं। अमेरिका को याद रखना चाहिए कि 1971 में सातवें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने के बाद भी निक्सन-किसिंजर की जोड़ी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। मई, 1998 में भारत द्वारा परमाणु परीक्षण के बाद कड़े अमेरिकी प्रतिबंध भी भारत को नहीं झुका सके। टैरिफ का डंडा भी सफल नहीं होगा।

देखा गया है, जनवरी 2025 से अक्तूबर 2025 के बीच भारत में अमेरिका से तेल और गैस के आयात में भारी वृद्धि और रूस से आयात में भारी कमी हुई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इस बात की तस्दीक की है कि यूरोपीय संघ उनके देश से गैस का और अमेरिका यूरेनियम का आयात कर रहा है। इसलिए भारत पर 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क अत्यधिक अनुचित है। सर्जियो गोर का दायित्व है कि वह इसे हटवाने के लिए प्रयास करें। दोनों देशों में उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों में सहयोग सर्वाधिक जरूरी है, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय आतंक के जनक देश के जनरल का व्हाइट हाउस में स्वागत किया जाता है, तो अमेरिकी रणनीति पर संदेह लाजिमी है।

सबसे अधिक निराशाजनक रवैया अमेरिकी नेताओं द्वारा भारतीय नेतृत्व का जिक्र अपमानजनक तरीके से करना है। वाणिज्य मंत्री लुटनिक का यह कहना भारतीयों को रास नहीं आया कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए न हो सका, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया। एआई के युग में भी धैर्यपूर्ण, शांत कूटनीति का विकल्प नहीं है। सर्जियो गोर अगर इस असलियत को स्वीकार कर ट्रंप प्रशासन में सुधार करा सके, तो नई दिल्ली में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मन को कल्पवृक्ष बनाएं

आपका मन पांच अलग-अलग अवस्थाओं में हो सकता है। आपका मन निष्क्रिय हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि यह सक्रिय नहीं है। यह शुरुआती अवस्था में है। अगर आप इसे ऊर्जावान बनाते हैं, तब यह सक्रिय हो जाता है, पर बिखरा हुआ रहता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान बनाते हैं, तो यह बिखरा तो नहीं रहता, मगर आगे-पीछे होता रहता है। अगर आप इसे और ऊर्जावान बनाते हैं, तो यह एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। जब इसे और ऊर्जावान बनाते हैं, तो यह सचेतन हो जाएगा। अगर आपका दिमाग सचेतन है, तो यह जादू बन जाता है; तब यह परे जाने के लिए एक सेतु बन जाता है।

निष्क्रिय मन से समस्या नहीं होती। ऐसा इंसान जो सरल मन वाला है, जिसकी बुद्धि अभी उत्तेजित नहीं है, उसे समस्या नहीं होती। वह ठीक से खाता है और अच्छे से सोता है। सिर्फ वे लोग नहीं सो सकते, जो सोच सकते हैं! सरल दिमाग वाले लोग, तथाकथित बुद्धिजीवियों की तुलना में अपने शरीर के सारे क्रिया-कलाप काफी अच्छी तरह से करते हैं। उनके अंदर एक तरह की शांति होती है। एक निष्क्रिय मानव दिमाग इंसानी प्रकृति की तुलना में जानवर प्रकृति के ज्यादा करीब होता है।

कुछ लोग, जब आध्यात्मिक अभ्यास की शुरुआत करते हैं, तो उन्हें मानसिक प्रखरता के एक नए स्तर का अनुभव हो सकता है। अगर माहौल ठीक नहीं है, तो वे उसे संभाल नहीं पाते। उनके 'सिस्टम' में ऊर्जा के नए स्तर से पैदा हुई मन की प्रखरता को कुछ लोग व्याकुलता समझ सकते हैं। ऐसे लोग, जिनका मन बहुत बिखरा हुआ है, उन्हें आध्यात्मिक अभ्यास के बाद इसमें सुधार का अनुभव होता है। अब मन इधर-उधर होने लगता है- एक दिन इस तरफ, अगले दिन दूसरी तरफ। हालांकि, बिखरे होने की तुलना में यह काफी बड़ा सुधार है, क्योंकि पहले हर पल मन दस जगह पर भटकता था।

अगर मन पहले से ही इधर-उधर डोलने वाला है और आप इसे ज्यादा ऊर्जावान बनाते हैं, तो धीरे-धीरे यह एक बिंदु पर केंद्रित होने लगता है। यह और भी अच्छा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मन को सचेतन हो जाना चाहिए। यह आपका कंप्यूटर, कार या अंतरिक्ष यान नहीं, बल्कि मानव मन है, जो इस अस्तित्व की सबसे चमत्कारिक चीज है, बशर्ते आप सचेतन होकर इसका इस्तेमाल करें। ऐसा क्यों होता है कि किसी इंसान को सफलता बड़ी आसानी से और सहज मिल जाती है, जबकि दूसरे को संघर्ष करना पड़ता है? इसकी वजह यह है कि पहला इंसान जो चाहता है, वैसा ही सोचता है, जबकि दूसरा अपने ही खिलाफ सोचता है।

ऐसा क्यों होता है कि किसी इंसान को सफलता बड़ी आसानी से मिल जाती है, जबकि दूसरे को संघर्ष करना पड़ता है? इसकी वजह यह है कि पहला इंसान जो चाहता है, वैसा ही सोचता है।

एक सुस्थापित और सुव्यवस्थित मानव मन को कल्पवृक्ष कहते हैं, यानी एक ऐसा पेड़, जो मनचाहा वरदान देता है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति

भारत का भविष्य ऐसे युवाओं पर निर्भर है, जो वैज्ञानिक सोच रखें, जिम्मेदारी से कार्य करें और निःस्वार्थ भाव से सेवा करें। नौजवानो, आप जो भी कार्य चुनें, यह सुनिश्चित करें कि आपका योगदान राष्ट्र को सुदृढ़ बनाए और मानवीय मूल्यों को मजबूत करे।

अनुलोम-विलोम
रिक्त पद

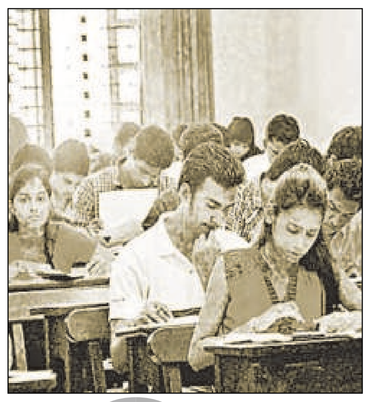

रिक्त पदों को जल्द भरने का उचित निर्देश

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने देश भर के शासकीय और निजी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को चार माह के भीतर भरने के कड़े निर्देश दिए हैं। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश निस्संदेह स्वागत-योग्य है। उसकी इस फटकार ने एक बार फिर शिक्षा के मामले में देश की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया है। समस्या केवल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूलों की हालत भी चिंताजनक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात आज भी अधिकांश स्कूलों में पूरा नहीं हो पा रहा। अनेक शिक्षण संस्थान या तो बहुत कम शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं या फिर अतिथि शिक्षकों के सहारे। ऐसा नहीं है कि सरकारें इनकी तरफ पूरी तरह से उदासीन हैं, पर जो भर्तियां की जाती हैं, वे जरूरत के अनुपात में अपर्याप्त रहती हैं।

सवाल है कि नया अदालती निर्देश क्या शिक्षण संस्थानों की तस्वीर बदल सकेगा? इसका जवाब दावे के साथ नहीं दिया जा सकता। असल में, अभी केंद्र अथवा राज्य सरकारों के बजट का एक हिस्सा मुफ्त योजनाओं पर खर्च हो रहा है, जिसका लाभ कई बार आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी उठाते रहते हैं। यदि मुफ्त योजनाओं का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक सीमित किया जाए और महंगाई के अनुरूप उनको सीधी आर्थिक सहायता दी जाए, तो उनकी वास्तविक सहायता संभव हो सकती है। इससे खजाने पर भार कम हो सकता है, जिससे शिक्षा मद का बजट बढ़ाया जा सकता है। रिक्त पदों को भरना सरकारों का दायित्व है, जबकि वित्तीय संकट का हवाला देकर वे इसमें अपनी असमर्थता जताती रहती हैं।

एक प्रसद्धि कहावत है कि यदि किसी राज्य का विकास कुछ वर्षों के लिए करना हो, तो अच्छी सड़कें बनाइए; यदि पचास-सौ वर्षों के लिए करना हो, तो अच्छे बांध और जल-स्रोत बनाइए; और यदि हजारों वर्षों तक विकास चाहते हों, तो राज्य अपनी शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनाएं। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था इतनी समृद्ध और वैभवशाली थी कि तक्षशिला, नालंदा, काशी और उज्जैन जैसे ज्ञान के केंद्रों ने विश्व को दिशा दी, लेकिन आज शिक्षा के मामले में हमारी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में, आवश्यकता है कि केंद्र व राज्य सरकारें अपनी गैर-जरूरी योजनाओं की समीक्षा करें और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएं। तभी भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा।

अरविंद रावल, टिप्पणीकार

शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने का हो प्रयास

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किसी एक आदेश या अस्थायी पहल से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यापक, दूरदर्शी और सतत सुधारों की आवश्यकता है। इसमें निश्चय ही सबसे पहला और अनिवार्य कदम है, शिक्षकों के रिक्त पदों को समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से भरना, क्योंकि शिक्षक ही ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार की रीढ़ होते हैं। इसको लेकर अदालत ने उचित निर्देश दिया है, जिसका हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, केवल भर्ती कर देना ही काफी नहीं होगा। शिक्षकों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है, उनकी गुणवत्ता बढ़ाना। लिहाजा, उनकी नियुक्ति में शोध-क्षमता और शिक्षण कौशल को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और अंतरराष्ट्रीय अकादमिक एक्सपोजर अनिवार्य बनाया जाए, ताकि वे बदलती वैश्विक जरूरतों और नई शिक्षण पद्धतियों से स्वयं को जोड़ सकें।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए शोध को केंद्र में रखना आवश्यक है, इसलिए विश्वविद्यालयों में पर्याप्त शोध अनुदान, आधुनिक प्रयोगशालाएं और उद्योगों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। पाठ्यक्रमों को समयानुकूल, कौशल-आधारित और रोजगारोन्मुखी बनाया जाना चाहिए, ताकि छात्र केवल डिग्रीधारी न रहकर सक्षम मानव संसाधन बन सकें। डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग भी गुणवत्ता सुधार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन संसाधन, वर्चुअल लैब और हाइब्रिड शिक्षण मॉडल को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इन सबके साथ आवश्यक यह भी है कि तकनीक का उपयोग केवल औपचारिकता न बने, बल्कि उससे सीखने की प्रक्रिया वास्तव में सशक्त हो। विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक कुलपति या अन्य प्रशासनिक पदों का रिक्त रहना संस्थानों की कार्य-संस्कृति को कमजोर करता है।

वास्तव में, अदालत के निर्देश को थोड़ी व्यापकता में देखने की जरूरत है। इससे देश में शिक्षा की संस्कृति में भी बड़ा बदलाव आएगा। इन तमाम कामों के अलावा मानसिक स्वास्थ्य, करियर मार्गदर्शन और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी संस्थानों में समर्पित केंद्र बनाए जाने चाहिए। हमें यह समझना ही होगा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तभी सुधर सकती है, जब सरकारें, विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षक व छात्र सभी मिलकर इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करें। क्या ऐसा हो सकेगा?

विभूति बुपक्या, टिप्पणीकार

रक्षा क्षेत्र में बढ़ती नौकरी की सुरक्षा

देश की सुरक्षा तकनीक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। वैश्विक और घरेलू रिपोर्ट्स इस ओर इशारा करती हैं कि डिफेंस सेक्टर तेजी से नई तकनीकों की ओर बढ़ रहा है, जहां इंजीनियरिंग, आईटी, साइबर सुरक्षा, एआई जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की मांग बढ़ेगी। यही बदलाव डिफेंस टेक्नोलॉजी को रोजगार के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है। उभरती संभावनाओं पर नजर डाल रही हैं तृप्ति मिश्रा

भारत में डिफेंस-टेक्नोलॉजी का क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 के 1.27 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2024–25 में बढ़कर लगभग 23,622 करोड़ रुपये पहुंच गया है। वहीं, ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं ने देश को रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत की ओर भी ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स की मानें, तो इस सेक्टर में अगले 5-7 वर्षों में बड़े पैमाने पर, टेक, साइबर सिक्योरिटी और एआई के जानकारों के लिए नए रोजगार अवसर पैदा होने वाले हैं।

डिफेंस टेक का क्षेत्र

आज हथियारों में सिर्फ मशीनें ही नहीं, स्मार्ट तकनीक भी शामिल है। देश में आर्म फैक्ट्रियां, टेक कंपनियां और रिसर्च लैब्स नई पीढ़ी के रक्षा उपकरण बना रही हैं। एआई-ड्रोन, स्मार्ट मिसाइलें, नाइट-विजन उपकरण, बुलेटप्रूफ जैकेट और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लगातार बेहतर हो रहे हैं। इनके लिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा और डिजाइन में दक्ष पेशेवरों की जरूरत बढ़ी है।

अभी कौशल की कमी

बीते साल दिसंबर में आई क्वेस कॉर्प हाइलाइट्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत में मौजूद आठ लाख एआई पेशेवरों में से पांच प्रतिशत से भी कम डिफेंस सेक्टर की वास्तविक जरूरतों के अनुसार पूरी तरह तैयार हैं। यानी ऐसे विशेषज्ञ जो ड्रोन सिस्टम, रडार और आरएफ टेक्नोलॉजी, क्वांटम कम्युनिकेशन, साइबर-डिफेंस, मिलिट्री-ग्रेड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जैसी वास्तविक रक्षा जरूरतों पर काम करने के लिए तैयार हों, उनकी संख्या बेहद कम है। रक्षा क्षेत्र लगातार नए और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है, इसमें ड्रोन के अतिरिक्त डिफेंस रोबोटिक्स, जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट और स्वतः चलने वाले नौसैनिक जहाज भी शामिल हैं। सेना के सुरक्षित संचार-संवाद के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी खूब काम हो रहा है।

करिअर का रोडमैप

डिफेंस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा, एआई, रोबोटिक्स, डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए अवसर बनते हैं। 12वीं में मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस या आईटी का चयन आगे की पढ़ाई की नींव रखता है। इसके बाद इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल या साइबर सिक्योरिटी जैसी डिग्रियां इस सेक्टर में प्रवेश का रास्ता खोलती हैं। डाटा, सॉफ्टवेयर और साइबर सुरक्षा में रुचि रखने वाले छात्र बीसीए, बीएससी आईटी या एआई/एमएल कोर्स के जरिए डिफेंस प्रोजेक्ट्स से जुड़ सकते हैं। डिजाइन, यूआई/यूएक्स, एनिमेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के विशेषज्ञ डिफेंस सिस्टम और ड्रोन इंटरफेस के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप क्रांति

सरकार की नीतियों और बढ़ती मांग ने घरेलू ड्रोन और रक्षा सामग्री संबंधी स्टार्टअप्स के लिए अवसर बढ़ा दिए, जिससे नए प्रोजेक्ट्स और नौकरियों की संख्या भी बढ़ी है। भारत में डिफेंस–टेक के 1,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स सक्रिय हैं, जो ड्रोन से लेकर अंडरवॉटर डिवाइसेस और एआई सेंसर सिस्टम तक विकसित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आइडियाफोर्ज उन्नत मानवरहित हवाई वाहन यानी ड्रोन बनाता है। इसी तरह न्यू स्पेस, टॉरस रोबोटिक्स, आईरोव, बिंग बैंग बूम सॉल्यूशंस और क्रॉनएआई जैसे स्टार्टअप्स समुद्र से लेकर डीपटेक और डाटा आधारित प्रणालियों, रोबोटिक्स सिस्टम पर काम कर रहे हैं। इस सेक्टर में 2025 में लगभग 564 करोड़ रुपये निवेश किया गया। जाहिर है कि रक्षा समाधान तकनीकों पर काम बढ़ेगा। इस तरह डिफेंस टेक सेक्टर करिअर व रोजगार का एक बड़ा केंद्र बन रहा है।

विशेषज्ञ की राय

आज डिफेंस टेक्नोलॉजी को केवल युद्ध या सीमा सुरक्षा तक नहीं देखा जा सकता। देश की सुरक्षा अब साइबर खतरों, डिजिटल नेटवर्क, ड्रोन निगरानी और आधुनिक संचार प्रणालियों तक फैली है। सीआरपीएफ और अन्य रक्षा बल आधुनिक तकनीक का सक्रिय उपयोग कर रहे हैं– सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और ड्रोन सर्विलांस जैसे क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है। मतलब कि डिफेंस टेक में करिअर के अवसर केवल वर्दी तक सीमित नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, आईटी, सॉफ्टवेयर, डाटा एनालिटिक्स और तकनीकी सपोर्ट तक उपलब्ध हो रहे हैं।

विजय कुमार, महानिरीक्षक (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी), सीआरपीएफ

प्रमुख संस्थान

- डीआईएटी, पुणे (डीआरडीओ के तहत, पीजी और पीएचडी स्पेशलाइजेशन); आईआईएईआईटी, पुणे (यूजी एवं पीजी कोर्स; आईआईटी, कानपुर; एआईडीएसएस, नोएडा
- बीटेक कोर्स के लिए स्पेस सीईटी, जेईई मेन/ एडवांस या संस्थान की प्रवेश परीक्षा। पीजी के लिए गेट स्कोर।
- डिफेंस रिसर्च साइंटिस्ट, एअरोस्पेस डिफेंस इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की ज्यादा मांग।

डीआरडीओ, इसरो, एचएएल और कई निजी कंपनियां इंटर्नशिप का मौका देती हैं।

अपस्किलिंग के लिए मंच : एनपीटीईएल, आईआईटी, एआईसीटीई, इसरो ई-लर्निंग, डीआरडीओ ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल इंडिया, कोर्सेरा, उडेमी और एडेक्स जैसे मंच ऐसे कोर्स उपलब्ध कराते हैं, जिनके जरिए छात्र साइबर सुरक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी एआई- एमएल, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम और उपग्रह संचार, थ्री-डी डिजाइन जैसे महत्वपूर्ण कौशल सीख सकते हैं।

रोजगार के दो प्रमुख रास्ते

डिफेंस टेक्नोलॉजी में करिअर बनाने के दो मुख्य रास्ते हैं: सरकारी और निजी क्षेत्र। सरकारी सेक्टर में डीआरडीओ, इसरो, एचएएल, बीईएल, बीडीएल, एनपीओएल, एआरडीई और सेना की तकनीकी शाखाओं में गेट परीक्षा, लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के जरिए भर्ती होती है। वहीं, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, एलएंडटी डिफेंस, भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस, डाटा पैटर्न और ड्रोन स्टार्टअप्स जैसे निजी संस्थान सीधे रोजगार के अवसर दे रहे हैं, जहां उम्मीदवार अपने कौशल के अनुसार रास्ता चुन सकते हैं।

अनुमानित वेतन : इस क्षेत्र में शुरुआती वेतन 4-8 लाख रुपये सालाना होता है, जो अनुभव के साथ 12–20 लाख तक पहुंच सकता है। डीआरडीओ, इसरो और पीएसयू में वरिष्ठ पदों पर 25-40 लाख, जबकि निजी डिफेंस कंपनियों और स्टार्टअप्स में इससे अधिक पैकेज भी संभव है।

जॉब/करिअर

- भारतीय रिजर्व बैंक में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर आवेदन करने का मौका है। अभ्यर्थी का संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश से दसवीं पास होना अनिवार्य होगा।

कुल पद : 572
अंतिम तिथि: 04 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। वेबसाइट है- **rbi.org.in**

- बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड, बिहार सरकार द्वारा जूनियर रेजिडेंट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।

कुल पद : 1445
अंतिम तिथि: 06 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है - **bceceboard.bihar.gov.in**

- नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में डेवलपमेंट असिस्टेंट की भर्तियां करेगा। आवेदन ऑनलाइन करें।

कुल पद : 162
अंतिम तिथि: 03 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : इस वेबसाइट **nabard.org** पर लॉगइन करें।

- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर एवं मार्केटिंग ऑफिसर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

कुल पद : 350
अंतिम तिथि: 03 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट **centralbank.bank.in** पर जाएं।

- उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद भरे जाएंगे।

कुल पद : 202
अंतिम तिथि: 02 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करें। वेबसाइट है- **upanganwadibharti.in**

- दिल्ली हेल्थ स्टेट मिशन ने एमबीबीएस अभ्यर्थियों से मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।

कुल पद : 200
अंतिम तिथि: 30 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट देखें - **dshm.delhi.gov.in**

- स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बॉक्सिंग, टेनिस सहित अन्य खेलों के लिए सहायक कोच की जरूरत है।

कुल पद : 323
अंतिम तिथि: 15 फरवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : देखें **sportsauthorityofindia.nic.in**

- रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत विभिन्न पद भरे जाएंगे।

कुल पद : 312
अंतिम तिथि: 29 जनवरी 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट है- **rrbchennai.gov.in**

(**नोट :** आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें।)

भेजें अपना सवाल

करिअर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें
nayiraheincareer@gmail.com

एक्सपर्ट टिप्स

आशीष आदर्श
करिअर काउंसलर

यूजीसी मानकों के मुताबिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी

■ क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की मान्यता है? क्या इसके आधार पर नौकरी मिल सकती है?

पूजा कुमारी

यदि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं, तो यह मान्य है, बशर्ते इसकी प्रक्रिया नियमानुसार हो। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए आवेदन देने से पहले आप निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लें :

1. उक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कई विदेशी प्राइवेट यूनिवर्सिटी पीएचडी कराने का दावा करती हैं, परन्तु उनकी मान्यता यूजीसी से नहीं होती।
2. उक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी में दाखिला यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार होना चाहिए। वर्तमान में पीएचडी में दाखिले के लिए यूजीसी-नेट का स्कोर जरूरी है।
3. दाखिले में यूजीसी के नियमानुसार प्रवेश जांच परीक्षा, साक्षात्कार जैसी जरूरी प्रक्रिया का अनुपालन किया गया हो।
4. रिसर्च रेगुलर मोड में किया गया हो, न कि कागजी तौर पर। ऐसी किसी भी जानकारी पर यूजीसी द्वारा उक्त पीएचडी रद्द की जा सकती है।
5. पीएचडी के लिए गाइड की योग्यता यूजीसी के अनुरूप होनी चाहिए।
6. पीएचडी के लिए तय समय सीमा में नियमानुसार थीसिस तैयार कर जमा किया गया गया हो।

यदि आप उपरोक्त नियमों को सुनिश्चित करते हुए अपनी पीएचडी पूरा करती हैं, तो नौकरियों में उक्त पीएचडी की पूरी मान्यता मिलेगी।

■ मैं हॉकी में अपना करिअर बनाना चाहती हूं। मेरा प्रदर्शन अच्छा है। राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आगे बढ़ सकती हूं, कृपया मार्गदर्शन करें।

राजेश्वरी

हॉकी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्कूल और फिर जिला स्तर पर खेलते हुए स्टेट लेवल पर चयनित हो जाने तक का सफर तय करना होगा। इसके बाद आप औपचारिक ट्रेनिंग प्राप्त करने की योजना बना सकती हैं। हॉकी में औपचारिक प्रशिक्षण के लिए जो संस्थान सराहनीय हैं, उनमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत नेशनल सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, नवल टाटा हॉकी अकादमी, श्री रामचंद्र सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंसेज इत्यादि प्रमुख हैं।

भारत सरकार के युवा खेल मंत्रालय द्वारा हॉकी सहित अनेक खेल में प्रशिक्षण के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। साथ ही, अच्छे प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को लगभग तमाम स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम सरकार की मुख्य योजनाओं में एक है।

क्विज-कोना

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं सुर्खियों में हैं। इन्हीं घटनाओं के आधार पर हम पाठकों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो करंट अफेयर्स की समझ बढ़ाने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए भी उपयोगी हैं। पेश हैं दस सवाल और उनके जवाब

1: 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस का मुख्य विषय या थीम क्या रखा गया है?
2: 2026 में भारत के 77वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का नाम बताएं?
3: हाल ही में मिजोरम को आधिकारिक रूप से किस पदार्थ की राजधानी घोषित किया गया है?
4: मैन पोर्टेबल एंटी–टैंक गाइडेड मिसाइल (एमपीएटीजीएम) का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कब और कहां किया?
5: 2026 में जिस क्रिकेट विश्व कप का आयोजन फरवरी से शुरू होना है, वह किस फॉर्मेट से जुड़ा है?
6: हाल ही में किस देश ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जताकर वैश्विक बहस छेड़ दी है?
7: ईरान में किसके नेतृत्व के खिलाफ लोकतंत्र समर्थक आंदोलन जारी है?
8: आस्था और पवित्र स्नान के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज में हाल ही में कौन सा आध्यात्मिक मेला आयोजित हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए?
9 : रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना अभिनीत वह कौन–सी स्पाई–थ्रिलर फिल्म है, जिसने बॉक्स–ऑफिस पर जोरदार प्रदर्शन किया है?
10 : हाल ही में हुए महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में कौन सा राजनीतिक दल सबसे आगे रहा?

उत्तर : 1 : वंदे मातरम के 150 वर्ष; 2 : उर्सुला वॉन डेर लेयेन; 3 : भारत की अदरक राजधानी; 4 : 11 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के केके रेंज में; 5 : टी20; 6 : यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका; 7 : आयातुल्लाह अली खामेनेई; 8 : माघ मेला 2026; 9 : धुरंधर; 10 : भारतीय जनता पार्टी

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कार आदि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा। बौद्धिक कार्यों में सम्मान प्राप्त होगा।

वृष : पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। मित्र का सहयोग मिल सकता है। कारोबार विस्तार के लिए पिता से धन मिल सकता है।

मिथुन : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। पिता का सान्निध्य मिलेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा।

कर्क : मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा।

सिंह : मन प्रसन्न रहेगा, किंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार से दूर रहना पड़ सकता है।

कन्या : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान भी हो सकता है। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है।

तुला : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर मिल सकते हैं, परंतु किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है।

वृश्चिक : मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। संतान की सेहत का ध्यान रखें।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पठन-पाठन में रुचि रहेगी। लेखन आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आय के साधन बन सकते हैं। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

मकर : मन परेशान रहेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु कार्य-क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। कठिनाइयां आ सकती हैं। परिश्रम भी अधिक रहेगा।

कुंभ : मन प्रसन्न रहेगा। बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि हो सकती है। शैक्षिक कार्यों के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु कारोबार में बदलाव हो सकता है। परिवार और मित्रों से आर्थिक सहयोग प्राप्त हो सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

22 जनवरी, गुरुवार, **शक संवत्:** 02, माघ, (सौर) शक 1947, **पंजाब पंचांग:** 09, माघ मास प्रविष्टे 2082 **इस्लाम:** 02, शब्बान, 1447, **विक्रमी संवत्:** माघ शुक्ल चतुर्थी तिथि रात्रि 02.29 मिनट तक पश्चात पंचमी तिथि, शतभिषा नक्षत्र दोपहर 02.27 मिनट तक पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में (दिन रात)।

सूर्य उत्तरायण। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा दोपहर 02.39 मिनट से रात्रि 02.29 मिनट तक। वरद्–तिल–कुन्द चतुर्थी। पंचक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमारी दुकान में हमेशा खर्चों की समस्या बनी रहती है। जितना पैसा आता है, उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। कृपया कोई उपाय बताएं। – अंकित सम्राट, सोनीपत

- आपकी दुकान उत्तरमुखी है। प्रवेश द्वार भी शुभ पद में है, इस कारण आपके पास धन आ रहा है, किंतु आपने दक्षिण दिशा में फर्श नीचा करवाकर एक लिंटर डलवा दिया है।
- इसके कारण दक्षिण दिशा नीची हो गई है। इस वजह से पैसा आता है, पर उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। इसका श्रेष्ठ उपाय तो यही है कि फर्श इस प्रकार बनाएं कि फर्श एक ही लेवल पर हो। फर्श का ढाल भी उत्तर दिशा की ओर हो।
- दुकान की दक्षिण पश्चिम दिशा में पीतल की एक कटोरी में पीली सरसों भर कर रखें।

वर्ग पहेली : 8217

■	1	■	2	3		4		5
6			■		■		■	
■		■	7		8			
9		■		■		■	■	
	■	10					■	
	■	■		■		■	11	
12		13		14		■		■
	■		■		■	15		
16						■		■

बाएं से दाएं
2. एकता के साथ; एक स्वर में; मिलकर (6)
6. कोना; छोर; सिरा; कूल; तीर; तट (3)
7. चिंतन करना; विचार करना; अध्ययन करना (3,3)
9. मजा; स्वाद; अमृत; सुधा; निचोड़; निर्यास; द्रव; यूष; शोरबा (2)
10. आक्षेप लगाना; व्यंग्य करना (2,3)
11. आगमन; पधारना; पहुंचना; प्रवेश करना (2)
12. विवाद खड़ा करना; लड़ाई करना (3,3)
15. भार रखना; जोर देना; पीछे हटाना; गाड़ना; छिपाना (3)
16. नामकृत करना; नाम लिखना; मनोनीत करना (3,3)

ऊपर से नीचे
1. एकाएक; बिना प्रयास के; बैठे बिठाए (4)
3. कड़ा; कठोर; दृढ़; सख्त; दुष्कर; मुश्किल (3)
4. पूरा करने वाला; पूर्तिकर्ता (3)
5. अटकल लगाना; अनुमान करना; खयाली उड़ान भरना; सोचना (3,3)
7. प्रधान नेता; सबसे बड़ा नायक; सम्राट; पोताध्यक्ष; महा सेनापति (5)
8. कोलाहलपूर्ण स्थान; नक्कारा बजाने की जगह; नौबतखाना (5)
9. गरदन पर धौल जमाना; थप्पड़ लगाना; चांटा जड़ना; मुक्का मारना (3,3)
11. ठाट बाट; वैभव; शान; सजधज (2,2)
13. हरा; हरे रंग का; शाक-भाजी (3)
14. गति; चाल; प्रवाह; चलने का ढंग (3)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8216

1 नो	2 क	दा	र	■	3 का	4 म	या	5 ब
■	रा	■	■	6 वि	■	ध्य	■	र
7 गि	रा	8 ना	■	त	■	9 म	ल	बा
र	■	10 ह	स	र	त	■	■	द
फ्ता	■	क	■	ण	■	11 मी	■	क
र	■	■	12 च	क	रा	ना	■	र
13 क	मा	14 ना	■	र	■	15 र	16 ह	ना
र	■	दा	■	ना	■	■	वा	■
17 ना	गा	न	न	■	18 ह	वा	ला	त

सुडोकू : 8199

*कठिन

	3				6		1	
6		8						
	9		4	2				
		3		9		7		
5			2		7			8
		1		6		9		
				8	5		6	
						1		5
	5		1				7	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8198

1	8	3	5	9	6	4	2	7
5	6	4	2	1	7	3	8	9
7	2	9	8	4	3	1	6	5
9	7	1	6	8	4	5	3	2
6	3	2	9	5	1	7	4	8
8	4	5	3	7	2	9	1	6
4	1	8	7	2	5	6	9	3
2	5	6	4	3	9	8	7	1
3	9	7	1	6	8	2	5	4

किफायती आवास सीमा 90 लाख रुपये तक होने की संभावना

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। उम्मीद है इस बार वित्तमंत्री आर्थिक विकास को गति देने वाले बजट पेश करेंगी, जिसमें विनिर्माण और आवास क्षेत्र को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। खासकर सरकार किफायती मकान एवं फ्लैट की कीमतों संबंधी बदलाव को लेकर ऐलान कर सकती है। लंबे समय से मांग की जा रही है कि सरकार किफायती आवास से संबंधी मूल्य सीमा को बढ़ाए।

वर्तमान मूल्य सीमा काफी कम: मौजूदा समय में देश में 45 लाख रुपये तक की कीमत के फ्लैट एवं आवास किफायती मकानों की श्रेणी में आते हैं। नियमों के तहत मेट्रो शहरों (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहर) में 60 वर्ग मीटर (करीब 645 वर्ग फुट) और गैर-मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर (करीब 968 वर्ग फुट) तक के घरों को किफायती आवास की श्रेणी में रखा गया है लेकिन बढ़ती लागत के कारण निर्माता और खरीदार किफायती आवास की सीमा को बढ़ाकर 70-90 लाख तक करने की मांग कर रहे हैं, जिससे किफायती आवास खरीदने पर कर छूट संबंधी लाभ दिया जा सके।

लागत बढ़ने से सीमा बढ़ाना जरूरी: रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया था। उनका कहना था कि सरकार ने वर्ष 2017 में किफायती आवास की अधिकतम 45 लाख की कीमत तय की थी। अब रियल एस्टेट क्षेत्र का कहना है कि देश भर में निर्माण लागत बढ़ रही है इसलिए सीमा को बढ़ाना जरूरी है।

बड़े शहरों में मकानों और फ्लैट की कीमत आसमान पर पहुंची

मेट्रो शहरों में अधिकांश मकान-फ्लैट की कीमत 70 लाख के पास चली गई है। दो कमरों का फ्लैट भी अब 70 लाख से कम पर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में पहली बार घर खरीद रहे खरीदार किफायती मकान खरीदने के दायरे बाहर हो जाते हैं। ऐसे में खरीदारों को सब्सिडी योजना का लाभ नहीं मिलता है। बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार को किफायती आवास की कीमत सीमा को बढ़ाकर 70-90 लाख कर देती है तो इससे पहली बार घर खरीद रहे काफी लोगों को सब्सिडी योजना का लाभ मिल सकेगा।

45 लाख रुपये ही वर्तमान में किफायती आवास योजना के तहत सब्सिडी पात्रता सीमा

70 लाख से कम पर उपलब्ध नहीं हो रहे दो कमरों के फ्लैट इस वक्त बड़े शहरों में

मौजूदा प्रावधान

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 45 लाख तक के आवास पर सीधे सब्सिडी नहीं, बल्कि होम लोन पर ब्याज सब्सिडी (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना) मिलती है, जिसमें एमआईजी के लिए 2.67 लाख तक की सब्सिडी 25 लाख के लोन पर 120 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक घर खरीदने के लिए मिलती है। यह सब्सिडी 1.8 लाख तक की ब्याज बचत के बराबर है। इसमें परिवार की वार्षिक आय 9 लाख तक होनी चाहिए और कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।

अन्य अहम मांगें

- सेक्शन 80 को फिर से लागू करना, जिससे निर्माता को 100 फीसदी कर छूट मिले।
- होम लोन के ब्याज पर दो लाख की वर्तमान कटौती पुरानी कर व्यवस्था के तहत (धारा 24 (बी) को बढ़ाकर 4-5 लाख किया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को मजबूत किया जाए।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स		निफ्टी	
81,909	-270.84	25,157	-75.00

अनाज एटीएम खोलने की तैयारी

जयपुर। राजस्थान के जयपुर, भरतपुर एवं बीकानेर जिलों में अनाज एटीएम खुलने जा रहा है जहां से खाद्य सुरक्षा लाभार्थी राशन कार्ड से राशन प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ ऐसे मजदूर परिवारों को होगा जो सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं और देर रात तक घर लौटते हैं। ये अनाज एटीएम घनी बस्तियों में संचालित किए जाएंगे।

मौजूदा स्थिति जगा रही भविष्य के लिए उम्मीद

मुंबई। भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति भविष्य के लिए खुशनुमा उम्मीद जगाती है और अनिश्चितताओं के बावजूद देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आरबीआई के बुलेटिन में कहा गया है कि वर्ष 2026 की शुरुआत वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों से हुई। इन घटनाओं से अस्थिरता बढ़ी, लेकिन भारत की मौजूदा स्थिति आगे के लिए उम्मीद जगाती है।

दीपिंदर गोयल सीईओ और एमडी का पद छोड़ेंगे

नई दिल्ली। जोमैटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली इटर्नल ने कहा कि दीपिंदर गोयल समूह के सीईओ और प्रबंध निदेशक का पद छोड़ेंगे। उनकी जगह ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा एक फरवरी से समूह के नए सीईओ के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में गोयल ने कहा कि वह नए विचारों पर काम करने के लिए अपने वर्तमान पद से हट रहे हैं।

हरित बदलाव के लिए एजेंसी के गठन की सिफारिश

नई दिल्ली। नीति आयोग ने कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की दिशा में एमएसएमई के हरित ऊर्जा की ओर बदलाव को लागू करने के लिए बुधवार को एजेंसी के गठन की सिफारिश की। एमएसएमई क्षेत्र में करीब 6.9 करोड़ इकाइयां हैं, जिनमें से लगभग 6.86 करोड़ सूक्ष्म उद्यम हैं। कुल निर्यात में इनका योगदान 45.7% है और यह क्षेत्र करीब 25 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

ग्रीनलैंड मुद्दे को लेकर ट्रंप के यूरोप के साथ बढ़ते तनाव के कारण निवेशक हुए सतर्क

रुपया 68 पैसे की गिरावट के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा

झटका

मुंबई, एजेंसी। रुपया बुधवार को 68 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 91.65 (अस्थायी) पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता एवं जोखिम से बचने की धारणा के बीच विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से घरेलू मुद्रा पर दबाव रहा।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये 16 दिसंबर 2025 को 91.14 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था। इस महीने अब तक स्थानीय मुद्रा में 1.50 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस गिरावट का कारण भू-राजनीतिक अनिश्चितता में वृद्धि है।

उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड मुद्दे और संभावित शुल्क को लेकर यूरोप के साथ बढ़ते तनाव के कारण निवेशकों ने सतर्कता का रुख अपनाया है। इसके अलावा, घरेलू शेयर बाजार में नकारात्मक रुझान ने भी निवेशकों की धारणा को कमजोर किया। इससे रुपये पर दबाव देखा गया।

1.50 प्रतिशत की गिरावट आई एक महीने में

91.14 प्रति डॉलर था पिछला निम्न बंद स्तर

अलग-अलग वर्गों पर इस गिरावट का असर

आम आदमी
- **महंगाई बढ़ने का खतरा:** पेट्रोल-डीजल, गैस, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों जैसी आयातित वस्तुएं महंगी हो सकती हैं।
- घर का बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां बढ़ी लागत उपभोक्ताओं से वसूलेंगी।
- एफडी/बचत पर फायदा नहीं, उल्टा खर्च बढ़ सकता है।

निवेशक
- शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ता है।
- आयात-आधारित कंपनियों पर दबाव।
- निर्यातक कंपनियों के शेयरों में तेजी।
- विदेशी निवेशक मुनाफा निकाल सकते हैं, जिससे बाजार पर दबाव।

कारोबारी
आयात पर निर्भर कारोबारी संकट झेलेंगे। कच्चा माल और मशीनरी महंगी पड़ेगी। मुनाफा घट सकता है या कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी।

निर्यातक
फायदा: डॉलर में मिलने वाली कमाई रुपये में ज्यादा होगी। आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर लाभ में।

आयातक
कच्चा तेल, सोना, गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स आयात महंगा। मार्जिन घटता है या कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। छोटे आयातकों पर सबसे ज्यादा दबाव।

अर्थव्यवस्था
तेल और उर्वरक सब्सिडी का बोझ बढ़ता है। देश का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। महंगाई नियंत्रण सरकार के लिए चुनौती बनेगी।

पर्यटक
- विदेश जाने वालों पर असर।
- होटल, खाना, ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग सब महंगा होगा।
- यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर की यात्रा पर खर्च काफी बढ़ेगा।

विदेशी पर्यटक
भारत सस्ता लगेगा, देश में पर्यटन करने पर फायदा होगा।

विदेश यात्रा
- हवाई टिकट, वीजा फीस, ट्रैवल इंश्योरेंस महंगे।
- अंतरराष्ट्रीय कार्ड और फॉरेक्स खर्च बढ़ेगा।

विदेश में पढ़ाई
- ट्यूशन फीस, हॉस्टल, रहन-सहन महंगा।
- अभिभावकों को ज्यादा रुपये भेजने पड़ेंगे।
- एजुकेशन लोन का बोझ बढ़ेगा।

विदेश में इलाज
- इलाज, अस्पताल खर्च, दवाइयां सब ज्यादा महंगे होंगे।
- अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में इलाज और मुश्किल होगा।

पेंशनधारकों का 'संपन्न' पोर्टल डिजीलॉकर से जुड़ा

सुविधा

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने बुधवार को बताया कि 'संपन्न' पेंशन पोर्टल को अब डिजीलॉकर से जोड़ दिया गया है। इससे पेंशनरों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ग्रेच्युटी भुगतान आदेश और अन्य जरूरी दस्तावेज कभी भी और कहीं से ऑनलाइन मिल सकेंगे।

यह 'संपन्न' पेंशन पोर्टल कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है। दूरसंचार विभाग के सभी पेंशनरों को इस सफल इंटीग्रेशन की जानकारी दे दी गई है।

इस तरह करें इस खास सेवा का इस्तेमाल

पेंशनर इस सेवा को इस्तेमाल करने के लिए डिजीलॉकर.गव.इन पर आधार के जरिए लॉगिन कर सकते हैं, अपना पीपीओ नंबर लिंक कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। 'संपन्न' के यूजर्स हर सर्विस कैटेगरी में अपना पीपीओ नंबर डालकर 'गेट डॉक्यूमेंट' पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद सिस्टम अपने आप यूजर्स की मांग के अनुरूप पेंशन सर्टिफिकेट, ग्रेच्युटी भुगतान आदेश, कम्यूटेशन पेमेंट ऑर्डर या फॉर्म-16 तैयार कर देगा।

श्रमिकों की खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि

नईदिल्ली, एजेंसी। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मजबूती के कारण दिसंबर महीने में खेतिहर और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति में क्रमशः 0.04 प्रतिशत और 0.11 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा

मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार) पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर भारत संघ के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निर्धारित ई-निविदा आमंत्रित करते है। (1) **निविदा सूचना क्रमांक:** जबल-एन-सिग-टेंडर-2026-5 **कार्य का नाम लोकेशन सहित:** पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के घाटपिंदराई स्टेशन पर गुड्स शेड की व्यवस्था के संबंध में एस एंड टी कार्य (सिग्नलिंग कार्य)। **निविदा का अनुमानित मूल्य:** ₹11230966.42 **निविदा फॉर्म की कीमत:** ₹ 00/- **कार्यालय का पता:** मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार) कार्यालय, प्रथम तल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जबलपुर **बयाना राशि:** ₹ 206200/- **समापन अवधि (माह):** 11 माह **निविदा बंद होने एवं खुलने की अंतिम तिथि एवं समय:** दिनांक 13.02.2026 को 15.00 बजे तक बंद होगी एवं 15.00 बजे के बाद खोली जाएगी। निविदा सूचना की पूर्ण जानकारी रेलवे वेबसाइट "https://ireps.gov.in" पर उपलब्ध है तथा मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार) कार्यालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है। उक्त निविदा उक्त वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन की जा सकती है।

(हस्ता.)
मण्डल रेल प्रबन्धक (संकेत एवं दूरसंचार)
प.म.रे., जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्टारलिंक पर सरकार फैसला लेगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्टारलिंक की शुरुआत सुरक्षा जरूरतों का पालन करने और स्पेक्ट्रम की कीमत और आवंटन पर सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

पिछले महीने कंपनी के अधिकारियों के साथ अपनी बैठक के बाद भारत में स्टारलिंक के संचालन की समय-सीमा के बारे में सिंधिया ने कहा कि इस प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण कारक शामिल हैं। इस दिशा में पहला कारक है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में उनका अनुपालन। भारत सरकार ने उन्हें उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने के लिए अस्थायी स्पेक्ट्रम दिया है। वे वर्तमान में उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, हमारे लिए उन्हें स्पेक्ट्रम प्रदान करना है। यह पॉलिसी लागत के संदर्भ में तय किया जाना है, जिस पर ट्राई और दूरसंचार विभाग काम कर रहे हैं।

वोडाफोन आइडिया को 10 साल की मोहलत दी है इसलिए अन्य बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर एजीआर बकाया पर समान व्यवहार की मांग कर रहे हैं, केंद्रीय संचार मंत्री ने साफ किया कि यह राहत पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दी गई थी।

लगातार नौवें दिन तेजी के साथ चांदी नए शिखर पर

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना-चांदी नई ऊंचाई पर पहुंच गए। सोने की कीमत करीब 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 3.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर रही।

स्थानीय सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत में भी लगातार नौवें दिन तेजी जारी रही। चांदी की कीमत 11,300 रुपये बढ़कर 3,34,300 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 20,400 रुपये बढ़कर 3,23,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

वहीं, अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 6,500 रुपये यानी 4.24 प्रतिशत बढ़कर 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गया। मंगलवार को, सोने ने पहली बार देश की राजधानी में 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के महत्वपूर्ण स्तर को पार किया।

कारोबार मंच 'फॉरेक्स डॉट कॉम' के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना पहली बार 4,800 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर गया। हाजिर कीमत 124.97 डॉलर या 2.62 प्रतिशत बढ़कर 4,888.46 डॉलर प्रति औंस हो गईं। विदेशी व्यापार में हाजिर चांदी में मजबूती रही, बुधवार को कीमतें 0.33 प्रतिशत बढ़कर 94.91 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

सेंसेक्स 82 हजार अंक से नीचे उतरा

मुंबई, एजेंसी। वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ने, कमजोर संकेतों और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए।

उतार-चढ़ाव भरे सत्र में सेंसेक्स 271 अंक टूट कर 82,000 अंक से नीचे आ गया जबकि निफ्टी में 75 अंक की गिरावट रही।

Jamner Municipal Council
Jalgaon Tal, Jamner, Dist. Jalgaon

e-Tender Notice for 2025-26

"Proposed Development of Wadi Talav (Lake) Situated At Jamner Municipal Council, for Municipal Council Jamner Tal. Jamner Dist. Jalgaon", in the State of Maharashtra, of Estimated Cost **Rs. 7,55,09,257.00/-** The e- Tender details are available on **www.mahatenders.gov.in** All relevant dates will be as per the tender published in web portal **www.mahatenders.gov.in**

Date 21/1/2026

Sd/-
Chief Officer
Jamner Municipal Council

U.P. COOPERATIVE SUGAR FACTORIES FEDERATION LTD
9-A, RANA PRATAP MARG, LUCKNOW-226001
Tel No. (0522) 2200183, (0522)2628310, Fax: (0522) 2627994
Email: upsugarfed@yahoo.co.in | Website: www.upsugarfed.org

NOTICE Date:22.01.2026

SALE OF SCRAP FROM VARIOUS CO-OPERATIVE SUGAR MILLS & DISTILLERIES IN UTTAR PRADESH IN YEAR 2025-26.
Online E-auction are invited from the Agencies/ firm in this field for the sale of scrap from various cooperative sugar mill UTTAR PRADESH:-

S.NO.	Name Of Item	Earnest Money	Start Date of Loading of Auction
1.	SALE OF SCRAP FROM VARIOUS CO-OPERATIVE SUGAR MILLS IN UTTAR PRADESH IN YEAR 2025-26.	RS. 2,00,000.00	22.01.2026

The details for submission of the E-Bids is available on the GEM PORTAL. The bidders will have to deposit auction fees **(Non-Refundable)** of **Rs.1,180.00/-** & earnest money in the form of **RTGS/NEFT/NET BANKING** in favor of **U.P.Co-op. Sugar Factories Federation Ltd, Payable at Lucknow**. Auctions without earnest money will not be accepted. The bank details are available inside the auction document.

The Managing Director/Administrator Federation reserves the right to cancel any or all bids/annual e-bidding process, without assigning and reason to & decision of Federation will be final & binding.

All amendments, clarifications, corrigendum, addendum, time extension etc. will be given on this auction only. Auction keep reading GEM PORTAL regularly for updated information.

MANAGING DIRECTOR

गाजियाबाद नगर निगम
(I.S.O. 14001, 18001 एवं 19001 प्रमाणित संस्था)

पत्रांकः– 4922/उद्यान/2025–26 दिनांक :– 20/01/2026

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

गाजियाबाद नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न कार्य हेतु ई–निविदाऐं दिनांक 22.01.2026 से दिनांक 02.02.2026 तक आमंत्रित की जाती है। जिसमे निविदा सं0–07 में स्वर्ण जयंती पार्क, इंदिरापुरम, गाजियाबाद के व्यापक संचालन, रखरखाव, प्रबंधन और देखभाल के लिए किराए के आधार पर किसी एजेंसी/फर्म/NGO का चयन किये जाने का कार्य भी सम्मलित है। निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई–प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाईड **http://etender.up.nic.in** से प्राप्त किया जा सकता है, जिसे दिनांक 02.02.2026 की मध्यान्हः 03:00 तक वेबसाईड से डाउनलोड कर अपलोड करना आवश्यक होगा। प्राप्त निविदाओं को दिनांक 02.02.2026 की अपरान्हः 04:00 बजे से खोला जायेगा। प्रत्येक निविदा हेतु उसके सम्मुख अंकित धरोहर की धनराशि एवं निविदा शुल्क (Tender Fees Non Refundable) वेबसाईड **http://etender.up.nic.in** पर जमा करना अनिवार्य होगा तथा सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के समय शेष प्रतिशत की, धनराशि अनुबन्ध कराते समय एफ.डी.आर. के रूप में कार्यालय में जमा करानी होगी, जोकि लेखाधिकारी, गाजियाबाद नगर निगम के नाम पर बन्धक होगी। निविदा में प्रतिभागी फर्म योग्य होने पर वित्तीय निविदा आगामी कार्य दिवस में खोली जायेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को अवकाश रहता है, तो निविदा आगामी कार्य दिवस में खोली जायेगी।

विस्तृत शेष नियम व शर्ते एवं सूचना वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर देखी जा सकती है।

उद्यान प्रभारी
गाजियाबाद नगर निगम

भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

बिहार सरकार

ई0 निविदा पद्धति के अनुसार बेवसाइट एवं www.eproc2.bihar.gov.in पर
ई0–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या (SBD)–46/मुजफ्फरपुर/2025–26

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।
2. निविदा आमंत्रण निर्गत की तिथि :– दिनांक–19.01.2026
3. परिमाण विपत्र बिक्री (डाउनलोड) की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक–30.01.2026 से दिनांक–20.02.2026 को 3:00 बजे अप0 तक
4. निविदा प्राप्ति (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय :– दिनांक–21.02.2026 को 3:00 बजे अप0
5. निविदा (तकनीकी बीड) खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक–23.02.2026 को 3:30 बजे अप0
6. निविदा वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय :– तकनीकी बीड निष्पादन के पश्चात्
7. प्रिबीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान :– (i) दिनांक–03.02.2026 को 3.00 बजे अपराह्न को अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय। (ii) दिनांक–09.02.2026 को 3:00 बजे अप0 को मुख्य अभियंता (उत्तर), भवन निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय।
8. परिमाण विपत्र की बिक्री स्थान :– बेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in)
9. निविदा प्राप्ति का स्थान :– बेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in)
10. निविदा बैधता की तिथि :– 120 दिन

कार्य का विवरणः–

क्र. सं0	कार्य का नाम	परिमाण विपत्र की राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मुल्य + बीड प्रोसेसिंग फीस	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिला में संचालित मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर के परिसर में प्रस्तावित अतिरिक्त भवनों यथा–शिक्षकों के लिए टाईप–सी आवासीय भवन (20 यूनिट), 300 बेड बालिका छात्रावास (G+5) एवं 200 बेड बालक छात्रावास (G+3) के निर्माण कार्य। वर्ष–2025–26 (विद्युतीकरण सहित)	42,45,80,000.00	52,45,800.00	eproc2 बेवसाईट के अनुसार	18 माह
2	सात निश्चय कार्यक्रम के अधीन विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में 200 (दो सौ) बेड बालिका छात्रावास (G+3) भवनों के निर्माण कार्य। वर्ष–2025–26 (विद्युतीकरण सहित)	17,88,03,000.00	27,88,100.00	eproc2 बेवसाईट के अनुसार	15 माह

11. विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट **state.bihar.gov.in/prdbihar** & www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

PR- 022328 (B C D) 2025-26

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर।

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1 (पी-2) ग्रेटर नौएडा
Toll Free No. 18001808296, वेबसाइट : www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांकः वाई.ई.ए./भूलेख/तह.–एम.के.एस./264/2026 दिनांक 16.01.2026

सार्वजनिक सूचना

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। क्रय हेतु काश्तकार, गाटा संख्या, क्षेत्रफल व काश्तकार का हिस्सा निम्नलिखित तालिका में अंकित है–

(सैक्टर–11, ग्राम – रबूपुरा के अन्तर्गत)

क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का भाग	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का नाम
1	922	2024	0.6780	में से	0.0843	दिग्विजय सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह राणा नि. कासना ग्रेटर नोएडा
2	922	2024	0.6780	में से	0.0851	सर्वेश सिंह पत्नी संतोष सिंह नि. अलीगढ़
3	926	2000/3	0.2020	में से	0.1010	वेदप्रकाश कौशिक पुत्र हरीराज शर्मा नि. बी–72 गोविंदपुरी ग्वालियर
4	926	2000/3	0.2020	में से	0.1010	गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र हरीराज शर्मा नि. मालीपाडा अलीगढ़
5	1183	2061	8.0140	में से	0.6326	श्री गोपाल पुत्र प्रहलाद नि. मौहम्मदपुर जादों
6	0013 0013	2049मि 2042मि	0.0285 0.0645	में से	0.0143 0.0323	अनिल कुमार पुत्र चन्द्रपाल नि. मौहम्मदपुर जादों
7	508	2031	0.9400	में से	0.2350	श्री मौहम्मद जैद पुत्र श्री मौहम्मद नसीम नि. दिल्ली
8		2009	0.9440	में से	0.3934	प्रदीप कुमार व कुलदीप सिंह व कृपा देवी पुत्र व पत्नी महेशपाल व अजीतपाल सिंह पुत्र सूरजपाल सिंह व प्रेमलता व अदिति सिंह ना. आयु 12 वर्ष व सूर्याशं सिंह ना. आयु 7 वर्ष पुत्र व पत्नी राजीवपाल सिंह नि. मौहम्मदपुर जादों।

(सैक्टर–21, ग्राम – रबूपुरा के अन्तर्गत)

क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का भाग	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का नाम
9	492	659	0.2256	में से	0.0941	प्रियंका पत्नी योगेन्द्र सिंह नि.–सी–286, सै.–37 ग्रेटर नोएडा
10	852	496	3.5740	में से	0.0814	अशोक पुत्र मामचन्द व रश्मि पत्नी मामचन्द नि. कासना ग्रेटर नोएडा
11	261	1305	0.7466	में से	0.1245	कांती पत्नी गिर्राज नि. हाउस नं.–10 विद्यया नगर कालोनी, दादरी
12	121	421	0.4680	में से	0.0468	बालू सिंह पुत्र खिच्चू नि. रबूपुरा

(सैक्टर–34, ग्राम – रबूपुरा के अन्तर्गत)

क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का भाग	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का नाम
13	1095	2066	1.5320	में से	0.2702	दीक्षा चोपड़ा पत्नी दीपक चोपड़ा नि. राजेन्द्र नगर दिल्ली
14		2072	1.7420	में से	0.1742	अमीचन्द पुत्र सोहनलाल नि. ग्राम भुन्नातगा
15	1076	2066	1.5320	में से	0.1054	प्रेमसागर पुत्र भभूती शर्मा नि. पचोकरा

(सैक्टर–33, ग्राम – रबूपुरा के अन्तर्गत)

क्र. सं.	खाता संख्या	खसरा संख्या	गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का भाग	तहसील की आख्यानुसार काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का नाम
16		2224	0.3700	में से	0.0616	महेश पुत्र दीनदयाल नि. ग्राम मुरादगढ़ी

प्रस्तावित भूमि प्राधिकरण के नियोजित सै. 11, 21, 33 व 34 के अन्तर्गत होने के कारण क्रय हेतु प्रस्तावित है।

- उक्त भूमि को क्रय करने हेतु तालिका में अंकित काश्तकारों द्वारा सहमति प्रदान की गयी है जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय की जानी प्रस्तावित है।
- प्रस्तावित भूमि को प्राधिकरण की 84वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या 03 के अनुसार रूपये 3808.00/प्रति वर्ग मी. की दर से सम्बन्धित भूस्वामी के पक्ष में भुगतान किया जाएगा व 07 प्रतिशत आबादी भूखण्ड आवंटित किया जाएगा।

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है वह लिखित रूप में 15 दिवस के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के कार्यालय/सी.आर. सैल में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीद–फ़रोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

संपादकीय जागरण

गुरुवार, 22 जनवरी, 2026 : माघ शुक्ल - 4 वि. 2082

दृढ़ता के अभाव में संकल्पों की पूर्ति संभव नहीं

मुफ्त की रेवड़ियां

यह स्वागतयोग्य है कि सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें मांग की गई है कि देश पर बढ़ते कर्ज को देखते हुए राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लोकलुभावन घोषणाओं का संज्ञान लिया जाए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले भी यह मामला सामने आ चुका है और उसने चुनाव आयोग को इस संदर्भ में कुछ निर्देश भी दिए थे, लेकिन उनसे बात बनी नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजनीतिक दल चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए जनकल्याण के नाम पर मुफ्त में सुविधाएं और रियायत देने वाली घोषणाएं करने लगते हैं। कुछ दल तो सीधे-सीधे धन देने की घोषणा भी करने लगे हैं। चूंकि ऐसी घोषणाएं चुनाव जीतने में सहायक बनने लगी हैं, इसलिए उनका सिलसिला तेज होता जा रहा है। एक समय जो काम तमिलनाडु में होता था, वह अब शेष देश में भी होने लगा है। स्थिति यह है कि जो भाजपा लोकलुभावन योजनाओं को मुफ्त की रेवड़ी बताती थी, वह भी ऐसी योजनाओं की घोषणा करने लगी। मुफ्त की योजनाएं यह कहकर शुरू की जाती हैं कि इससे निर्धन-वंचित तबके को लाभ मिलेगा और उनका आर्थिक उत्थान होगा, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि ऐसी योजनाएं न केवल सरकारी खजाने पर बोझ बनती हैं, बल्कि निर्धन वर्गों को सरकार पर निर्भर भी बनाती हैं।

निःसंदेह भारत जैसे निर्धन आबादी वाले देश में सरकारों को गरीब एवं वंचित लोगों की चिंता करनी होगी और उनके आर्थिक उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रयत्न भी करने होंगे, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जनकल्याण के नाम पर आर्थिक नियमों की अनदेखी कर दी जाए। फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। लोकलुभावन घोषणाओं पर लगाम लगाने के लिए पहली आवश्यकता तो इसकी है कि इसे परिभाषित किया जाए कि वास्तविक जनकल्याण क्या है और सरकारों को उसे कैसे करना चाहिए? ऐसी किसी योजना को जनकल्याणकारी नहीं कहा जा सकता, जो लोगों को आत्मनिर्भर न बनाए यानी उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित न करे। जनकल्याण के नाम पर ऐसी योजनाएं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के विपरीत हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को लालच देकर उनके वोट हासिल करना होता है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना होगा कि राजनीतिक दल जनकल्याण के बहाने लोकलुभावन घोषणाएं करते समय राज्य विशेष की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। उन्हें ऐसी योजनाएं शुरू करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, जो राज्य की आर्थिक स्थिति को डांवाडोल करें और उनके पास बुनियादी विकास के काम करने के लिए भी धन का अभाव व्याप्त हो जाए। ध्यान रहे कई राज्यों को अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के भी लाले पड़े हैं।

दीर्घावधि उपाय जरूरी

दिल्ली समेत एनसीआर के वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान वाहनों का ईंधन जलने से उत्सर्जित होने वाली जहरीली गैसों का है। केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दी गई ये जानकारी बिलकुल सही है, वहीं यह निराशाजनक भी है कि विगत कई वर्षों से इसपर कोई ठोस कार्य नहीं हुआ है। यह निराशाजनक है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह यह है कि वाहनों से उत्सर्जित होने वाले धुएं को नियंत्रित करने की दिशा में विगत डेढ़ दशक में कोई ठोस उपाय नहीं किए गए।

> राजधानी की सड़कों से बाटलनेक दूर करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है

राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बदहाल स्थिति में है। डीटीसी बसों के बेड़े की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। पर्याप्त संख्या में बसें न होने के कारण सड़कों से निजी वाहनों को कम करने में सफलता नहीं मिल रही है। सड़कों पर बाटलनेक यातायात की गति को अचानक रोक देते हैं। इससे जाम लगता है और वाहन काफी देर तक धीमी गति से चलते रहते हैं, जिससे उनसे जहरीली गैसों का उत्सर्जन सामान्य परिस्थितियों के मुकाबले अधिक होता है। ऐसे में मुख्यतया सड़कों से बाटलनेक दूर करने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है। जब तक इन बिंदुओं पर ठोस काम नहीं होगा, वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार की उम्मीद करना बेमानी ही है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने से युवाओं का पार्टी के साथ जुड़ाव बढ़ेगा?

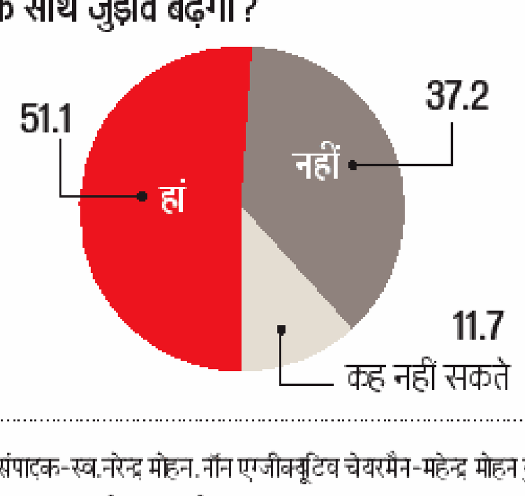

आज का सवाल
क्या ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का पहला साल विश्व में अमेरिका का सम्मान घटाने वाला साबित हुआ है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

विवाद बढ़ाने का काम करता चीन

विजय क्रांति

शक्सगाम घाटी को लेकर चीन का रवैया एक ऐसी चेतावनी है, जिस पर भारत को पूरी तरह चौकस रहने की आवश्यकता है

जब अमेरिका भारत के समक्ष समस्याएं खड़ी करने से बाज नहीं आ रहा है, तब चीन भी चिंता का कारण बन रहा है। वास्तव में चीन ने जबसे 1951 में तिब्बत पर जबरन कब्जा करके भारत-तिब्बत सीमा को भारत-चीन सीमा में बदल दिया, तबसे उसके भारत-विरोधी रुख में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। पहले तो उसने 1962 में तिब्बत को छावनी की तरह इस्तेमाल करके भारत पर हमला किया। इसके बाद से वह सैकड़ों किलोमीटर लंबी इस सीमा पर उकसावे की कोई न कोई हरकत करता आ रहा है। आर्थिक और सैनिक शक्ति हासिल करने के बाद तो चीन की यह आक्रामकता सीधी दादागीरी में बदल चुकी है। पहले वह भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों पर जुबानी दावे करता था, लेकिन 2017 में डोकलाम घाटी पर कब्जे की कोशिश में मुंह की खाने के बाद उसने पूरी सीमा पर बड़े पैमाने पर सैन्य निर्माण शुरू करके भारत के लिए नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। पिछले दिनों अंतरिक्ष से सीमाओं की टोह लेने वाले भारतीय उपग्रहों से पता चला कि लद्दाख में चीनी कब्जे वाले शक्सगाम इलाके में चीनी सेना एक ऐसी सड़क बना रही है, जो भारत-पाकिस्तान और चीन के इस मिलन क्षेत्र में सियाचिन की सुरक्षा के लिए नए खतरे पैदा कर सकती है।

शक्सगाम घाटी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भारत में विलय के बाद भारत का हिस्सा थी, लेकिन अक्टूबर 1947 में उस पर हमले में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया था। 1962 के भारत-चीन युद्ध के एक साल बाद ही पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए 1963 की एक संधि के तहत शक्सगाम का लगभग 5,180 वर्ग किमी क्षेत्र चीन को सौंप दिया। रणनीतिक दृष्टि से शक्सगाम के भौगोलिक महत्व को इससे समझा जा सकता है कि यह पाकिस्तान द्वारा भारत से छीने गए गिलगित-बाल्टिस्तान और चीन द्वारा 1949 में कब्जाए गए ईस्ट-तुर्किस्तान (चीन द्वारा दिया गया नया नाम 'शिनजियांग') को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा यह सियाचिन के बहुत निकट है जो शक्सगाम और भारत के उस अक्साई चिन को अलग करता है, जिस पर 1950 के दशक में चीन ने गुपचुप कब्जा कर लिया था। शक्सगाम में चीन की यह नई सड़क बन जाने के बाद दुनिया के सबसे ठंडे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तानी हमलों से बचाने में जुटी भारतीय सेनाओं के लिए खतरा दोगुना हो जाएगा। आज सियाचिन पर उपस्थिति के कारण भारतीय सेना चीन के सैनिक महत्व वाले कराकोरम हाईवे पर नजर रख सकती है, जिसकी वजह से सियाचिन चीन के आंख की किरकिरी बना हुआ है। इसी क्षेत्र पर कब्जे के लिए 2021 में चीनी सेना ने गलवन में धोखे से हमला किया था।

अवधेश राजपूत

दुनिया के सबसे कठिन इलाकों में गिने जाने वाले इस क्षेत्र में सड़कों के सैनिक महत्व को इससे समझा जा सकता है कि गलवन कांड के तुरंत बाद भारतीय सेना ने जिस गति और संख्या के साथ चीनी सैनिकों पर जवाबी हमला करके चीन को झकझोर दिया, वह केवल इसलिए संभव हो पाया कि उससे पहले ही भारतीय सेनाओं को लेह और श्योक से गलवन होते हुए दौलतबेग ओल्डी तक पक्की सड़क मिल चुकी थी। मोदी सरकार को इसका श्रेय जाता है कि उसने भारत-तिब्बत सीमा पर लगने वाली लगभग हर चौकी को 70 से ज्यादा नई और बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया है। जैसी उम्मीद थी, सैटेलाइट चित्रों के बाद भारत सरकार ने चीन के समक्ष विरोध दर्ज किया है। न केवल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, बल्कि थलसेना अध्यक्ष ने भी चीन को याद दिलाया है कि शक्सगाम घाटी एक भारतीय क्षेत्र है और उसे चीन को सौंपने वाला 1963 का पाकिस्तान-चीन समझौता गैरकानूनी और अस्वीकार्य है। चीन ने अपने परंपरागत अक्खड़ अंदाज में इस विरोध को अस्वीकार करते हुए इसे दो सार्वभौम देशों के बीच हुआ समझौता बताने का प्रयास किया, लेकिन यह कहते हुए चीनी प्रवक्ता ने इस तथ्य को छिपा लिया कि उस समझौते में साफ-साफ लिखा है कि शक्सगाम भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित इलाका है और भविष्य में इस विवाद के सुलझने पर इस इलाके के अधिकार वाली सरकार से नया समझौता किया जाएगा।

शक्सगाम घाटी को लेकर विवाद के बीच सवाल यह है कि चीन ने नई सड़क बनाकर भारत के साथ नया विवाद शुरू करने का फैसला करने के लिए यही समय क्यों चुना? इसे समझने के लिए चीनी रणनीति और इतिहास पर एक नजर डालना काफी होगा। 1912 में स्वतंत्र चीनी गणराज्य की स्थापना के बाद चीन ने तिब्बत, दक्षिणी मंगोलिया और मंचूरिया पर कब्जा करके जिन 14 देशों के साथ सीमाएं साझा की हैं, उनमें से 12 में से अधिकांश के साथ उसने सीमा समझौते ऐसे मौकों पर किए, जब वे किसी न किसी कारण से कमजोर थे और चीन के दबाव में थे, लेकिन भारत और भूटान के साथ उसने सीमा समझौते इस कारण टाले हुए हैं कि धीरे-धीरे लक्षित इलाकों में उनकी जमीन हड़पने के बाद ही और 'उचित' अवसर आने पर ही वह ये समझौते करेगा।

चीन ने एशिया में हर बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए ऐसे समय का चुनाव किया, जब बड़ी शक्तियां किसी बड़े विवाद में उलझी हुई थीं। उदाहरण के लिए तिब्बत पर कब्जा जमाने के लिए उसने मुख्य सैनिक हमला तब किया जब उसने सोवियत संघ के साथ मिलकर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच युद्ध शुरू करके अमेरिका को उस झगड़े में उलझा दिया। इसके बाद 1962 में उसने अक्टूबर में भारत पर तब हमला किया, जब क्यूबा में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों की तैनाती को लेकर पूरी दुनिया का ध्यान इस तनाव पर टिका हुआ था। आज भारत के एकमात्र भरोसेमंद दोस्त रूस ने खुद को यूक्रेन के साथ अपने अंतहीन युद्ध में उलझा लिया है और इस कारण काफी कमजोर हो चुका है। चीन-विरोध के नाम पर भारत की मदद का फैसला कर सकने वाला अमेरिका भी इस समय दुनिया भर के साथ आर्थिक टकराव में बुरी तरह उलझा हुआ है। ऐसे में भारत के लिए चीन की ओर से किसी अनुचित कार्रवाई का खतरा पहले से अधिक है। शक्सगाम में चीन का नया कदम एक ऐसी चेतावनी है, जिस पर भारत को पूरी तरह चौकस रहने की आवश्यकता है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं सेंटर फार हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

मुख्यधारा के विकास से जुड़तीं महिलाएं

डा. आलोक मिश्रा

माइक्रोफाइनेंस ने महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और बचत को भी बढ़ावा दिया है

संप्रति महिलाओं के माध्यम से एक प्रभावी आर्थिक क्रांति आकार ले रही है। लाखों महिलाएं सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, स्थानीय व्यापार और हस्तशिल्प जैसे छोटे, अनौपचारिक उद्यमों से अपनी आजीविका चला रही हैं। यह उनका पहला स्थायी और स्वतंत्र आय का स्रोत बनता है। इस परिवर्तन में माइक्रोफाइनेंस ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है। बिना गारंटी वाले ये छोटे कर्ज, जो घर की दहलीज पर ही आसान किस्तों पर उपलब्ध हैं, महिलाओं की आजीविका और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, परिवार की आय को सुदृढ़ करने और अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम बनाते हैं। इन महिलाओं के लिए माइक्रोफाइनेंस केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि सम्मानजनक आजीविका का माध्यम और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने वाली एक जीवनरेखा बनकर उभरा है।

एक ऐसे दौर में जब तमाम प्रयासों के बीच ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में पारंपरिक बैंकों की पहुंच अब भी कुछ अपेक्षाकृत रूप से सीमित है, तब इस स्थिति में माइक्रोफाइनेंस एक वरदान बनकर उभरा है। आज माइक्रोफाइनेंस भारत के दूर-दराज वाले इलाकों तक गहराई से अपनी पैठ बना चुका है। यह देश के 720 जिलों में लगभग 7.5 करोड़ ऐसे लोगों को अपनी वित्तीय सेवाओं का लाभ दे रहा है, जिस तबके के लोगों की आय कम है। इनमें देश के 112 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इन लाभार्थियों में लगभग 100 प्रतिशत महिलाएं हैं, जिनके लिए माइक्रोफाइनेंस औपचारिक ऋण प्रणाली से जुड़ाव की पहली कड़ी बन गई है। इसने आर्थिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर तक औपचारिक वित्त को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दृष्टि से यह कहना उचित होगा कि माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेशन का सशक्त स्तंभ बनकर उभरा है।

माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से ऋण प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग पहली पीढ़ी के उद्यमी होते हैं, जिनके व्यवसाय समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होते हैं। प्रारंभिक ऋण जोकि 30,000 से 50,000 के बीच होता है, उसका उपयोग बुनियादी उपकरण खरीदने में किया जाता है। अगले चरण के ऋण चक्र आय के स्रोतों में विविधता और उत्पादन विस्तार को संभव बनाते हैं। तयशुदा किस्तें वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देती हैं और नियमित आय परिवारों को अस्थायी मजदूरी की अनिश्चितता से बाहर निकालने में सहायक होती है। यह परिवर्तन केवल अनुभवजन्य नहीं, बल्कि संरचनात्मक भी है। वर्ष 2021 में एनसीएईआर के एक अध्ययन के अनुसार माइक्रोफाइनेंस का भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान कुल सकल मूल्य वर्धन का लगभग 2.03 प्रतिशत है और यह लगभग 1.30 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करने में सहायक बना है। इससे स्पष्ट है कि माइक्रोफाइनेंस आज वर्तमान भारत की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुका है। माइक्रोफाइनेंस परिदृश्य पर आरबीआइ द्वारा विनियमित संस्थाएं सख्त दिशानिर्देशों, फेयर प्रैक्टिसेज कोड और उद्योग की आचार संहिता के तहत जिम्मेदार ऋण प्रथाओं का पालन करती हैं, जिससे महिला उधारकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। आरबीआइ के अनुसार किसी उधारकर्ता की कुल माइक्रोफाइनेंस ऋण चुकौती उसकी घरेलू आय के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।

रोजगार सृजन से आत्मनिर्भरता की ओर कदम ● फाइल

इसके साथ ही आरबीआइ द्वारा मान्यता प्राप्त स्व-नियामक संगठन माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क यानी एमएफआइएन द्वारा निर्धारित प्रविधान भी लागू होते हैं। इसमें उधार की सीमा को निर्धारित कर ऋण जोखिम को कम किया जाता है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली भी मौजूद है, जिसमें एमएफआइएन दूसरे स्तर की व्यवस्था को चौबीसों घंटे संचालित करता है। ये सभी सुरक्षा प्रविधान जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उधारकर्ताओं की रक्षा करते हैं और समग्र सेक्टर की दीर्घकालिक स्थिरता को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके बावजूद अपने प्रमाणित प्रभाव के बावजूद माइक्रोफाइनेंस सेक्टर इस समय गंभीर नकदी संकट से जूझ रहा है। इसके कारण करीब 50 लाख जरूरतमंद औपचारिक ऋण व्यवस्था से बाहर हो गए हैं। इससे उनके फिर से साहूकारों और बिना नियमन वाली अनौपचारिक ऋण व्यवस्थाओं के शिकंजे में फंसने का जोखिम बढ़ गया है। ऐसे में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को महंगे कर्ज के दुष्चक्र में फंसने से बचाने के लिए संगठित और विनियमित माइक्रोफाइनेंस में औपचारिक वित्त का प्रवाह बनाए रखना आवश्यक हो गया है।

प्रभाव के स्तर पर भी देखा जाए तो आय अर्जन से इतर माइक्रोफाइनेंस का सामाजिक प्रभाव गहरा और स्थायी है। यह महिलाओं की घरेलू निर्णय भूमिका को सशक्त करता है, शिक्षा-स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाता है और बचत की आदत को प्रोत्साहित करता है। जैसे-जैसे महिलाएं वित्तीय योगदानकर्ता और रोजगार सृजनकर्ता बनती हैं, वे परिवार और समुदाय दोनों में सामाजिक सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करती हैं। महिला-केंद्रित विकास की दिशा में बढ़ते भारत के लिए, निरंतर पूंजी प्रवाह और सशक्त नियामक निगरानी के साथ माइक्रोफाइनेंस एक बुनियादी स्तंभ बना रहेगा, जो आजीविका के माध्यमों को मजबूत कर भारत की विकास गाथा में निर्णायक योगदान देने में सक्षम बन रहा है।

(लेखक माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क-एमएफआइएन के सीईओ एवं निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चेतना के सोपान

हमारे मनीषियों ने मानव अस्तित्व को चार विशिष्ट श्रेणियों में विभक्त किया है, जो आत्मिक समुन्नति के विभिन्न सोपानों को दर्शाती हैं।

जीव कोटि मानवीय चेतना की वह प्राथमिक और संवेदनशील अवस्था है, जहां मन पूर्णतः बाह्य परिस्थितियों का दास होता है। इस धरातल पर मनुष्य सुख की मंद-मंद सुगंधित शीतल वायु से प्रफुल्लित और दुख के झंझावातों से तत्काल विचलित हो उठता है। यह अवस्था पराधीनता की परिचायक है, जहां व्यक्ति का आंतरिक संतुलन पूर्णतः बाह्य जगत के आधीन होता है। जब मनुष्य विवेक और आत्मसंयम का संबल पाकर द्वंद्वों से ऊपर उठता है, तब वह आत्मा कोटि में प्रवेश करता है। यह अवस्था 'स्थितप्रज्ञता' की है, जहां व्यक्ति सुख और दुख, दोनों ही परिस्थितियों में हिमालय की भांति अडिग और धैर्यवान रहता है। यहां परिस्थितियां बदलती तो हैं, किंतु वे अंतरात्मा की शांति को भंग नहीं कर पाती हैं, यह आत्मिक स्थिरता ही मनुष्य को स्वयं का स्वामी बनाती है।

चेतना का और अधिक विस्तार होने पर महात्मा कोटि का प्राकट्य होता है। इस सोपान पर व्यक्ति अपनी क्षुद्र 'स्व' की सीमा को लांघकर 'सर्व' के कल्याण में ही अपनी सार्थकता ढूंढ़ता है। यहां सेवा केवल एक कार्य नहीं, अपितु जीवन का नैसर्गिक धर्म बन जाता है। निष्काम भाव से लोक-मंगल के लिए स्वयं को अर्पित कर देना ही इस श्रेणी की पराकाष्ठा है। अंततः, समस्त सीमाओं से परे वह परमात्मा कोटि है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है। यह वह परम सत्ता है, जिसके कर-कमलों में जीवन-मृत्यु, हानि-लाभ और यश-अपयश की अदृश्य डोर है। वह सर्वसामर्थ्यवान, निर्विकार और शाश्वत है। परमात्मा वह आदि और अंत है, जहां पहुंचकर साधक और साध्य का भेद मिट जाता है। जीव का इस परम तत्व की ओर अग्रसर होना ही मानव जीवन की चरम परिणति है।

आचार्य नारायण दास

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

विश्व के लिए संकट बढ़ाते ट्रंप

'ट्रंप के रवैये से त्रस्त दुनिया' विषय पर प्रकाशित हर्ष वी. पंत का लेख बहुत सामयिक है। एक ओर तो ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपना दावा करते रहे हैं तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित घर से उठा लेना और अमेरिकी जेल में कैद रखना आखिर किस देश के मुखिया को शोभा देता है? ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर भी वे आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। यह कुछ और नहीं एक महाशक्ति देश के मुखिया का अहंकार ही है। पूरा यूरोप आज ट्रंप के विरुद्ध मुखर है। आज पूरी दुनिया ट्रंप टैरिफ से परेशान है। ट्रंप जब सत्ता में आए तो उनका पूरा लक्ष्य अमेरिका फर्स्ट था, पर अब वे अमेरिका को और संकट में डालने का काम कर रहे हैं। खुद अमेरिकी नागरिक उनकी नीतियों से परेशान हैं, क्योंकि इससे वहां महंगाई बढ़ रही है। उनकी दमनकारी नीतियों से तमाम देशों के समक्ष संप्रभुता का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में भारत को भी अमेरिका के साथ सक्रियता के मामले में संभलकर कदम उठाने होंगे।

समीक्षा मिश्रा, भारतीय जनसंचार संस्थान, जम्मू

भाजपा का युवा चेहरा

औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के तौर पर 45 वर्षीय नितिन नवीन के पदभार संभालने के उपरांत पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार पैदा होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा कि भाजपा में पार्टी अध्यक्ष को अपने काम को अपने ढंग से करने की आजादी रहती है। यह मोदी का बड़प्पन ही है कि नितिन नवीन के युवा होने, ऊर्जावान होने एवं संगठन में व्यापक अनुभव होने का सराहनीय जिक्र किया है। नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद दल के सदस्यों को भी उनसे काफी अपेक्षाएं हैं कि वे पार्टी में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे और दलगत संविधान के अनुरूप सदस्यों को ढालने का कार्य बखूबी निभाएंगे। पार्टी अध्यक्ष की यह भी भूमिका होगी कि वे एनडीए से जुड़े सहयोगियों को बिगड़ने न दें और पार्टी के बढ़ते वर्चस्व के साथ तालमेल भी बढ़ा रहे। जैसा कि राजनीति में जगजाहिर है कि चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण एवं प्रत्याशियों की जीतने की संभावना एवं विरोधियों को परास्त करने की रणनीति के लिए मतदाताओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़े रखने के लिए कार्य करना होता है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा की हालिया जीत जनता के विश्वास जीतने का उदाहरण दर्शाता है कि भाजपा की पकड़ देश में चहुंओर बढ़ी है। इस जीत में पूर्व पार्टी अध्यक्षों का स्वर्णिम योगदान रहा है। पार्टी को लगातार आगे बढ़ाते रहने के लिए दल के अंदरूनी मतभेदों एवं भीतरघात को न्यूनतम करना जिलाध्यक्षों, प्रदेशाध्यक्षों एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी की जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि पार्टी के युवा चेहरा नितिन नवीन इसमें कामयाब होंगे और पार्टी अधिक मजबूत होगी। भाजपा के लोकतांत्रिक पार्टी वाले चेहरे को भी नितिन उज्जवल करेंगे। इसकी उम्मीद भी की जा सकती है। कुल मिलकर भाजपा के इस युवा चेहरे से पार्टी के युवा सोच का भी पता चलता है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

सनकी ट्रंप

निर्विवाद रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। 80 वर्ष पूर्व स्थापित इस संस्था में न तो निर्णायक निर्णय लेने की क्षमता है न ही उनको लागू कराने का सामर्थ्य। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश एवं विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं बनाया जा सका है। वहां के नियम ऐसे हैं कि 193 सदस्यों वाली संस्था में यदि 192 सदस्य भी एक प्रस्ताव पास करना चाहें तो वह पास नहीं करा सकते दि अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन एवं यूके में से कोई भी एक उसके विरुद्ध हो। संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर तो था ही, रही सही कसर अमेरिका ने उसके आनुषंगिक संगठनों से त्यागपत्र देकर निकाल दी। अब ट्रंप गांजा में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की तर्ज पर एक संस्था ''बोर्ड आफ पीस'' बनाना चाहते हैं। ट्रंप इसके आजीवन चेयरमैन रहेंगे। बोर्ड आफ पीस का सदस्य बनने के लिए भारत, पाक, चीन सहित 60 देशों को न्योता भेजा है। अभी तक केवल हंगरी ने अपनी सहमति दी है। तीन देशों की सहमति प्राप्त होते ही यह अस्तित्व में आ जाएगा। तीन वर्ष के लिए सदस्यता शुल्क एक अरब डालर है। इस राशि से गाजा का पुनर्विकास किया जाएगा। अमेरिकन का यह मानना है कि सनकी ट्रंप इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ को चुनौती देने का प्रयास करेंगे।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

पोस्ट

अगर कोई व्यक्ति इस कारण युद्ध की धमकी दे कि उसे नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो समझिए कि वह कभी ऐसे पुरस्कार के योग्य नहीं हो सकता।
जो@JoJoFromJerz

अमेरिका को यह समझना होगा कि अपने साथियों को दगा देने वाली महाशक्तियां लंबे समय तक महाशक्ति नहीं रह जातीं। निक कोहेन@NickCohen4

सुनने में यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन यह भी इतिहास का एक पड़ाव है कि अमेरिका को संतुलित करने के लिए यूरोप इस समय भारत की ओर निहार रहा है और एक बड़ा व्यापार समझौता करने के बहुत करीब है। प्रोसेनजीत@mitrapredator

इंजीनियर युवराज की मृत्यु के मामले में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को हटाना ही काफी नहीं। मौके पर मौजूद दमकल, एसडीआरएफ और पुलिस के उन कर्मियों का क्या, जो पानी ठंडा होने की बात कह कर युवराज को बचाने नहीं उतरे और उनकी आंखों के सामने युवराज ने दम तोड़ दिया? क्या इन सभी को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए?
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जनपथ

मुखिया बनकर आ गए युवा विनम्र 'नवीन',
भाषण में शालीनता दिखती सोच जहीन।
दिखती सोच जहीन जोर भरपूर लगाएं,
कठिन किलों पर आप भाजपा ध्वज फहराएं।
तमिलनाडु-बंगाल उधेड़ो सबकी बखिया,
कहलाओगे आप तभी तो काबिल मुखिया!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 188

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दैनिक जागरण को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी सम्मानित

राज्य ब्यूरो, जागरण. पटना : भारत निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेगा। यह सम्मान मतदाता जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार-प्रसार एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने में दैनिक जागरण के निरंतर एवं प्रभावी योगदान के लिए दिया जा रहा है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु पुरस्कार प्रदान करेंगीं। इससे पहले 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी दैनिक जागरण को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था।

2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी दैनिक जागरण को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राष्ट्रपति से मिला था पुरस्कार

चुनाव आयोग का मानना है कि लोकतंत्र की मजबूती में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दैनिक जागरण ने वर्षों से सामाजिक सरोकार, निष्पक्ष पत्रकारिता के दायित्व को निभाते हुए मतदाता शिक्षा एवं सहभागिता को केंद्र में रखकर विशेष अभियान, ग्राउंड रिपोर्ट, संपादकीय एवं जनजागरूकता श्रृंखलाएं प्रकाशित की हैं। विशेषकर युवा मतदाताओं, महिला मतदाताओं एवं पहली बार मतदान करने वालों तक पहुंच बनाने में अखबार की भूमिका को आयोग ने सराहा है।

मतदान को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया: दैनिक जागरण द्वारा चलाए गए, 'पहले मतदान, फिर जलपान'', 'युवा वोटर, मजबूत लोकतंत्र'' जैसे अभियानों ने आमजन के बीच मतदान को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया। चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत बढ़ाने, कथित खबरों से सावधान करने के साथ ही ईवीएम-वीवीपैट जैसे विषयों पर तथ्यपरक जानकारी देने में भी दैनिक जागरण की पहल उल्लेखनीय रही है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में अखबार की व्यापक पहुंच ने इन अभियानों को प्रभावी बनाया।

पुरस्कार पाठकों के विश्वास एवं पत्रकारों की प्रतिबद्धता का परिणाम: दैनिक जागरण ने 22 वर्ष उपरांत हुए एसआइआर (मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर लगातार जागरूक किया। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने, मतदान के अधिकार एवं दायित्व पर निरंतर प्रकाश डालने से लोगों में जागरूकता बढ़ी। उन लोगों ने मतदान का संकल्प लेते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ ली। बिहार में रिकार्ड मतदान हुआ, जिसमें दैनिक जागरण ने समाचारीय-पत्रकारीय अभियान से इसमें अपना योगदान दिया। यह पुरस्कार पाठकों के विश्वास एवं पत्रकारों की प्रतिबद्धता का परिणाम है। दैनिक जागरण ने हमेशा निष्पक्ष, तथ्यात्मक और जनहितकारी पत्रकारिता को प्राथमिकता दी है।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध मतदाता सूची है जरूरी : ज्ञानेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर विपक्षी राजनीतिक दलों के विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त व अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान (आइडीईए) के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार ने बुधवार को वैश्विक मंच से एसआइआर की पैरवी की है। साथ ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध मतदाता सूची को जरूरी बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह मुद्दा तब उठाया, जब दुनिया के अधिकांश देश मतदाता सूची की गड़बड़ियों की समस्या से जूझ रहे।

अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाता सूची को लेकर उठाए गए अपने कदमों को साझा करते हुए बताया कि हाल ही में बिहार में इस प्रक्रिया को अपनाया गया। इस दौरान तैयार की गई ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी का नाम छूट जाने या गलत जुड़ने पर राजनीतिक दलों से दावे-आपत्तियां भी मांगी गई थी लेकिन एक भी आपत्तियां नहीं मिली। जो

अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते मुख्य चुनाव आयुक्त ● एएनआइ

यह बताता है कि मतदाता सूची तैयार करने का काम कितनी पारदर्शिता के साथ किया गया था। इतना ही नहीं, बिहार में दो चरणों में एक लाख मतदान केंद्रों पर हुए चुनाव में किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराने की नौबत नहीं आई। उन्होंने कहा शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनाव कराने तक की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने उच्च स्तर की दक्षता हासिल कर ली है। तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया के 70 से अधिक देशों के सौ से अधिक चुनावी प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि, राजदूत, उच्चायुक्त और विशेषज्ञ शामिल हैं।

बंगाल में चुनाव आयोग के खिलाफ प्राथमिकी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: बंगाल के पुरुलिया जिले में निर्वाचन आयोग के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 82 वर्षीय आदिवासी दुर्जन माझी की मौत का जिक्र है, जिसने राज्य में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर कथित तौर पर चिंता के कारण आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग के बेटे द्वारा पारा पुलिस थाना में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर घटना के 23 दिन बाद मामला दर्ज किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि मामले में निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में किसी भी अधिकारी का नाम नहीं है। दुर्जन ने ब्लाक कार्यालय में एसआइआर सुनवाई के लिए पेश होने से कुछ घंटे पहले 29 दिसंबर को आत्महत्या कर ली। एक अन्य घटना में पुरुलिया जिले के मानबाजार में 32 वर्षीय एक आदिवासी व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उसके परिवार ने यह दावा कि उसने यह आत्मघाती कदम तब उठाया

नागरिकता साबित करने को 10 बार बुलाए जाने पर भी आऊंगा : शमी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● कोलकाता: भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मंगलवार को बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए कोलकाता में चुनाव अधिकारियों के सामने पेश हुए। सुनवाई के बाद उन्होंने कहा-'मैं एक गर्वित भारतीय और बंगाल का निवासी हूं। नागरिकता साबित करने के लिए 10 बार बुलाए जाने पर भी आऊंगा।' 462 अंतरराष्ट्रीय विकेट चटका चुके शमी दक्षिण कोलकाता के बिक्रमगढ़ इलाके के स्कूल में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पेश हुए। राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शमी द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र में कुछ स्थानों पर विसंगतियां थीं, जिसके कारण सुनवाई के लिए तलब किया गया था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले शमी क्रिकेट करियर के कारण छोटी उम्र में कोलकाता आ गए थे और यहां के जादवपुर इलाके के काटजूनगर में रह रहे हैं। वह कोलकाता नगर निगम के वार्ड-93 के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

मोहम्मद शमी

जब उसे एसआइआर सुनवाई का नोटिस मिला। चुनाव आयोग 'नो मैपिंग' मतदाताओं की सूची भी जारी करेगा। सूत्रों के अनुसार बंगाल में नो मैपिंग मतदाताओं की संख्या 31,68,426 है, वहीं तार्किक विसंगतियों वाले मतदाताओं की संख्या 14,49,132 हैं। वहीं चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपित वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस (डब्ल्यूबीसीएस) के चार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत से रिपोर्ट तलब की है।

एक नजर में

तृणमूल विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं को निकालकर दी जिंदा जलाने की धमकी

मालदा: तृणमूल कांग्रेस विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जिंदा जलाने की धमकी दी है। बंगाल में मालतीपुर के तृणमूल कांग्रेस विधायक अब्दुर रहीम बक्शी ने इस विवादित बोल से भाजपा पर निशाना साधा है। तृणमूल विधायक ने एसआइआर के कथित भय से मृत मोहम्मद जलील की कब्र की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और विरोध प्रदर्शन में कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जिंदा जला दिया जाना चाहिए। मोहम्मद जलील की मौत के बाद तृणमूल कांग्रेस ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। विधायक इसी प्रदर्शन को संबोधित कर रहे थे। (जासं)

बंगाल पुलिस को निर्देश, एसआइआर के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखें

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बुधवार को बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखें। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को चुनाव आयोग को "तार्किक विसंगतियों" की सूची में शामिल नामों को ग्राम पंचायत भवनों और ब्लाक कार्यालयों में प्रदर्शित करने का आदेश देने के बाद आया है। (प्रेट्र)

कल्याण-डोंबीवली में भी महापौर पद पर शिवसेना-भाजपा में रार

मनसे ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन की पेशकश की

- शिंदे गुट बहुमत के लिए अन्य पार्टियों के चुनकर आए पार्षदों से संपर्क साध रही
- 122 सदस्यों वाली कडोमपा में शिवसेना (शिंदे) और भाजपा ने मिलकर लड़ा था चुनाव

राज्य ब्यूरो, मुंबई: महापौर पद के लिए शिवसेना (शिंदे) और भाजपा के बीच चल रही खींचतान सिर्फ मुंबई महानगरपालिका तक ही सीमित नहीं है। कल्याण-डोंबीवली महानगरपालिका में भी सत्तारूढ़ गठबंधन के ये दोनों दल अपना-अपना महापौर बनाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) से गठबंधन करके बीएमसी चुनाव लड़ी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कल्याण-डोंबीवली में अपने पांच सदस्यों का समर्थन शिंदे के पक्ष में घोषित कर पलड़ा भारी कर दिया है।

122 सदस्यों वाली कल्याण-डोंबीवली महानगरपालिका (कडोमपा) में शिवसेना (शिंदे) और भाजपा मिलकर चुनाव लड़े थे। शिवसेना को 53 और भाजपा को 52 सीटें मिली हैं। शिवसेना (यूबीटी) 11 और मनसे पांच सीटों पर सिमट गई हैं। यूबीटी के 11 में से चार पार्षद परिणाम आने के बाद से ही अपनी पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। उनके फोन नहीं लग रहे हैं। उनमें से एक पार्षद तो खुलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र डा.श्रीकांत शिंदे के साथ दिखाई दे चुके हैं। आज राज ठाकरे की मनसे के पांच पार्षदों ने भी अपना समर्थन शिवसेना के महापौर के पक्ष में घोषित कर दिया है। अब भी शिवसेना बहुमत के लिए जरूरी 62 के आंकड़े से एक-दो सीट दूर ही है। शिंदे गुट इस संख्या तक पहुंचने के लिए अन्य पार्टियों के चुनकर आए आठ पार्षदों से भी संपर्क साध रही है। या शिवसेना (यूबीटी) के ही कुछ और पार्षद भी उसके साथ आ जाएं, तो उसका महापौर बन सकता है। भाजपा के लिए इस अंक तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल लग रहा है।

महापौर बनाना भाजपा और शिवसेना के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई: भाजपा-शिवसेना ने कडोमपा का चुनाव गठबंधन करके भले लड़ा हो, लेकिन इस महानगरपालिका में महापौर बनाना दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण डोंबीवली विधानसभा सीट से ही लगातार चौथी बार विधायक हैं, तो एकनाथ शिंदे के पुत्र डा.श्रीकांत शिंदे उपमुख्यमंत्री का गढ़ माने जानेवाले ठाणे जिले में ही आनेवाले कल्याण लोकसभा सीट से सांसद हैं। महानगरपालिका चुनाव में इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दोनों दलों ने बड़ी संख्या में एक-दूसरे के दलों से नेताओं और कार्यकर्ताओं को फोड़कर अपने पक्ष में किया था। भाजपा की यह शिकायत लेकर एकनाथ शिंदे को अमित शाह के पास तक जाना पड़ा था। ऊपर से हस्तक्षेप के बाद ही दोनों दलों की ओर से हो रही तोड़-फोड़ का सिलसिला रुका और गठबंधन कर चुनाव लड़ा। मौजूदा स्थितियों में 50 पार्षदों वाली भाजपा को विपक्ष में बैठने की नौबत आ सकती है।

उत्तर प्रदेश में राजभवन अब 'जन भवन' के नाम से जाना जाएगा

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ: प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आधिकारिक आवास अब 'जन भवन' के नाम से जाना जाएगा। बुधवार को राजभवन का नाम बदलकर तत्काल प्रभाव से 'जन भवन' कर दिया गया।

औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने और शासन को जन-केंद्रित बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्यपालों के आधिकारिक आवासों के नामकरण के मानकीकरण के संबंध में पिछले वर्ष नवंबर में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। राजभवन शब्द में राजशाही और गुलामी की मानसिकता प्रतिध्वनित होने पर देशभर के राजभवनों के नाम बदलकर 'लोक भवन' किया जा रहा है।

निर्देशों के तहत उत्तर प्रदेश के राजभवन का नाम बदलकर भी 'लोक भवन' होना चाहिए था लेकिन वर्ष 2017 में बने नए मुख्यमंत्री सचिवालय भवन का नाम 'लोक भवन' पहले से होने के कारण अब तक राजभवन के नए नाम को लेकर कवायद चल रही थी। इस संबंध में बुधवार को जारी निर्देश के तहत राज्यपाल का आधिकारिक आवास तत्काल प्रभाव से सभी शासकीय व वैधानिक कार्यों में 'जन भवन' के नाम से ही संबोधित किया जाएगा।

नेहरू ने पश्चिम से प्रभावित होकर गढ़ी नीतियां, मोदी ने बदल दी स्थिति : शाह

- कहा, पश्चिमी नीतियों पर यू-टर्न का काम तेजी से चल रहा है
- कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक के समारोह में गिनाई उपलब्धियां

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के समय जब रक्षा, विदेश, व्यापार और शिक्षा नीति पश्चिमी देशों के विचारों से प्रभावित होकर बन रही थी, तब गीता प्रेस ने कल्याण पत्रिका के माध्यम से बड़ी भूमिका निभाई। कहा कि कल्याण पत्रिका के हिंदू संस्कृति अंक में हिंदू धर्म, दर्शन, आचार-विचार, कला संस्कृति को जनता के सामने रखा। पत्रिका के शताब्दी वर्ष पर इन पश्चिमी नीतियों पर यू-टर्न का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से चल रहा है। 11 वर्ष में कई काम हुए हैं।

गृह मंत्री बुधवार को यहां स्वर्गाश्रम स्थित गीता भवन में गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के सौ साल पूरे होने पर शताब्दी अंक का विमोचन करने उत्तराखंड पहुंचे। अमित शाह ने कहा कि औरंगजेब ने हिंदू धर्मस्थल तोड़ने का काम किया। मोदी सरकार ने साढ़े पांच सौ वर्ष बाद रामलला को अपमानजनक स्थिति से बाहर निकालकर भव्य राम मंदिर बनाया। 16 बार मंदिर को तोड़ा, यह फिर बना। आज हम सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष मना रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा, सात्विक संगठन शोरगुल और पैसों के प्रदर्शन से नहीं बनता है। सनातन की रक्षा शोरगुल से नहीं, शास्त्र से ही हो सकती है।

गीता भवन में गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ● सूचना विभाग

यह भी बोले शाह

- कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया।
- केदारनाथ बदरीनाथ धाम सहित 35 से अधिक तीर्थों में काम हो रहे हैं।
- अंग्रेजों के समय ले जाई गई 642 से अधिक मूर्तियों को वापस लाकर फिर स्थापित किया गया।
- मातृ भाषा में शिक्षण का अब विरोध नही हो रहा।

एएमएमके के लौटने से राजग और मजबूत होगा : गृह मंत्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि टीटीवी दिनाकरण के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) राजग में लौटने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग आगामी चुनावों में राजग को ''आशीर्वाद'' देने के लिए तैयार हैं ताकि राज्य विकास और समृद्धि के नए शिखर तक पहुंचे। बता दें कि यह पार्टी पिछले साल सितंबर में राजग से अलग हो गई थी। दक्षिण और मध्य तमिलनाडु में इसका अच्छा-खासा प्रभाव है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अगले दिन ही नितिन नवीन की मैराथन बैठक

देशभर के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और शिव प्रकाश (दाएं) ● आइएएनएस

- अध्यक्ष ने पार्टी को बूथ एवं मंडल स्तर पर सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने पर दिया जोर
- चुनावी राज्यों में तैयारियों की समीक्षा की, राज्य पदाधिकारियों ने दी विस्तृत रिपोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: पदभार संभालने के अगले ही दिन और चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति के बाद भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को देशभर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। लगभग आठ घंटे चली बैठक में नवीन ने जमीनी स्तर पर पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और भाजपा शासित राज्यों में सरकार व संगठन के बीच समन्वय पर जोर दिया। राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद थे।

सूत्रों के मुताबिक, पार्टी पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक में ही नितिन नवीन ने प्राथमिकताएं तय कर दीं। बैठक में महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन की रिपोर्ट भी पेश की गई। उन्होंने खासतौर पर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। नवीन ने बूथ इकाई व मंडल इकाई को और अधिक सर्वस्पर्शी एवं सर्वव्यापी बनाने को कहा। बंगाल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल, जहां अगले तीन महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने हैं, के प्रदेश अध्यक्षों और संगठन सचिवों से उन्होंने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इन राज्यों के पदाधिकारियों ने चुनाव तैयारियों पर विस्तृत रिपोर्ट दी। भाजपा की ओर जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, बैठक में सभी पदाधिकारी असम में तीसरी बार और बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के प्रति आश्वस्त थे। इसी तरह तमिलनाडु और पुडुचेरी में राजग की सरकार का आना तय है। वहीं, केरल में भाजपा अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराएगी। नवीन ने साफ किया कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं हैं, उन्हें चुनावी राज्यों में पार्टी के काम के लिए तैयार रहना होगा। बैठक में जी-राम-जी को लेकर कांग्रेस की नकारात्मक राजनीतिक का काउंटर करने के लिए भाजपा की ओर से चलाए जा रहे अभियान पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

फिर रामलला के दर्शन से कतरा गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी

जासं अयोध्या : राम मंदिर व हिंदुत्व के मुद्दे पर अक्सर सदन में सत्तासीन एनडीए के प्रमुख घटक दल भाजपा को घेरने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व रायबरेली सांसद राहुल गांधी फिर अयोध्या आने और रामलला के दर्शन से कतरा गए हैं। नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जयंती के दिन 23 जनवरी को रक्षा मामलों की 31 सदस्यीय संसदीय समिति के सदस्य तो रामनगरी आ रहे हैं, परंतु उनमें राहुल गांधी नहीं सम्मिलित होंगे। राहुल भी उस संसदीय समिति का हिस्सा हैं और वह सितंबर 2024 में गठित समिति के सदस्य बनाए गए थे। संसदीय समिति के सदस्यों का अयोध्या में रामलला के दर्शन व छावनी क्षेत्र में भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

जन्मभूमि पर भव्य-दिव्य राम मंदिर बन कर तैयार हो जाने और इसमें रामलला के भव्य विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के बाद से अब तक दो वर्षों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बड़े नेता, खिलाड़ी, फिल्मी हस्तियां व विभिन्न क्षेत्रों में ख्यातिलब्ध लोगों ने अयोध्या पहुंच राम मंदिर में दर्शन-पूजन किया है, इनमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे हैं, परंतु सोनिया गांधी के परिवार के किसी सदस्य ने अब तक रामलला के दर्शन नहीं किए हैं। गत दिनों रक्षा मामलों की 31 सदस्यीय संसदीय समिति की अयोध्या यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ तो समिति का सदस्य होने के नाते राहुल गांधी का भी आगमन स्वाभाविक माना जा रहा था, लेकिन अब तक उनके आगमन की कोई सूचना जिला प्रशासन को भी नहीं मिली है। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डा. अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि संसदीय समिति तो आ रही है, परंतु राहुल गांधी के आगमन की कोई जानकारी नहीं मिली है। राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के समय भी सोनिया गांधी व राहुल को श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रण भेजा था, परंतु गांधी परिवार ने दूरी बनाए रखी।

राहुल गांधी ● फाइल फोटो

रामनगरी में 23 जनवरी को आने वाली रक्षा मामलों की 31 सदस्यीय संसदीय समिति में नहीं आ रहे राहुल गांधी

मुगल व ब्रिटिश चले गए, भाजपा वाले भी चले जाएंगे

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब आप किसी संगठन में काम करते हैं तो सर्वप्रथम आपका काम उस संगठन की मजबूती के लिए प्रयास करना होना चाहिए। आप कांग्रेस के योद्धा हैं और उसी तरह ही कार्य करना है। जिस तरह देश से मुगल और ब्रिटिश चले गए, एक दिन भाजपा वाले भी चले जाएंगे। राहुल ने बुधवार को हरियाणा और उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में यह बात कही। राहुल ने आरोप लगाया कि वर्ष 2014 में भाजपा की सरकार बनाने में विदेशी ताकतों का हाथ था। वर्तमान केंद्र सरकार भी विदेशी ताकतों के हाथों खेल रही है।

विधान मंडलों में वर्ष में न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित करेंगे : ओम बिरला

- 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का समापन, छह संकल्प लिए गए
- लोस अध्यक्ष बोले, सभी विधानसभाओं को एक डिजिटल प्लेटफार्म पर लाएंगे

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि राज्यों के विधानमंडलों में एक वर्ष में न्यूनतम 30 बैठकें सुनिश्चित की जाएंगी। डिजिटल प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग से सांसदों और विधायकों की क्षमता का संवर्धन किया जाएगा। इससे विधायिकाओं में होने वाली बहस व चर्चाओं में जनप्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। 2026 में ही लोकसभा में एआइ टूल्स व प्रौद्योगिकी को विकसित किया जाएगा। हम सभी विधानसभाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाएंगे। लोकसभा इस वर्ष माडल यूनिफार्म रूल्स तैयार करने की दिशा में काम कर रही है जिससे विधायी प्रक्रिया को और प्रभावी व जन उपयोगी बनाया जा सकेगा। इसके लिए यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में गठित समिति ने काम शुरू कर दिया है। राज्यों को इन रूल्स को लागू करने के लिए इन्हें अपने विधानमंडल से पारित कराना होगा। 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में ओम बिरला ने बताया, सम्मेलन में छह संकल्प लिए गए हैं।

शंकराचार्य संबंधी नोटिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्रशासन से किया सवाल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज : प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य लिखने को लेकर मिले नोटिस पर जगदगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रुख कड़ा है। उनकी ओर से नोटिस का जवाब मेला प्रशासन को भेज दिया गया है। साथ ही प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर उन्हें नोटिस देने के औचित्य के बारे में पूछा गया है। कहा गया है कि किस आधार पर उनकी ओर से यह नोटिस दिया गया है? अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि उचित जवाब नहीं मिलने पर मेला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ वह मानहानि का केस करेंगे। वहीं, बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने उनके शिविर पहुंचे। माता प्रसाद पांडेय ने अविमुक्तेश्वरानंद का आशीर्वाद लिया और कहा कि मौनी अमावस्या पर संतों की पिटाई करना बेहद निंदनीय है। यह संत समाज का अपमान है। भाजपा सरकार संतों और सनातन धर्मावलंबियों का सम्मान नहीं करती। प्रयाग में संतों को पीटा जा रहा है। काशी में मंदिर तोड़ रहे हैं। सपा पूरी तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना के दूसरे दिन ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की थी। उन्होंने भी इस घटना की निंदा की थी। कहा कि माघ मेले में हुई घटना को विधानसभा में उठाया जाएगा। इसके पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला क्षेत्र में 'गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा' निकाली।

जगद्गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

- सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर अविमुक्तेश्वरानंद ने नोटिस देने के औचित्य के बारे में पूछा
- जगद्गुरु से मिले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, कहा-पिटाई करना निंदनीय

अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ है, उन्होंने तो अन्याय किया : जगद्गुरु रामभद्राचार्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन विवाद को लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अन्याय उनके (स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद) साथ नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने ही अन्याय किया है। अविमुक्तेश्वरानंद अभी जगद्गुरु ही नहीं बने हैं। गंगा तट तक रथ से नहीं जाया जाता है। मैं भी संगम में पैदल ही जाता हूं। रामभद्राचार्य बुधवार को यहां मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पिता स्व.हाकिम सिंह तोमर द्वारा रचित पुस्तक 'बोधः कर्तव्य बोध में चिंतन की दिशा'' का विमोचन करने पहुंचे थे।

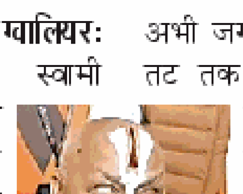

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ● नईदुनिया

अधिकारियों के साथ निश्चलानंद से मिले सतुआ बाबा: जगद्गुरु संतोषाचार्य सतुआबाबा ने बुधवार की रात पुरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद से उनके शिविर में मुलाकात की। सतुआ बाबा के साथ अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था डा. अजय पाल शर्मा व मेला प्रशासन के कई अधिकारी थे। लगभग एक घंटा वार्ता चली। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर चल रहे विवाद के बीच इंटरनेट मीडिया पर बटुकों की पिटाई का फर्जी फोटो बनाकर प्रसारित किया गया है। पुलिस ने खंडन करते हुए कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस का कहना है कि फेसबुक पर दीपक मुकेश तिवारी मेजा एट इलाहाबाद के नाम से बनाई गई प्रोफाइल के जरिये फर्जी फोटो पोस्ट की गई। फोटो एआइ से बनाया गया है।

उदयनिधि की टिप्पणी में मालवीय के खिलाफ एफआइआर की गई रद

मदुरै, प्रेट्र : मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने भाजपा नेता अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद कर दिया है। मालवीय पर तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा ''सनातन धर्म'' पर दिए गए बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप था। पीठ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 'नफरत फैलाने वाला भाषण'' देने वालों को छूट क्यों मिल जाती है, जबकि उन पर प्रतिक्रिया देने वालों को कानून का सामना करना पड़ता है। भाजपा ने उदयनिधि को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। मालवीय की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस एस श्रीमती ने कहा, मामले को जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा। इसलिए, तिरुचिरापल्ली नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआइआर रद की जाती है।

विनिवेश और संपदा मौद्रीकरण पर करना होगा फोकस

बजट 2026-27 बिगुल

राजीव कुमार ● जागरण

- आयकर में राहत और जीएसटी सुधारों से टैक्स संग्रह की वृद्धि दर में आई कमी, अब राजस्व के मोर्चे पर चुनौती
- बजट में पांच से सात लाख रुपये कमाने वाले निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए की जा रही राहत की आस
- इस वर्ग को निश्चित किस्त पर मकान की सुविधा जैसी सहूलियत देने से बढ़ेगी खपत, इकोनमी को होगा लाभ

नई दिल्ली : यूं तो पिछले साल ही केंद्र सरकार ने बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने की घोषणा कर दी थी और उसके बाद जीएसटी सुधारों ने जनता पर पड़ने वाली महंगाई की मार को भी कम कर दिया है। इसका असर सरकार के राजस्व पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि, अभी भी पांच से सात लाख रुपये कमाने वाले निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए बजट में राहत की आस लगाई जा रही है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ सके जो अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो। यानी ऐसी राहत जिससे वह किफायती मकान खरीद सकें और जीवनस्तर पर बदलाव ला सकें।

जानकर मानते हैं कि शहर में रहने वाले ये निम्न मध्यम वर्ग सबसे अधिक आकांक्षी है और इन्हें मकान खरीदारी में ब्याज दरों पर अतिरिक्त छूट या सरकार की तरफ से एक निश्चित किस्त पर मकान की सुविधा, इलाज के लिए सब्सडी वाले हेल्थ इंश्योरेंस और रेल, बस व मेट्रो में सवारी के लिए कम दर पर सालाना एकमुश्त भुगतान की सुविधा मुहैया कराई जाए तो अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलेगा। पर इसके साथ ही राजस्व बढ़ोत्तरी के लिए विनिवेश और मौद्रीकरण पर ध्यान देना होगा। डेलाइट के पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर) एमएस मणि कहते हैं, 'बजट का फोकस उपभोग बढ़ाने पर होना चाहिए, ताकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिले और उससे टैक्स का संग्रह बढ़ सके।'

राजस्व बढ़ाने की चुनौती : चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार ने इनकम टैक्स के साथ जीएसटी की दरों में भी कटौती कर राहत देने का काम तो किया, लेकिन इससे चालू वित्त वर्ष में टैक्स से मिलने वाले राजस्व की बढ़ोतरी दर प्रभावित हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़ोतरी दर सात प्रतिशत से अधिक थी जो चालू वित्त वर्ष में चार प्रतिशत के पास है। भारत में टैक्स संग्रह जीडीपी का लगभग सात प्रतिशत है जबकि चीन में यह प्रतिशत 20 तो वियतनाम में 16 प्रतिशत है। तभी बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस और एचडीएफसी बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता दोनों इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वैश्विक उथल-पुथल और अमेरिकी टैक्स की वजह से कारपोरेट के मार्जिन पर दबाव है। इनकम टैक्स छूट की सीमा 12 लाख करने से लगभग एक करोड़ टैक्सपेयर्स इस दायरे से बाहर चले गए। जानकारों का कहना है कि जीएसटी कम करने से बढ़ने वाली खपत से टैक्स संग्रह तो बढ़ेगा, लेकिन इसमें छह माह का समय लगेगा।

20 एकड़ से अधिक कृषि भूमि रखने वालों को कर दायरे में लाएं : नंदा

ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार अपने राजस्व को कैसे बढ़ाएगी। पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल किया नहीं जा सकता है। राजनीति इतनी तीखी चल रही है कि कोई भी सरकार या दल कृषि से होने वाली आय को टैक्स के दायरे में नहीं लाएगी। हालांकि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट आफ इंडिया (आइसीएआइ) के प्रेसिडेंट चरनजोत सिंह नंदा कहते हैं, '20 एकड़ से अधिक जमीन पर खेती करने वालों को टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, हमने सरकार से यह सिफारिश की है।' हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों पर नजर डालें तो ऐसा संभव होता नहीं दिखता है।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

मोनेटाइजेशन बन सकता है राजस्व जुटाने का प्रमुख जरिया

टैक्स बढ़ाने के लिए विनिवेश और संपदा के मौद्रीकरण (मोनेटाइजेशन) का रास्ता मुख्य रूप से दिखता है। हालांकि पिछले तीन साल से इस दिशा में सरकार को कुछ खास सफलता हाथ नहीं लगी है। वहीं, सब्सिडी के मद में सालाना 4.5 लाख करोड़ के खर्च की भी समीक्षा की जा सकती है। मदन सबनवीस कहते हैं, 'विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के तहत सरकार को इस साल आयात शुल्क में कटौती करनी होगी, इसलिए टैक्स के फ्रंट पर तो बजट में राहत मुश्किल है, खाद के मद की 1.7 लाख करोड़ की सब्सिडी में राहत देखने को मिल सकती है। मुफ्त के राशन की स्कीम में भी कोई बदलाव नहीं होगा। विनिवेश की जगह सरकार का मुख्य फोकस संपदा के मौद्रीकरण पर रहेगा।'

" 50 लाख की आय से सरकार का सरचार्ज शुरू हो जाता है। इस सीमा को बढ़ाकर 75 लाख किया जाना चाहिए। अभी 50 लाख से एक करोड़ की आय पर 10 प्रतिशत का सरचार्ज लगता है। टीडीएस नहीं देने और इनकम टैक्स नोटिस का जवाब नहीं देने पर उसे अपराध नहीं माना नहीं जाना चाहिए।

चरनजोत सिंह नंदा, प्रेसिडेंट, आइसीएआइ

वित्तीय मजबूती के लिए बजट में सरकार का फोकस निश्चित रूप से विनिवेश और संपदा के मौद्रीकरण पर होगा। अगले वित्त वर्ष में नामिनल जीडीपी की विकास दर अधिक होने से टैक्स संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी। "

साक्षी गुप्ता, मुख्य अर्थशास्त्री, एचडीएफसी बैंक

एक नजर में

देश में परिचालन बंद करने संबंधी खबरें गलत : वनप्लस

नई दिल्ली : वनप्लस इंडिया ने भारत में अपने परिचालन को बंद करने से जुड़ी खबरों को खारिज करते हुए कहा कि आनलाइन मीडिया पर चल रही गलत जानकारी के बावजूद परिचालन सामान्य तरीके से चल रहा है। सीईओ राबिन लियू ने कहा कि हम हमेशा की तरह काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कंपनी की तरफ यह सफाई ऐसे समय आई है जब भारत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जांच का सामना करना पड़ रहा है और इससे समेकन हुआ है। (आइएएनएस)

फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 20% की

नई दिल्ली : इलेक्ट्रानिक सामानों की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्रालय ने फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का एलान किया है। ओपेन सेल और खास तरह के कंपोनेंट्स पर बीसीडी को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक पोस्ट में कहा, 'मेक इन इंडिया' नीति और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बीसीडी को 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने और ओपन सेल और दूसरे कंपोनेंट्स पर बीसीडी को घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है।' (प्रेट्र)

बैंक आफ इंडिया का शुद्ध लाभ 7.50 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली : बैंक आफ इंडिया ने बुधवार को बताया कि दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 7.5% बढ़कर 2,705 करोड़ रुपये हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के इस बैंक का शुद्ध लाभ 2024-25 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2,517 करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक की कुल आय बढ़कर 21,205 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 19,957 करोड़ रुपये थी। तीसरी तिमाही में बैंक का एनपीए घटकर सकल कर्ज का 2.26% प्रतिशत हो गया जो एक साल पहले इसी समयावधि में 3.69% था। (प्रेट्र)

अमेरिकी दादागीरी से सहमा रुपया, रिकार्ड निचले स्तर पर

डालर के मुकाबले 68 पैसे टूटकर 91.65 पर बंद हुआ, इस साल अब तक 1.50 प्रतिशत कमजोर हुई भारतीय मुद्रा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की 'दादागिरी' के खिलाफ यूरोपीय संघ की तरफ से एकजुटता दिखाने का असर पूरी दुनिया के शेयर बाजार और मुद्रा बाजार पर दिख रहा है। हालांकि, भारतीय बाजार में कुछ ज्यादा उथल-पुथल मची है। बुधवार को भारतीय रुपया डालर के मुकाबले 68 पैसे टूटकर 91.65 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बंद हुआ। इसके पहले का न्यूनतम रिकार्ड स्तर 91.14 रुपये था। जनवरी माह में रुपया ना सिर्फ 1.50 प्रतिशत कमजोर हुआ है बल्कि चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्द्धी इकोनमी के मुकाबले इसकी गिरावट ज्यादा तेज रही है।

इस गिरावट के लिए मुख्य तौर पर वैश्विक अनिश्चितता, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से भारतीय बाजार से निवेश का बाहर निकालना और भारतीय तेल कंपनियों की तरफ से डालर की बढ़ती मांग को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस बीच यह बात भी सामने आ रही है कि आरबीआइ की तरफ से रुपये को थामने के लिए कोई बहुत खास सक्रियता नहीं दिखाई जा रही है। कारण यह है कि वैश्विक अनिश्चितता में रुपये की कमजोरी निर्यातकों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगा। रुपये की कमजोरी के पीछे सबसे बड़ा कारण एफआइआइ यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय शेयरों और बांड से बाहर निकलना है, इससे बाजार में डालर की मांग बढ़ गई है। जनवरी में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से करीब 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है। इन्होंने 2025 में भारतीय बाजार से 19 अरब डालर की निकासी की थी।

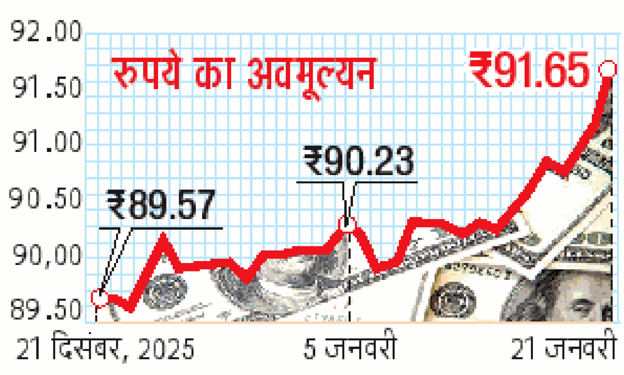

गिरावट की प्रमुख वजहें

- वैश्विक अनिश्चितता, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से भारतीय बाजार से निवेश का बाहर निकालना
- भारतीय तेल कंपनियों की तरफ से डालर की बढ़ती मांग
- आरबीआइ की तरफ से रुपये को थामने के लिए कोई बहुत खास सक्रियता नहीं दिखाना

30,000 करोड़ रुपये से अधिक निकाले हैं विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से जनवरी में

यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील से स्थिति कुछ सुधरने की उम्मीद

यूरोप में ग्रीनलैंड विवाद और व्यापार संबंधी तनाव जैसी वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं की वजह से दुनियाभर में डालर की मांग बढ़ गई है। कई विश्लेषकों ने पिछले छह कारोबारी दिनों से रुपये की गिरावट को सीधे तौर पर शेयर बाजार में चल रही गिरावट से जोड़ा है। यह स्थिति आगे भी जारी रहने की संभावना है। हो सकता है कि अगले हफ्ते होने वाले भारत-यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कुछ सकारात्मक संदेश जाए। रुपये को सबसे ज्यादा ताकत भारत और अमेरिका के बीच संभावित कारोबारी समझौते की घोषणा से मिल सकती है।

आगे भी रुपये पर दबाव बने रहने के संकेत

रुपये की कमजोरी का व्यापक प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। कमजोर रुपये से आयात महंगा होता है। खासतौर पर ईंधन और मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग के लिए जरूरी धातुओं का आयात महंगा होता जा रहा है। वैश्विक अस्थिरता से सरकारी तेल कंपनियों अभी जमकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की खरीद कर रही हैं, इससे भी भारत में घरेलू स्तर पर डालर की मांग बढ़ गई है।

आरबीआइ ने नवंबर में विदेशी मुद्रा बाजार में 9.70 अरब डालर बेचे

नई दिल्ली, रायटर : डालर के मुकाबले रुपये की गिरावट को थामने के लिए आरबीआइ ने नवंबर में विदेशी मुद्रा बाजार में 9.7 अरब डालर बेचे। आरबीआइ ने अपने मासिक बुलेटिन में कहा कि उसने नवंबर के दौरान 14.35 अरब डालर खरीदे और 24.06 अरब डालर बेचे। अक्टूबर में सेंट्रल बैंक ने बाजार में 11.88 अरब डालर बेचे थे। 21 नवंबर को भारतीय रुपया अपने उस समय के सबसे निचले स्तर 89.49 पर था, जो अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार में रुकावट और लगातार विदेशी फंड की निकासी के चलते दबाव में था। अकेले नवंबर में रुपये में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को रुपया 91.7425 के रिकार्ड निचले स्तर पर पहुँच गया, जो दो महीने में एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। ग्लोबल मार्केट में "रिस्क-ऑफ" और लोकल स्टॉक से लगातार निकासी से साउथ एशियन करेंसी को नुकसान हुआ।

40 साल से कम उम्र के युवा उद्यमियों में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा

मुंबई, प्रेट्र : 10 करोड़ डालर से ज्यादा की कंपनी की स्थापना करने वाले 40 साल से कम उम्र के युवा उद्यमियों के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। एवेंडस वेल्थ हुरून इंडिया यूथ सीरीज 2025 की के मुताबिक, भारत में ऐसे उद्यमियों की संख्या 166 है जबकि चीन में इनकी संख्या 140 है। 20 करोड़ डालर से ज्यादा कीमत की कंपनी चलाने वाले नेक्स्ट जेनरेशन लोगों की संख्या चीन में 54 है जबकि भारत में यह 35 है।

अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड के 38 साल के करण अदाणी 201 युवा उद्यमियों की सूची में सबसे ऊपर हैं। इसके बाद एल्केमी के निखिल विश्वनाथन और अपोलो हास्पिटल्स के हर्षद रेड्डी हैं। ये उद्यमी मिलकर 31 लाख करोड़ के मूल्य वाली कंपनियों का नेतृत्व करते हैं और यह जीडीपी का 11वां हिस्सा है। ये उद्यमी मिलकर 4.43 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देते हैं, जिसमें अपोलो हास्पिटलस में सबसे ज्यादा 42,497 कर्मचारी हैं।

भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनमी बना रहेगा

- आरबीआइ ने कहा-मौजूदा हालात आगे के लिए पेश करते हैं एक सुनहरी तस्वीर
- जीडीपी वृद्धि के पहले अग्रिम अनुमानों से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का चलता है पता

मुंबई, प्रेट्र : भू-राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनमी बना रहेगा। आरबीआइ के जनवरी बुलेटिन में छपे एक लेख में कहा गया कि इकोनमी की मौजूदा हालात आगे के लिए एक सुनहरी तस्वीर पेश करते हैं। 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान बताते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनमी बना रहेगा।

बढ़ी हुई अनिश्चितताओं के बावजूद 2025 में वैश्विक वृद्धि मजबूत बनी रही। 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि के पहले अग्रिम अनुमानों से भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का पता चलता है और इस वृद्धि की प्रमुख वजह घरेलू कारक हैं। लेख में आगे कहा गया है कि दिसंबर के संकेतक बताते हैं कि मांग की स्थिति अच्छी बनी रहने के साथ वृद्धि में तेजी बनी रहेगी। दिसंबर में सकल महंगाई में तेजी आई, लेकिन यह निचली सहनीय सीमा से नीचे रही। लेख में यह भी बताया गया है कि भारत ने बाहरी क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के मकसद से अपने निर्यात का विविधीकरण करने की काफी कोशिशें की हैं। लेख में कहा गया है कि साल 2025 में बड़े आर्थिक सुधार हुए, जिसमें कर ढांचे को तर्कसंगत बनाना, लेबर रिफार्म के लिए लेबर कोड लागू करना और वित्तीय क्षेत्र को विनियमन से मुक्त करना शामिल है।

सोने और चांदी में रिकार्ड तोड़ तेजी जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : रिकार्ड तोड़ तेजी का सिलसिला बरकरार रखते हुए बुधवार को देश की राजधानी में सोने की कीमतें लगभग 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गईं। दुनियाभर में सुरक्षित निवेश की होड़ के बीच चांदी 3.34 लाख रुपये प्रति किलो की नई ऊंचाई पर पहुंच गई।

सोना 6,500 रुपये या 4.24 प्रतिशत बढ़कर 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मंगलवार को, सोने ने पहली बार 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम का अहम स्तर पार किया था। चांदी की कीमतों में भी लगातार नौवें दिन जबरदस्त उछाल जारी रहा। बुधवार को यह सफेद धातु 11,300 रुपये बढ़कर 3,34,300 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (कमोडिटीज) सौमिल गांधी ने कहा, 'मजबूत निवेश मांग, आपूर्ति में दिक्कत और कमजोर रुपये के चलते दोनों धातुएं घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में काफी ज्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रही हैं।' मिराए एसेट शेयरखान के वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण सिंह ने कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच बढ़ते तनाव और महंगाई की चिंताओं से वैश्विक बाजार में हाजिर सोना दो प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है।

6,500 रुपये बढ़कर 1,59,700 प्रति 10 ग्राम हुआ सोना

11,300 रुपये बढ़कर 3,34,300 प्रति किलोग्राम हो गई चांदी

" वैश्विक जोखिम कारकों से धारणा बिगड़ने के कारण घरेलू बाजारों में अस्थिरता बनी रही। लेकिन कारोबारी सत्र के अंत में मूल्य-आधारित खरीदारी आने से शुरुआती नुकसान की थोड़ी भरपाई हो गई। **-विनोद नायर, रिसर्च हेड**, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

एक हजार से ज्यादा अंक गिरने के बाद संभला बाजार

मुंबई, प्रेट्र : भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने, वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए। उतार-चढ़ाव भरे सत्र में अपने ज्यादातर नुकसान की भरपाई करते हुए सेंसेक्स जहां 271 अंक टूटकर बंद हुआ वहीं निफ्टी में 75 अंक की गिरावट दर्ज की गई।

इटरनल के एमडी और सीईओ का पद छोड़ेंगे दीपिंदर गोयल

नई दिल्ली, प्रेट्र : जोमैटो और ब्लिंकिट का संचालन करने वाली इटरनल् ने बुधवार को कहा कि दीपिंदर गोयल समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) का पद छोड़ेंगे। उनकी जगह ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर ढींडसा एक फरवरी से समूह के नए सीईओ के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। शेयरधारकों को लिखे एक पत्र में गोयल ने कहा कि वह नए विचारों पर काम करने के लिए अपने वर्तमान पद से हट रहे हैं और अब वाइस-चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे।

दीपिंदर गोयल ने समूह सीईओ और एमडी का पद छोड़ने का कारण स्पष्ट करते हुए पत्र में लिखा, 'पिछले कुछ समय से मेरा रुझान कुछ नए विचारों की ओर बढ़ा है, जिनमें बहुत अधिक जोखिम और प्रयोग की गुंजाइश है। इस तरह के विचारों पर इटरनल जैसी सार्वजनिक कंपनी के दायरे से बाहर काम करना ही बेहतर है।' उन्होंने कहा, 'अगर ये विचार इटरनल के रणनीतिक दायरे में होते, तो मैं कंपनी के भीतर ही इन पर काम करता, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं दिख रहा है। इटरनल को अपने वर्तमान व्यवसाय के प्रति केंद्रित और अनुशासित रहने की जरूरत है।' उन्होंने अलबिंदर ढींडसा की भूमिका पर कहा, 'अब परिचालन संबंधी निर्णयों का मुख्य केंद्र 'अल्बी' (अलबिंदर) होंगे।

दीपिंदर गोयल ●

राष्ट्रीय जागरण

'सबरीमाला में मिलकर लूटी स्वामी अय्यप्पा की संपत्ति'

कोच्चि, प्रेट्र : केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामलों में कहा है कि आरोपितों ने संपत्ति की रक्षा के नाम पर मिलकर स्वामी अय्यप्पा की संपत्ति लूटी। इस आधार पर कोर्ट ने टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी मुरारी व कर्नाटक के स्वर्ण व्यापारी नागा गोवर्धन की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने 119 पन्नों के आदेश में कहा कि अभियोजन रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि आरोपितों ने देवता की संपत्ति का सुरक्षा के बहाने मिलकर गबन किया। इस सोने का प्राचीन मूल्य पैसों में नहीं आंका जा सकता, इसलिए ये अपराध अलग और जमानत के नियम के अपवाद की श्रेणी में आते हैं। कहा कि संपत्ति की रक्षा को नियुक्त लोग ही लुटेरे बन जाएं तो जमानत पर रिहाई नहीं दी जा सकती। इस बीच, कोल्लम की सतर्कता अदालत ने मुख्य आरोपित उन्नीकृष्णन पोट्टी को श्रीकोविल द्वारों से जुड़े मामले में वैधानिक जमानत दी, क्योंकि 90 दिन में आरोपपत्र दाखिल नहीं हुआ।

भारतीय सेना का असल 'ड्रोन'...

भारतीय सेना के नवाचार व अत्याधुनिक तकनीक का नया प्रयोग गणतंत्र दिवस परेड से पूर्व बुधवार को नई दिल्ली में दृष्टिगोचर हुआ। सेना के रिमाउंट वेटरनरी कोर ने चील के सिर पर निगरानी कैमरा लगा इसे असल 'ड्रोन' बना दिया है। यह प्रशिक्षित पक्षी सेना की नवीन क्षमताओं का प्रतीक हैं ● एएफपी

एक बार पत्नी को माफ किया तो फिर नहीं मांग सकते तलाक : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के केस से बरी होने के बाद पति-पत्नी सात साल तक साथ रहे। पति ने पत्नी की गलतियों को माफ कर दिया। इसके बाद फिर तलाक नहीं मांग सकते। डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा कि पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराने व प्रकरण से बरी होने के बाद पति-पत्नी लंबे समय तक साथ रह चुके हैं। ऐसे में पुराने आरोप के आधार पर तलाक मांगना स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, पति-पत्नी के लंबे समय साथ रहने से ऐसे मामलों में क्रूरता या अवैध संबंध जैसे आरोप माफ माने जाएंगे।

हल्के में मत लीजिए, एआइ ताकत के रूप में भारत अगुआ देशों में

दावोस में विश्व आर्थिक मंच के कार्यक्रम में बोलते केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ● वीडियोग्रैब

- दावोस में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री वैष्णव ने आइएमएफ की एआइ रैंकिंग को दिखाया आइना
- कहा-आइएमएफ की रैंकिंग गलत, पूर्व की कई रैंकिंग दिखा रहीं भारत का सही स्थान

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : हल्के में मत लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ के रूप में भारत दुनिया के अगुआ देशों में है। भारत पूरे एआइ स्टैक में क्षमताएं विकसित कर रहा है और वैश्विक मानक भारत को शीर्ष स्तर में दर्शाते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की एआइ रैंकिंग को आईना दिखाते हुए यह बातें कहीं। उन्होंने आइएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जार्जीवा की उन टिप्पणियों का खंडन किया, जिसमें उन्होंने भारत को एआइ मामले में दूसरे ग्रुप में रखा था। वैष्णव ने कहा कि आइएमएफ की रैंकिंग गलत है। पूर्व की कई रैंकिंग भारत का सही स्थान दिखा रही हैं।

इंटरनेट मीडिया के अनुसार, दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के कार्यक्रम के दौरान वैष्णव ने आइएमएफ प्रमुख द्वारा उपयोग किए गए मानदंड पर सवाल उठाया और एक स्टैनफोर्ड आकलन का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को एआइ क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रखा गया है। वैष्णव ने कहा- 'मुझे नहीं पता कि आइएमएफ का मानदंड क्या है, लेकिन आपका यह वर्गीकरण सही कहानी बयां नहीं करता है।'' मंत्री ने कहा कि भारत को स्पष्ट रूप से एआइ क्षेत्र में अग्रणी समूह में देखा जाना चाहिए।

वैष्णव ने भारत के एआइ में बढ़ते कदमों को बहु-स्तरीय प्रयास के रूप में पेश किया। उन्होंने कहा कि एआइ आर्किटेक्चर में पांच लेयर- एप्लीकेशन लेयर, माडल लेयर, चिप लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर और एनर्जी लेयर शामिल हैं। भारत अपनी अर्थव्यवस्था के आकार, आबादी और आइटी सेवा कंपनियों की वैश्विक उपस्थिति को देखते हुए इन पांच स्तरों पर तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने इसे देश की व्यापक आर्थिक प्रगति से जोड़ा, जोकि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सुर्खियां बटोरने वाले बड़े पैमाने के बजाय प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि भारत का तुलनात्मक फायदा एंटरप्राइज के लिए एआइ एप्लीकेशन बनाने और डिलीवर करने में है। उन्होंने कहा- ''एप्लीकेशन लेयर पर हम शायद दुनिया को सेवाओं के सबसे बड़े सप्लायर होंगे। वैष्णव की दावोस में की गई टिप्पणियां ऐसे समय आई हैं जब नई दिल्ली अगले महीने एआइ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है, जहां भारत जिम्मेदार व समावेशी एआइ पर अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने और सेक्टोरल एप्लीकेशन में घरेलू प्रगति को प्रदर्शित करने की उम्मीद कर रहा है।

भारत अगले पांच वर्षों में छह से आठ प्रतिशत की दर से विकास करता रहेगा : प्रेट्र के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि मध्यम मुद्रास्फीति और मजबूत विकास के चलते भारत अगले पांच वर्षों में छह से आठ प्रतिशत की दर विकास करेगा, वहीं नामिनल जीडीपी में 10-13 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। सीआइआइ और ईवाई द्वारा आयोजित 'भारत पर भरोसा- भविष्य पर बैंकिंग' सत्र में वैष्णव ने चीजों के सरलीकरण के महत्व को उजागर किया। उन्होंने बताया कि टेलीकाम टावर की स्थापना का औसत समय 270 दिनों से घटकर सात दिन हो गया है, जिसमें 89 प्रतिशत परमिशन तुरंत मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इरादे और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटने की आवश्यकता है। सीआइआइ के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और 2047 तक इसे कम से कम पांच गुना बढ़ाने की आवश्यकता है।

दावोस में वैष्णव ने यह भी कहा

- भारत अपने मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के कारण धीरे-धीरे दुनिया में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
- भारत 2030 तक सात नैनोमीटर और 2032 तक तीन नैनोमीटर की तकनीक विकसित कर लेगा।
- हमारी चार इकाइयां इसी वर्ष उच्च तकनीक वाले स्वदेशी चिप का उत्पादन शुरू कर देंगी।
- भारत में अब लगभग 200,000 स्टार्टअप हैं और यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है।
- 24 भारतीय स्टार्टअप चिप्स डिजाइन कर रहे हैं, जो स्टार्टअप के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और उनमें से 18 को पहले ही वेंचर कैपिटल फंडिंग मिल चुकी है।

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 22 जनवरी, 2026

कल्पमेधा

जो सत्य है, उसे निर्भीक होकर कहो, उससे व्यक्ति विशेष को कष्ट हुआ या नहीं, इस पर ध्यान मत दो।
– स्वामी विवेकानंद

पर्यावरण की परवाह

देश में अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खनन तथा इसके पर्यावरण पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ये तर्क सही हो सकते हैं कि खनन गतिविधियां विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन क्या पर्यावरण की कीमत पर विकास की राह तलाशना उचित है? पिछले कुछ दिनों से चर्चा में रहे अरावली पर्वत–शृंखला के मसले को लेकर यह बहस जोर पकड़ रही है कि अगर कोई प्राकृतिक संरचना किसी क्षेत्र के लिए जीवन–धारा और सुरक्षा दीवार के रूप में खड़ी है, तो क्या उसका संरक्षण जरूरी नहीं है! हाल के वर्षों में अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियां बढ़ी हैं और इससे होने वाले नुकसान को लेकर उठी आवाज की अनदेखी हुई है। यही वजह है कि बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया कि अरावली में खनन और इससे संबंधित मुद्दों की व्यापक एवं समग्र जांच जरूरी है तथा इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन से पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि आसपास की जमीन से कम से कम सौ मीटर ऊंचे हिस्से को ही अरावली पहाड़ी के तौर पर माना जाएगा। अदालत की इस नई परिभाषा के बाद यह आशंका पैदा हो गई थी कि अगर सौ मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर खनन, निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के रास्ते खुलेंगे, तो इसके बाद समूचे इलाके के पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकते हैं। क्योंकि, पहाड़ियों के बीच पांच सौ मीटर की दूरी के मानक से अरावली का बड़ा हिस्सा पर्यावरण संरक्षण से बाहर हो सकता था। हालांकि, बाद में शीर्ष अदालत ने अपने इस फैसले को स्थगित करते हुए कहा था कि इस मामले में कुछ गंभीर अस्पष्टताओं का समाधान जरूरी है। अब न्यायालय ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर खनन क्षेत्र के विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया है, ताकि विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सके। मगर यह पहलू भी महत्त्वपूर्ण है कि विशेषज्ञों की समिति बिना किसी दबाव और निष्पक्षता से अध्ययन कर अपने सुझाव सामने रखे। इस चिंता को दूर करने के लिए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि यह समिति उसके निर्देशन और निगरानी में कार्य करेगी।

दरअसल, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से लेकर दिल्ली तक के सैकड़ों किलोमीटर इलाके में फैली अरावली पर्वत–शृंखला को उत्तर भारत में पर्यावरण को संतुलित रखने की लिहाज से एक प्राकृतिक दीवार के रूप में देखा जाता है। मगर पिछले कुछ वर्षों से अरावली क्षेत्र में जिस तरह पत्थर, रेत और अन्य संसाधनों की पूर्ति के लिए खनन गतिविधियां बढ़ी हैं, उससे इलाके के पर्यावरण पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अरावली के आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर को सामान्य बनाए रखने, रेगिस्तान बनने से रोकने और लोगों की आजीविका बचाने के लिए इसका संरक्षण जरूरी है। इसे न केवल पर्यावरणीय, बल्कि भूगर्भीय और जलवायु संबंधी महत्त्व की दृष्टि से भी देखने और मूल्यांकन करने की जरूरत है। अगर अरावली की पहाड़ियों में अवैध और अवैज्ञानिक तरीके से खनन पर रोक नहीं लगाई गई, तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं।

व्यवस्था पर सवाल

बेहतर स्वास्थ्य के लिए उपचार की किफायती और सुलभ सुविधाएं मनुष्य की बुनियादी जरूरत है। इनमें चिकित्सक की उपलब्धता, समय पर सस्ते दामों में दवाएं मुहैया कराना और आपातकालीन देखभाल शामिल हैं, ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रहे। अगर व्यवस्था में इन जरूरी सुविधाओं का अभाव हो, तो विकास के दावों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। देश की राजधानी दिल्ली की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। दिल्ली सरकार की जन्म और मृत्यु पंजीकरण पर वार्षिक रपट के मुताबिक, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय राजधानी में एक लाख उनचालीस हजार से अधिक लोगों की मौत हुई, जिनमें से 34.84 फीसद लोगों की मौत घर पर ही हुई। सवाल है कि आज के दौर में जब लोग मामूली तकलीफ होने पर भी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों का रुख करते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में मौत घर पर ही हो जाती है? जाहिर है, इसके पीछे स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और आपात स्थिति में चिकित्सा सहायता समय पर न मिलना भी एक बड़ा कारण हो सकता है।

इस बात पर गौर करना जरूरी है कि आने वाले दिनों में भारत के दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाने के दावों के बीच अगर चिकित्सा सहायता न मिलने से लोगों की जान जा रही है, तो यह पूरी व्यवस्था पर सवाल है। हैरत की बात है कि आधुनिक चिकित्सा सेवाओं का दम भरने वाली दिल्ली के लोग स्वास्थ्य को लेकर आपात परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस करते हैं। यह अक्सर देखने में आता है कि अगर कहीं सड़क पर दुर्घटना हो जाए या फिर घर पर किसी व्यक्ति की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए, तो एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है। प्राथमिक उपचार के इंतजार में कई बार मरीज की जान चली जाती है। ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि किसी मरीज को अस्पताल में बिस्तर खाली नहीं होने की वजह से भर्ती नहीं किया गया, घर वापस आने पर उसकी मौत हो गई। हालांकि, कुछ मामलों में लोगों में जागरूकता की कमी भी एक कारण हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं में बरती जाने वाली लापरवाही के लिए संबंधित कर्मियों और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

शिक्षा में नवाचार की चुनौतियां

दावा किया जाता है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और नवाचार के मामले में भारत तेजी से उभर रहा है। शोध कार्यों में भी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मगर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की राह अब भी कई तरह की चुनौतियों से घिरी है।

सुरेश सेठ

भारत में बदलाव और विकास को रफ्तार देने के लिए नवाचार एक अहम पहलू है। इस समय कृत्रिम मेधा के माध्यम से भारत सबसे अग्रणी होने का प्रयास कर रहा है। इंटरनेट की शक्ति को 6जी से आगे ले जाने की कोशिश हो रही है और हर पुराने तरीके को कृत्रिम मेधा की सहायता से बदलने की पहल हो रही है। दावा किया जाता है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और नवाचार के मामले में भारत तेजी से उभर रहा है। शोध कार्यों में भी देश किसी से पीछे नहीं है। पेटेंट की बात की जाए तो इसके लिए उद्यम और प्रौद्योगिकी में हम लगातार नए अन्वेषण कर रहे हैं। पेटेंट मामले में भारत दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के मामले में दावा किया जाता है कि हम शीर्ष देशों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। मगर शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार की राह अब भी कई तरह की चुनौतियों से घिरी हुई है।

वैश्विक नवाचार में जो मुकाबला होता है, उसमें भारत ने लगातार अपनी बढ़त बनाई है और वह 90वें पायदान से तीसवें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के भावी प्रौद्योगिकी मिशनों में भी इसका विस्तार करने और सार्वजनिक क्षेत्र में कृत्रिम मेधा के विकास का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसके लिए शिक्षा में जो परिवर्तन होना चाहिए, वह अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षा परिसरों में जो नवाचार दिखाई देना चाहिए, वह भी नहीं दिखाई देता। निजी क्षेत्र ने विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों में भारी निवेश किया है। पंजाब को ही लें। इस राज्य में तीन मुख्य विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालय जरूर खुल गए हैं, लेकिन उनमें विद्यार्थियों की कमी तो है ही, वहीं सटीक पाठ्यक्रमों का अभाव भी नजर आता है। यहां कहीं नवाचार नहीं दिखाई देता है।

केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया था। इसमें देश की विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को एक साथ मिला कर सीधा रास्ता निकालने की कोशिश की गई थी। अब इस अभियान में भी नवाचार की घोषणा शिक्षा मंत्री ने की है। शिक्षा क्षेत्र में बड़े सपने देखने के साथ भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में भी नई बुलंदियों को छूना चाहता है। वह अमेरिका या रूस के मुकाबले किसी भी तरह पीछे नहीं रहना चाहता। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में विकास की अब भी बहुत गुंजाइश है। वैसे मुद्दे की बात यह है कि शिक्षा के सभी पुराने ढर्रे अब बदले जाने चाहिए।

विज्ञान की समझ हर विद्यार्थी में हो, तभी शिक्षा में विकास के सपने पूरे हो सकेंगे। मगर इन सबके लिए पूंजी चाहिए। नीति आयोग यह कहता है कि कम से कम छह फीसद व्यय शिक्षा के विकास पर होना चाहिए, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद और विकास की बुलंदियों को छू लेने के दावों के बावजूद देश ने कभी भी सकल घरेलू उत्पाद में से छह फीसद शिक्षा पर खर्च नहीं किया। हमेशा यह खर्च आंकड़ों में दिखाया जाता है, फीसद में नहीं, ताकि आबादी के लिहाज से तेजी से बढ़ते हुए देश में शिक्षा में बदलाव की धीमी गति को लेकर कोई उलझन पैदा न हो। हम शिक्षा के विकास में कृत्रिम मेधा के जरिए विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं। सरकार का कहना है कि कृत्रिम बुद्धिमता

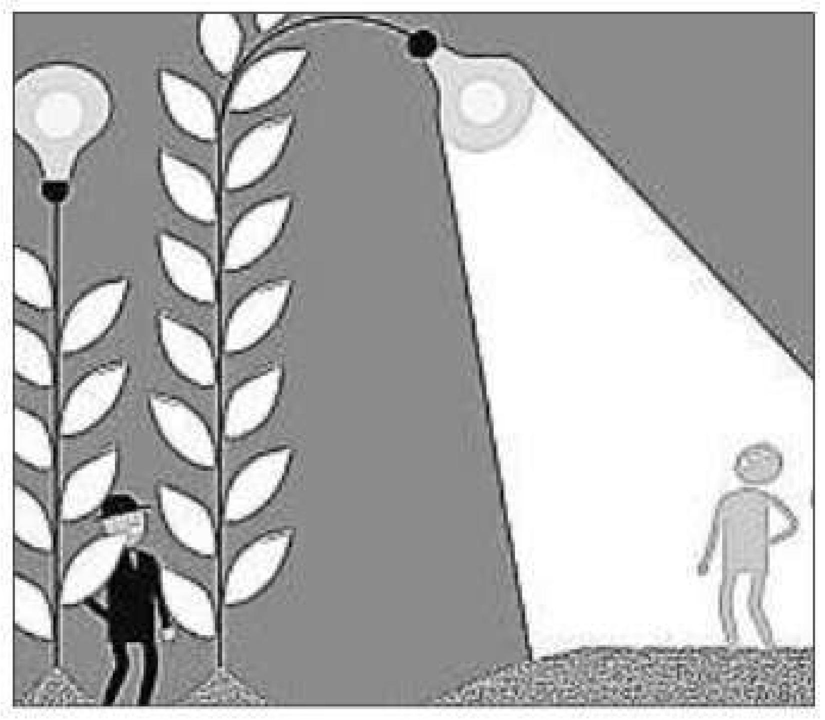

नैतिक, पारदर्शी और डेटा गोपनीयता सिद्धांतों पर आधारित हो। इसके अलावा यह समावेशी और मितव्ययी हो, लेकिन सच तो यह है कि मितव्यय के नाम पर धन का आबंटन अब भी कम है, लेकिन न तो यह समावेशी हो सका है और न ही वहनीय। सवाल यह है कि अगर

> **उच्च शिक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी कला और साहित्य क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शोध की रुचि कम ही नजर आती है। हम कृत्रिम मेधा से नवाचार की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा शोध इस क्षेत्र की बुलंदियों की ओर जाता नहीं दिख रहा। सवाल है कि कृत्रिम मेधा से नवाचार के लिए देश में कितने प्रशिक्षण संस्थान बनाए गए हैं। कितने शिक्षकों को हमने नई शिक्षा विधि में निपुण बनाया है? पुरानी नौकरियां अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि दफ्तरों में सब काम कागज रहित होता जा रहा है। ऐसे में नवाचार को बढ़ावा देने के गंभीरता से प्रयास किए जाने की जरूरत है।**

समावेशी, रोजगारपरक और अन्वेषणपूर्ण शिक्षा को गांव–गांव तक पहुंचाना है, तो इसके लिए उद्यम कहां है? अगर आज भी यह रपट आती है कि भारत में हजारों प्राथमिक विद्यालयों में एक–एक अध्यापक कई कक्षाओं को संभाल रहे हैं, तो शिक्षा में नई तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टि को आत्मसात करने का लक्ष्य कब पूरा होगा? पंजाब को ही लें, आज भी यहां अधिकतर छात्र कला संकायों की ओर जा रहे हैं। जबकि नई शिक्षा नीति यह कहती है कि शुरू से लेकर उच्च स्तर तक नई पीढ़ी कला और साहित्य के साथ–साथ विज्ञान एवं तकनीक का भी अध्ययन करे।

दूसरी ओर आलम यह है कि स्कूलों में दाखिले का फीसद जरूर बढ़ गया है, लेकिन दसवीं तक आते–आते विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। इसकी वजह है–परिवारों की आर्थिक असुरक्षा और रोजगार की अनिश्चितता। वहीं देश की युवा पीढ़ी में काम करने की इच्छा लगातार घट रही है, तो इसका कारण उदारता से बांटी गई रेवड़ियां भी हैं। अजब विडंबना है कि एक ओर देश आर्थिक शक्ति बनता दिख रहा है और हम भविष्य में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का दावा कर रहे हैं। आजादी के शतकीय महोत्सव 2047 तक हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। दूसरी ओर युवा पीढ़ी को अनुकंपा के जरिए धीरज रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे विरोधाभास नहीं तो और क्या कहा जा सकता है।

उच्च शिक्षा में ज्यादातर विद्यार्थी कला और साहित्य क्षेत्र में शोध करना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शोध की प्रवृत्ति नहीं बढ़ रही। हम कृत्रिम मेधा से नवाचार की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा शोध इस क्षेत्र की बुलंदियों की ओर जाता नहीं दिख रहा। हम कृत्रिम मेधा से नवाचार की बात जरूर करते हैं, लेकिन सवाल है कि कितने प्रशिक्षण संस्थान हमने इसके लिए बनाए हैं। कितने अध्यापकों को हमने नई शिक्षा विधि में निपुण बनाया है? नई शिक्षा नीति तो कहती है कि युवा पीढ़ी के प्रशिक्षण को किताबों के साथ–साथ यथार्थ से भी जोड़ा जाना चाहिए, मगर वास्तव में ऐसा हो नहीं पा रहा है। पुरानी नौकरियां अब खत्म हो रही हैं, क्योंकि दफ्तरों में सब काम कागज रहित होता जा रहा है। हालांकि अब भी अधिकतर संस्थानों में नौकरियों का वही पुराना ढर्रा है। दूसरी ओर चिकित्सा और इंजीनियरिंग की डिग्रियां अब युवा पीढ़ी के लिए अंतिम विकल्प नहीं रह गई हैं।

इसमें दोराय नहीं कि अब कृत्रिम मेधा में दक्ष पीढ़ी तैयार हो रही है। यही लक्ष्य भी होना चाहिए। मगर अभी तक इसमें नवाचार सतही स्तर पर ही दिखाई देता है। पाठ्यक्रमों में बदलाव नहीं दिख रहा और न ही इस दिशा में पुस्तकें लिखी जा रही हैं। अध्यापन विधि भी नहीं बदल रही। जबकि यथार्थ के धरातल पर नई पीढ़ी को खड़ा करना नई शिक्षा नीति का लक्ष्य होना चाहिए। फिलहाल इस बारे में दावे तो किए जाते हैं, लेकिन यह वास्तविक रूप से कहीं गतिमान नजर नहीं आता। अगर निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर समावेशी विकास के लिए दरवाजे खोलने हैं, तो समावेशी शिक्षण होना चाहिए। इस पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। कृत्रिम मेधा के उपयोग में आगे बढ़ने के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन हमारी उत्पादन प्रक्रिया में इसके इस्तेमाल से लागत कम होती नजर नहीं आती। कृषि क्षेत्र में तो आज भी कृत्रिम मेधा का इस्तेमाल न के बराबर है। समग्र शिक्षा अभियान में नवाचार का सपना सुंदर है, परंतु देश इस दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे में शिक्षा को नवाचार से जोड़ने के प्रयास करने होंगे।

दुनिया मेरे आगे

निजता की निधि

अमन आकाश

सूचना के इस असीमित एवं अनियंत्रित प्रवाह के दौर में हम सब सार्वजनिक प्रदर्शन को आतुर हैं। अनावश्यक रूप से हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कहां घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हमारी जीवनशैली कितनी चमक–दमक से भरी है। मसलन, कुछ विषय, जिन्हें दो दशक पहले तक निजी माना जाता था, हम अब सोशल मीडिया पर उन्हें भी सरेआम प्रदर्शित कर रहे हैं। सोशल मीडिया के शुरुआती दिनों में यह ठीक लगा, पर समय के साथ ऐसा महसूस होने लगा है कि हम कहीं तो चूक रहे हैं! डिजिटल विकास मानव सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है, पर इसी विकास ने एक ऐसी चुनौती भी सामने रख दी है, जिसकी गंभीरता को हम अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। निजता की निरंतर कमी अभी के समय की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। बीते वर्षों में तकनीक ने हमारी दुनिया को भले ही छोटा और सुविधाजनक बनाया हो, पर इसके साथ उसने मनुष्य को इतना सार्वजनिक भी कर दिया है कि उसके निजी जीवन की सीमाएं लगभग धूमिल हो चली हैं। सरल शब्दों में कहें तो आज के समय में हमने अपने शयन–कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और इसकी पहुंच पूरी दुनिया को दे रखी है। असली समस्या यह है कि अपनी इस प्रवृत्ति से हम खुश हैं!

यह विडंबना ही है कि जिस दौर में सूचना सबसे सुलभ है, उसी दौर में मनुष्य अपने बारे में उपलब्ध सूचनाओं पर सबसे कम नियंत्रण रख पा रहा है। यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि आने वाले वर्षों में निजता वही लोग सुरक्षित रख पाएंगे, जिनके पास तकनीकी अनुशासन, जागरूकता और संसाधन होंगे। आज का नागरिक अपने जीवन के अनेक हिस्सों, तस्वीरों, यात्राओं, निजी क्षणों, संबंध, विचार और भावनाओं को जाने–अनजाने में सार्वजनिक कर रहा है और इसे हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान रहे हैं। सोशल मीडिया मंच यह भ्रम पैदा करते हैं कि वे इंसान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, पर वास्तविकता यह है कि वे मनुष्य को निरंतर एक ऐसे सार्वजनिक मंच पर ले आते हैं, जहां वह अपनी निजता खुद क्षीण करता चलता है। निजी और सार्वजनिक के बीच की रेखा लगभग समाप्त हो चुकी है। घर की दीवारें अब सुरक्षा का आश्वासन नहीं देतीं। हम अपने ही हाथों अपनी गतिविधियों को दर्ज करते जाते हैं, और एक बार दर्ज हुई जानकारी हमारी इच्छानुसार मिट नहीं पाती।

> **एक समय था जब बाजार वस्तुओं पर चलता था। अब बाजार डेटा पर चलता है। यह डेटा हम स्वयं उपलब्ध कराते हैं और यही डेटा हमारी पहचान, पसंद, आदतों और हमारे व्यवहार का मानचित्र तैयार करता है। इस मानचित्र से कंपनियां अनुमान लगाती हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, किसे पसंद करते हैं और किस बात से प्रभावित होते हैं।**

क्या हमने सुविधा की तलाश में अपनी सुरक्षा गिरवी रख दी है? एक समय था जब बाजार वस्तुओं पर चलता था। अब बाजार डेटा पर चलता है। यह डेटा हम स्वयं उपलब्ध कराते हैं, और यही डेटा हमारी पहचान, पसंद, आदतों और हमारे व्यवहार का मानचित्र तैयार करता है। इस मानचित्र से कंपनियां अनुमान लगाती हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या खरीदते हैं, किसे पसंद करते हैं और किस बात से प्रभावित होते हैं। यह अनुमान कभी–कभी इतना सटीक होता है कि मनुष्य के खुद को पढ़ने से पहले उसे मशीन उसे पढ़ लेती है। सोशल मीडिया मंच हमें मुफ्त लगते हैं, पर इस मुफ्त के पीछे हमारी निजता का गंभीर मूल्य छिपा है।

आने वाले कुछ ही समय में निजता समाज में वर्ग–भेद का आधार बन जाएगी। भविष्य में समाज का एक छोटा वर्ग वह होगा, जिसकी सार्वजनिक उपस्थिति न्यूनतम होगी। उसके बारे में इंटरनेट पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध होगी। यह वर्ग न केवल अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि एक प्रकार के 'एलीट' समूह के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि उसके पास निजता नाम की दुर्लभ निधि होगी। इसके उलट समाज का एक बड़ा हिस्सा वह होगा, जिसकी डिजिटल उपस्थिति अत्यधिक होगी, जिसका जीवन खुली किताब की तरह इंटरनेट पर दर्ज होगा और समाज का यह हिस्सा पिछड़ा हुआ माना जाएगा। निजता ही आने वाले समय का नया 'स्टेटस सिंबल' या हैसियत का प्रतीक बन सकती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआइ, चेहरे से पहचान करने वाली मशीन यानी फेस–रिकग्निशन, डीपफेक जैसे उपकरण जिस गति से विकसित हो रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भविष्य में निजता की समस्या और जटिल होगी। अब किसी व्यक्ति की आवाज, तस्वीर या वीडियो का दुरुपयोग करना पहले से कहीं अधिक आसान हो चुका है। ऐसे माहौल में जो व्यक्ति अपनी जानकारी कम साझा करेगा, वही अधिक सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा अब दीवारों या तिजोरियों से नहीं, बल्कि सूचनात्मक संयम से आएगी। निजता का महत्त्व केवल किसी बात को छिपाने में नहीं है। यह मनुष्य के निर्णयों, उसके मनोविज्ञान और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा का मूल सूत्र है। जब किसी व्यक्ति के बारे में कम जानकारी उपलब्ध होती है, तभी उसके पास अपनी पहचान पर नियंत्रण होता है। निजता उसे वह स्थान देती है, जहां वह बिना दबाव, बिना भय और बिना निगरानी के सोच सकता है।

निजता की सुरक्षा की दिशा में हम अभी से कुछ बुनियादी कदम उठा सकते हैं जैसे सोशल मीडिया पर कम व्यक्तिगत जानकारी साझा करना, अपनी जगह को साझा करने को सीमित रखना, अलग–अलग एप को दी गई अनुमतियों की समीक्षा करना, पासवर्ड सुरक्षा मजबूत करना, अनावश्यक डिजिटल गतिविधियों से दूरी बनाना। निजता की रक्षा एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है। सूचना–युग में मनुष्य जितना अधिक सार्वजनिक हुआ है, उतना ही अधिक असुरक्षित भी। भविष्य का समाज वही व्यक्ति मजबूत और स्वतंत्र मानेगा, जिसकी व्यक्तिगत जानकारी उसके ही नियंत्रण में होगी। निजता अब केवल एक निजी विषय न रहकर सामाजिक, नैतिक और लोकतांत्रिक प्रश्न बनती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि हम आज से ही अपनी निजता को संचित करना शुरू करें, क्योंकि जो बातें हम सहजता से साझा करते हैं, वही भविष्य में सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती हैं।

वैचारिक संकट

बांग्लादेश में बीते कुछ वर्षों में मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी, पलायन और अब सिलसिलेवार हत्याओं ने यह साबित कर दिया है कि समस्या केवल कानून–व्यवस्था की नहीं, बल्कि गहरी वैचारिक और संस्थागत सोच की है। फिर भी अंतरिम सरकार इन घटनाओं को सामान्य आपराधिक कृत्य बता कर सांप्रदायिक पहलू से इनकार कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के खोखले आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार और लोकतंत्र की बातें करने वाली बांग्लादेश की सरकार जमीनी सच्चाई को स्वीकार करने से बचती नजर आती है। जबकि तथ्य बताते हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद न तो जल्दी गिरफ्तारी होती है, न ही पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और न्याय मिलता है। कई मामलों में स्थानीय प्रशासन की भूमिका संदिग्ध रही है। पुलिस भी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी करती है और कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से बचा जाता है। ऐसे में अल्पसंख्यकों के पास न तो राजनीतिक संरक्षण है और न ही प्रभावी प्रतिरोध की क्षमता।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

समस्या और समाधान

देश के ज्यादातर शहरी और ग्रामीण इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक गंभीर समस्या है। इससे आम लोगों के लिए जोखिम बढ़ा है। यह समस्या एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आवारा कुत्ते न केवल यातायात में बाधक बनते हैं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हैं। इनसे रेबीज होता है, जो एक खतरनाक बीमारी है। बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को काट लेने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। सड़कों पर इनसे यातायात भी प्रभावित होता है। नतीजा, अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। राज्य सरकारों को इनके कारण जख्मी हुए लोगों के मुफ्त उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए। मौत के मामले में सहायता राशि दी जानी चाहिए। आवारा कुत्तों की संख्या कम करने के लिए ठोस उपाय करने की जरूरत है। इनके लिए आश्रय स्थल बनाने होंगे। विदेश में तो इसे लेकर बहुत जागरूकता है, मगर भारत में इसका अभाव दिखता है।

– भगवानदास छारिया, इंदौर

संप्रभुता को खतरा

वेनेजुएला की संप्रभुता पर अमेरिका के नियंत्रण के बाद अब ग्रीनलैंड पर खतरा मंडरा रहा है। दुनिया में हर देश की अपनी संप्रभुता है, जिसमें असली ताकत जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों में होती है। मगर बीते कुछ समय से अमेरिका जिस तरह के हथकंडे अपना रहा है, उससे कई देशों पर संकट मंडराने लगा है। राष्ट्र की संकल्पना में संप्रभुता निहित है। भौगोलिक सीमा के भीतर आम जनता का हित ही प्राथमिक होता है। दूसरी ओर फिर से राजतंत्र जैसी भावना दिख रही है। लोकतंत्र के पर्दे के पीछे जो राजतंत्र दिख रहा है, उसे समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि उसी राजा जैसी छवि अपने भीतर उतार रहे हैं। अमेरिका को सोचना होगा कि संप्रभुता किसी एक देश विशेष पर ही लागू नहीं होती और न केवल उसी देश की जनता का ही हित प्राथमिक है, बल्कि हर देश के लोगों को गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है।

– शाहिद हाशमी, जाकिर नगर, दिल्ली

लापरवाही की परतें

'लापरवाही की अति' (संपादकीय, 20 जनवरी) पढ़ा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक कंप्यूटर इंजीनियर की मौत कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की नकामी का उदाहरण है। कोहरे में कार का गड्ढे में गिरना बेशक दुर्घटना है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौजूद तमाम प्रतिष्ठित एजंसियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और दमकल मिल कर भी एक युवक की जान बचाने में असमर्थ रहीं। यह तैयारी, संसाधन और समन्वय की कमी को भी उजागर करता है। सबसे पीड़ादायक पक्ष यह है कि युवक की जान उसके पिता के सामने गई। सवाल यह नहीं है कि कौन सी एजंसी मौके पर पहुंची, बल्कि उनके पास आवश्यक बचाव उपकरण, तकनीक और प्रशिक्षित मानव बल क्यों नहीं था? यह सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता है।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

खेल

जनसत्ता | 22 जनवरी, 2026

कोना

आस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप के दूसरे दौर में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ शाट लगाते फ्रांस के एलेक्जेंडर मुलर।

कैलेंडर

क्रिकेट

आइसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप
टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जा रहा है। लीग मैच एक फरवरी तक खेले जाएंगे।

भारत बनाम न्यूजीलैंड
रायपुर में दूसरा टी20, गुवाहाटी में तीसरा टी20, विशाखापट्टनम में चौथा टी20 और तिरुवनंतपुरम में पांचवा टी20 मुकाबला खेला जाएगा।

रणजी ट्राफी
इस अवधि में भारत के विभिन्न शहरों में रणजी ट्राफी के नाकआउट मुकाबले या अंतिम ग्रुप मैच खेले जाएंगे। दिल्ली में आज से छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा। वहीं, 29 से दिल्ली और मुंबई के खिलाफ मुकाबला खेला जाएगा।

निशानेबाजी

भारत में एशियाई राइफल/पिस्टल निशानेबाजी दो फरवरी से आयोजित की जाएगी।

टेनिस

आस्ट्रेलियाई ओपन। 22 जनवरी से 29 जनवरी। राउंड आफ 16, क्वार्टर-फाइनल और सेमी-फाइनल मुकाबले। 31 जनवरी व एक फरवरी को महिला और पुरुष एकल के फाइनल मैच।

फुटबाल

इंग्लिश प्रीमियर लीग जारी। ला लीगा और बुंडेसलीगा में स्पेन और जर्मनी की लीग के मैच इस दौरान जारी रहेंगे।

बैडमिंटन

इंडोनेशिया मास्टर्स 25 जनवरी तक खेला जाएगा। थाईलैंड मास्टर्स टूर्नामेंट जनवरी के आखिरी दिनों से शुरू होकर एक फरवरी तक चलेगा।

गोल्फ

पुरुषों की ईएचएफ यूरोपीय हैंडबाल प्रतियोगिता एक फरवरी तक डेनमार्क, नार्वे और स्वीडन में आयोजित की जाएगी।

बीता पखवाड़ा

9 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026

क्रिकेट

क्रिकेट
विजय हजारे ट्राफी
18 जनवरी को विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच खेला गया फाइनल सौराष्ट्र को हराकर विदर्भ बना चैंपियन।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट

न्यूजीलैंड का भारत दौरा
न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की शृंखला 2-1 से जीती। पहला एकदिवसीय मैच 11 जनवरी को खेला गया
भारत चार विकेट से मैच जीता।
दूसरा मैच 14 जनवरी को खेला गया। न्यूजीलैंड सात विकेट से मैच जीता।
तीसरा मैच 18 जनवरी को खेला गया। न्यूजीलैंड 41 रन से मैच जीता।

महिला प्रीमियर लीग

नौ जनवरी से शुरू हुआ। नौ जनवरी- रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को तीन विकेट से हराया। 10 - गुजराट जाइंट्स ने यूपी वारियर्स को 10 रन से हराया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराया। 11 - गुजराट जाइंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को चार रन से हराया। 12 - रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वारियर्स को नौ विकेट से हराया। 13 - मुंबई इंडियंस ने गुजरात जाइंट्स को सात विकेट से हराया। 14 - दिल्ली कैपिटल्स ने यूपी वारियर्स को सात विकेट से हराया। 15 - यूपी वारियर्स ने मुंबई इंडियंस को सात विकेट से हराया। 16 - रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजराट जाइंट्स को 32 रन से हराया। 17 - यूपी वारियर्स ने मुंबई इंडियंस को 22 रन से हराया। रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। 19 जनवरी- रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजराट जाइंट्स को 61 रन से हराया। 20 जनवरी- दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को सात विकेट से हराया।

टेनिस

एडिलेड ओपन नौ जनवरी-17 जनवरी तक। टी माचक बने विजेता।

आस्ट्रेलियाई ओपन
18 जनवरी से शुरू। पहला चरण - में यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच, स्टेफेनोस सिट्सिपास दूसरे दौर में पहुंचे। कार्लोस अल्कराज दूसरे दौर में जीते।

बैडमिंटन

इंडिया ओपन 13-18 जनवरी तक। पुरुष वर्ग में लिन चुन यी और महिला वर्ग में आन से यंग विजेता बनीं।

महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा चिंता का सबब

जनसत्ता खेल

रपट

भारतीय खेल जगत में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, पर उनके उत्पीड़न, यौन शोषण और असुरक्षित वातावरण की घटनाएं भी बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला और यूनेस्को की साल 2023 रपट के अनुसार, भारत में लगभग एक-तिहाई महिला एथलीटों ने प्रशिक्षकों से यौन शोषण या अनुचित व्यवहार का सामना किया है। वहीं, साल 2025 की रपट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून हैं, लेकिन अधिकारी इन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने या यह सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने ऐसे मामले शिकायत समितियों पर छोड़ दिए। हालांकि इन सभी मामलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है, जिससे महिला खिलाड़ियों को इन समस्याओं का सामना न करना पड़े।

ऐसे मामले न केवल महिलाओं की मानसिक स्थिति प्रभावित करते हैं, बल्कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में बाधा बनते हैं। सशक्तीकरण का अर्थ सिर्फ मैदान पर जीत नहीं, बल्कि सुरक्षित माहौल में विकास है। सरकार की अस्मिता योजना ने साल 2025 में 15 खेलों में 852 लीग आयोजित कर 70,000 महिला एथलीटों को अवसर दिए, जो साल 2024 से 17,000 अधिक है। लेकिन सुरक्षा की कमी से यह प्रयास अधूरा रह जाता है।

हाल ही में निशानेबाजी से जुड़े प्रशिक्षक अंकुश भारद्वाज पर एक नाबालिग निशानेबाज ने यौन शोषण का आरोप लगाया। एफआइआर दर्ज की गई और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने अंकुश को प्रशिक्षक पद से निलंबित कर दिया। इससे पहले भी साल 2010 में भारतीय महिला हाकी टीम की सदस्यों ने मुख्य प्रशिक्षक महाराज कृष्ण कौशिक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। कौशिक को बर्खास्त किया गया, लेकिन मामले ने दिखाया कि कैसे सत्ता के पदों पर बैठे लोग महिला खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। साल 2014 एशियाई खेलों की तैयारी के दौरान जिम्नास्टिक कोच मनोज राणा और जिम्नास्ट चंदन पाठक पर एक महिला जिम्नास्ट ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इन मामलों ने खेल संघों में आंतरिक शिकायत तंत्र की कमी को दर्शाया।

ऐसा ही मामला कुश्ती महासंघ में देखने को मिला, जब बड़े स्तर पर कुश्ती से जुड़े खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगा कर दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया। मामले ने महिला सशक्तीकरण पर प्रभाव डाला, क्योंकि कई युवा पहलवान खेल छोड़ने पर मजबूर हुईं। वर्ष 2022 में साइकिलिंग प्रशिक्षक आरके शर्मा पर स्लोवेनिया अभ्यास शिविर में एक महिला खिलाड़ी ने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया, जिसके बाद पूरी टीम को वापस बुलाया गया। साई द्वारा गठित जांच समिति की प्रारंभिक रपट में आरोपों को प्रथम द्रष्टया सही पाया गया, जिसके बाद आरके शर्मा का अनुबंध को समाप्त किया गया। साल 2021 में तमिलनाडु के ट्रैक एंड फील्ड कोच पी नागराजन पर सात महिला एथलीटों ने आरोप लगाए।

हरियाणा खेल मंत्री संदीप सिंह पर एक कनिष्ठ प्रशिक्षक ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, जिस कारण उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। फुटबाल में अंडर-17 महिला टीम के सहायक प्रशिक्षक एलेक्स एम्ब्रोस पर यूरोप दौरे में यौन शोषण का आरोप लगा। आरोप लगने के बाद अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ ने तुरंत जांच शुरू की और एम्ब्रोस को निलंबित कर नार्वे से वापस भारत बुलाया। ये मामले दिखाते हैं कि 30 फीसद से अधिक मामले यौन उत्पीड़न या बलात्कार के हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़े वास्तविकता से कम हैं।

साल 2025 की बात करें तो महिलाओं में सुरक्षा की कमी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को प्रभावित किया। आइसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान इंदौर में दो आस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एक होटल से कैफे जा रहीं थीं। तभी एक मोटरसाइकिल सवार ने उनका पीछा किया और उन्हें गलत तरीके से छुआ। हालांकि, पुलिस सख्त हुई और आरोपी पकड़ा गया। ऐसा ही एक मामला घुड़सवार खेल में भी हुआ, जहां युवतियां बातचीत के लिए गईं और उनके साथ यौन शोषण का प्रयास किया गया। यह मामला साल 2023 का है और कोर्ट पहुंचा। अन्य राज्य से जुड़ा होने के कारण मामले ने तूल नहीं पकड़ा। इन मामलों ने दिखाया कि महिलाओं की घटती सुरक्षा सशक्तीकरण को सीधे प्रभावित करती है। एथलीट सुरक्षित महसूस नहीं करतीं तो उनका प्रदर्शन गिरता है, जिसमें कई तो खेल को बीच में ही छोड़ देती हैं।

राष्ट्रीय खेल नीति साल 2025 ने एथलीट कल्याण, कानूनी ढांचा और महिलाओं की समावेशिता पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय खेल शासन के नए नियम अधिसूचित किए हैं, जो खेल संघों में महिलाओं की भागीदारी और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। सभी राष्ट्रीय खेल निकायों की समिति में शामिल होने वाले उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों में 50 फीसद महिलाएं होना अनिवार्य है। प्रत्येक खेल निकाय की कार्यकारी समिति में कम से कम चार महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां, स्वतंत्र जांच और जागरूकता जरूरी हैं, क्योंकि साल 2036 ओलंपिक मेजबानी की महत्त्वाकांक्षा में भारत सरकार को मानवाधिकार और महिला सुरक्षा को केंद्र में रखना होगा।

हार्दिक के बिना अधूरी है भारतीय टीम : आकाश

बोल

पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि इस आलराउंडर के बिना भारतीय टीम अधूरी है। भारत टी20 विश्व कप से पहले क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की शृंखला खेलेगा। विश्व कप में भारत के खिताब बचाने के अभियान में हार्दिक की भूमिका महत्त्वपूर्ण होगी। चोपड़ा ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय टीम में हार्दिक का कोई सानी नहीं है।

उन्होंने कहा, 'हार्दिक पांड्या के बिना भारतीय टीम अधूरी है। पूरी दुनिया में हार्दिक जैसा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं है। बल्ले और गेंद से वह जो कर दिखाते हैं, वैसा भारत में कोई और नहीं कर सकता। भारत भले ही अंतिम एकादश में वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव जैसे स्पिनर को शामिल करना चाहें, लेकिन फिर भी आपको नंबर आठ पर एक बल्लेबाज की भी जरुरत होगी। आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप 12 खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतार सकते।'

आकाश ने कहा, 'केवल हार्दिक ही ऐसा कर सकते हैं। वह नई गेंद से गेंदबाजी करके प्रभाव डाल सकते हैं और डेथ ओवरों में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने 2024 टी20 विश्व कप का आखिरी ओवर भी फेंका था जिसे भारत ने जीता था। इस तरह के कारनामे सिर्फ हार्दिक ही कर सकते हैं। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं मिलेगा।' चोपड़ा ने बताया कि चोट और खराब फार्म की चिंताओं के बीच भारत के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला महत्त्वपूर्ण होगी ताकि टीम संयोजन को सही किया जा सके।

आकाश ने कहा, 'न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की यह टी20 शृंखला सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। न्यूजीलैंड भी पूरी तैयारी के साथ आया है। एकदिवसीय श्रृंखला में उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को विश्राम दिया था, लेकिन यहां उनकी टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई टीम खेल रही है।'

कोहली को पछाड़कर शीर्ष पर पहुंचे डेरिल मिचेल

जनसत्ता खेल

न्यूजीलैंड के आक्रामक बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने हाल में संपन्न शृंखला में शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय सुपरस्टार विराट कोहली को ताजा आइसीसी एकदिवसीय बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान से हटा दिया। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ यह शृंखला 2-1 से अपने नाम की थी। इस तरह उसने भारतीय सरजमीं पर पहली बार एकदिवसीय शृंखला जीतकर 37 साल का इंतजार खत्म किया था। मिचेल ने इस शृंखला में दो शतक लगाए और 34 वर्षीय यह बल्लेबाज मात्र 54 वीं पारी में सबसे तेज नौ एकदिवसीय शतक पूरे करने वाले चौथे पुरुष खिलाड़ी बन गए। केवल इमाम - उल - हक (48), हाशिम अमला (52) और क्विंटन डिकाक (53) ही उनसे आगे हैं। हैमिल्टन में जन्में मिचेल अपने करिअर की शीर्ष फार्म में हैं। उन्होंने तीन मैच की शृंखला में कुल 352 रन बनाए। किसी तीन मैच की एकदिवसीय शृंखला में यह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन हैं और कुल मिलाकर यह तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। उनसे आगे केवल पाकिस्तान के बाबर आजम (2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 360 रन) और भारत के शुभमन गिल (2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 360 रन) हैं। आइसीसी ने एक बयान में कहा, '845 रैंकिंग अंक के साथ मिचेल ने कोहली (795 अंक) की जगह ली है जो अब दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। दोनों बल्लेबाजों के बाद इब्राहिम जदरान , रोहित शर्मा , शुभमन गिल और बाबर आजम मौजूद हैं।' यह दूसरी बार है जब मिचेल ने एकदिवसीय क्रिकेट में शीर्ष रैंकिंग हासिल की है। इससे पहले वह पिछले साल नवंबर में सिर्फ तीन दिन के लिए शीर्ष पर रहे थे जिसके बाद रोहित शर्मा ने उन्हें पछाड़ दिया था। भारत के खिलाफ उसकी सरजमीं पर खेले गए वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (पांच शतक) के बाद मिचेल (चार शतक) दूसरे सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। मिचेल एकदिवसीय में 54 पारियों में अब तक एक भी बार शून्य पर आउट नहीं हुए हैं, जिससे वह इस उपलब्धि की सर्वकालिक सूची में दूसे स्थान पर हैं। उनसे आगे केवल केपलर वेसल्स हैं जो 1983 से 1994 के बीच 105 एकदिवसीय पारियों में कभी भी शून्य पर आउट नहीं हुए। डेरिल मिचेल के पिता मशहूर रग्बी कोच जान मिचेल वर्तमान में इंग्लैंड की विश्व कप विजेता महिला टीम के मुख्य कोच हैं।

एकदिवसीय रैंकिंग

डेरिल मिचेल

एशिया और अफ्रीका उभरती शक्तियां

जनसत्ता खेल

फीफा विश्वकप

फुटबाल का महाकुंभ फीफा विश्व कप साल 2026 इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह विश्व कप 48 टीमों की हिस्सेदारी में खेला जाएगा। इस विस्तार का सबसे बड़ा लाभ एशिया और अफ्रीका जैसे महाद्वीपों को मिलने वाला है, जहां फुटबाल तेजी से विकसित हो रहा है। आने वाले विश्व कप में ये दोनों महाद्वीप पारंपरिक यूरोपीय और दक्षिण अमेरिकी वर्चस्व को गंभीर चुनौती देने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं।

एशिया : तकनीक, अनुशासन और आत्मविश्वास का मेल

पिछले कुछ वर्षों में एशियाई फुटबाल ने लंबी छलांग लगाई है। जापान, दक्षिण कोरिया, ईरान, सऊदी अरब और आस्ट्रेलिया जैसी टीमें अब केवल भागीदारी तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि बड़ी टीमों को हराने का माद्दा दिखा चुकी हैं। साल 2022 विश्व कप में सऊदी अरब द्वारा अर्जेंटीना को हराना और जापान का जर्मनी व स्पेन को मात देना इसका प्रमाण है।

वर्ष 2026 में एशिया से अधिक टीमें क्वालिफाई करेंगी, जिससे प्रतिस्पर्धा और मजबूत होगी। जापान की टीम अपने तेज पासिंग खेल और यूरोपीय लीगों में खेलने वाले खिलाड़ियों के कारण खतरनाक मानी जा रही है। काओरू मितोमा, ताकुफुसा कुबो और दाइची कामादा जैसे खिलाड़ी जापान की आक्रामक शक्ति हैं। दक्षिण कोरिया की उम्मीदें अब भी कप्तान सोन ह्युंग-मिन पर टिकी रहेंगी, जो किसी भी रक्षा पंक्ति को भेदने की क्षमता रखते हैं। ईरान के मेहदी तारेमी और सऊदी अरब के युवा खिलाड़ी सालेम अल-दौसारी भी एशियाई चुनौती को मजबूत बनाते हैं।

एशियाई टीमें अब शारीरिक मजबूती के साथ-साथ रणनीतिक समझ और मानसिक दृढ़ता में भी सुधार दिखा रही हैं, जो उन्हें नाकआउट चरण तक पहुंचने में मदद कर सकती हैं।

अफ्रीका : ताकत, गति और प्रतिभा का विस्फोट

अफ्रीका हमेशा से फुटबाल प्रतिभाओं की खान रहा है, लेकिन टीम के रूप में निरंतरता की कमी उसके रास्ते में बाधा रही है। हालांकि साल 2022 विश्व कप में मोरक्को का सेमीफाइनल तक पहुंचना अफ्रीकी फुटबाल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इससे पूरे महाद्वीप का आत्मविश्वास बढ़ा है।

वर्ष 2026 में अफ्रीकी टीमें और अधिक संगठित नजर आएंगी। मोरक्को, सेनेगल, नाइजीरिया, घाना और कैमरून जैसी टीमें संतुलित दल के साथ उतरेंगी। सेनेगल के सादियो माने अब भी टीम के प्रेरणास्रोत रहेंगे, जबकि नाइजीरिया के विक्टर ओसिमेन विश्व के सबसे खतरनाक स्ट्राइकरों में गिने जाते हैं। मोरक्को के अशरफ हकीमी अपनी रफ्तार और आक्रमण क्षमता से किसी भी मैच का रुख बदल सकते हैं। इसके अलावा मिस्र के मोहम्मद सलाह जैसे खिलाड़ी बड़े मंच पर हमेशा निर्णायक साबित होते हैं।

अफ्रीकी टीमों की सबसे बड़ी ताकत उनकी शारीरिक क्षमता, तेज गति और व्यक्तिगत कौशल है। यदि वे सामूहिक रणनीति और अनुशासन को बनाए रखती हैं, तो किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकती हैं।

लगता है कि फीफा विश्व कप साल 2026 केवल यूरोप और दक्षिण अमेरिका का अखाड़ा नहीं रहेगा। एशिया और अफ्रीका की टीमें अब छिपा रूस्तम नहीं, बल्कि वास्तविक दावेदार बनकर उभर रही हैं। युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास, यूरोपीय क्लबों का अनुभव और बढ़ती फुटबाल संरचना इन महाद्वीपों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आने वाला विश्व कप इस बात का गवाह बन सकता है कि वैश्विक फुटबाल का संतुलन धीरे-धीरे बदल रहा है।

एशिया के प्रमुख खिलाड़ी

काओरू मितोमा | ताकुफुसा कुबो | दाइची कामादा | मेहदी तारमी

अफ्रीका के प्रमुख खिलाड़ी

सादियो माने | विक्टर ओसिमेन | अशरफ हकीमी | मोहम्मद सालाह

खबर कोना

सीरिया के हसाकेह प्रांत में दाखिल होती सरकारी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां।

आबे की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास

तोक्यो, 21 जनवरी (एपी)।

जापान की एक अदालत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या करने का अपराध कबूल करने वाले एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी प्रसारक 'जापान ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन' ने यह जानकारी दी। इस मामले ने जापान की सत्तारूढ़ पार्टी और दक्षिण कोरिया के एक विवादास्पद चर्च के बीच दशकों पुराने करीबी संबंधों को उजागर किया। तेत्सुया यामागामी (45) ने पश्चिमी शहर नारा में जुलाई 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान भाषण दे रहे आबे की हत्या किए जाने के मामले में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।

हसीना के खिलाफ राजद्रोह मामले में सुनवाई नौ फरवरी को

ढाका, 21 जनवरी (भाषा)।

बांग्लादेश की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और 285 अन्य लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मामले में आरोप तय करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख नौ फरवरी निर्धारित की। मामले के 286 आरोपियों में से हसीना समेत 259 आरोपी फरार हैं और उन पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चल रहा है।

आंतरिक सुरक्षा व एआइ आधारित धोखाधड़ी के मुद्दों पर विचार करेगी समिति

नई दिल्ली, 21 जनवरी (ब्यूरो)।

आंतरिक सुरक्षा और कृत्रिम मेधा आधारित धोखाधड़ी उन मुद्दों में शामिल हैं, जिन्हें गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने विचार-विमर्श के लिए चुना है। लोकसभा के एक बुलेटिन में कहा गया है कि विभाग से संबंधित स्थायी समिति ने वर्ष 2025-26 के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श के लिए आठ विषयों का चयन किया है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति ने आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा और सीमा प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों, जिनमें वामपंथी उग्रवाद भी शामिल है, से जुड़े विषयों का अध्ययन करने का भी निर्णय लिया है।

आइएनएस सुदर्शिनी वैश्विक यात्रा पर रवाना

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत आइएनएस सुदर्शिनी 10 महीने की महासागरीय यात्रा पर रवाना हो गया है और इस दौरान यह पोत 22,000 समुद्री मील की दूरी तय करेगा एवं 13 देशों के 18 बंदरगाहों पर जाएगा। दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी) के फ्लैग आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने मंगलवार को कोच्चि के नौसैनिक अड्डे से आइएनएस सुदर्शिनी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो लंबी दूरी की नौकायन यात्रा 'लोकायन 26' की शुरुआत का प्रतीक है।

भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती

'प्रति व्यक्ति आय को ऊंचे स्तर तक ले जाना'

दावोस, 21 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारत आने वाले कुछ वर्ष में निश्चित रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं, अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि यह 2028 या उससे भी पहले संभव है।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के एक सत्र में यहां वैष्णव ने कहा कि चिंता का एकमात्र विषय अमीर देशों में कर्ज का पहाड़ और उनका भारत पर संभावित असर क्या होगा है।

गोपीनाथ ने कहा कि भारत के लिए चुनौती तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नहीं है बल्कि प्रति व्यक्ति आय को ऊंचे स्तर तक ले जाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि महंगाई में नरमी और मजबूत आर्थिक वृद्धि के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था अगले पांच वर्षों में वास्तविक रूप से छह-आठ फीसद और मौजूदा कीमतों पर 10-13 फीसद की दर से बढ़ती रहेगी। वैष्णव ने यहां संबोधित करते हुए अनुमति प्रक्रियाओं के सरलीकरण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दूरसंचार टावर स्थापित करने में लगने वाला औसत समय 270 दिनों से घटकर सात दिन रह गया है और 89 फीसद अनुमतियां अब तुरंत मिल रही हैं।

वैष्णव ने कहा कि पिछले एक दशक में देश में परिवर्तनकारी बदलाव हुआ है जो सुविचारित, स्पष्ट रूप से परिभाषित और बेहतर क्रियान्वयन पर आधारित है। उन्होंने बताया कि यह चार स्तंभों भौतिक, डिजिटल एवं सामाजिक अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश, समावेशी विकास, विनिर्माण एवं नवाचार और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर टिका है। वैष्णव ने कहा कि इन सभी को प्रौद्योगिकी मंच के साथ जोड़कर हमने ऐसा ढांचा तैयार किया है जिससे अगले पांच वर्ष में भारत छह से आठ फीसद की वास्तविक वृद्धि, दो से चार फीसद की महंगाई और 10-13 फीसद की बाजार मूल्य आधारित वृद्धि हासिल करेगा।

भारतीय नेताओं का मजबूत आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण अनुकूल उपायों पर जोर

नई दिल्ली, 21 जनवरी (ब्यूरो)।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक में जहां वैश्विक नेता सुस्त आर्थिक वृद्धि और बढ़ते जलवायु जोखिमों पर चिंता जता रहे हैं, वहीं भारतीय प्रतिनिधिमंडल देश की मजबूत वृद्धि दर और पर्यावरण अनुकूल उपायों को प्रमुखता से पेश कर रहा है। एक परिचर्चा में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

उन्होंने सतत विकास और ग्रिड स्थिरता के लिए निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है। जोशी ने बताया कि भारत ने डिजिटलीकरण और स्मार्ट मीटरिंग के जरिए अपने ग्रिड का आधुनिकीकरण शुरू कर दिया है, जिसने व्यवस्था को मजबूत किया है और नागरिकों को सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे ही जल्द चौथी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, अब मुख्य आवश्यकता ग्रिड की स्थिरता सुनिश्चित करने की है। 'ग्रिड स्थिरता' का मतलब बिजली के नेटवर्क (ग्रिड) में उत्पादन (आपूर्ति) और खपत के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखना है। मंत्री ने कहा कि भारत निवेश पर शानदार रिटर्न प्रदान करता है, जिसे एक स्थिर नियामक व्यवस्था और सुसंगत नीतियों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इन्हीं नीतियों ने भारत को एक 'नाजुक अर्थव्यवस्था' से बदलकर वैश्विक वृद्धि के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने में मदद की है। जोशी ने कहा कि कम गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए), नियंत्रित मुद्रास्फीति, बढ़ते उत्पादन और तेजी से सुधरते बुनियादी ढांचे के साथ भारत निवेश के लिए आकर्षक अवसर पेश कर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के 42 फीसद खनिज संसाधन झारखंड में हैं, जो देश के विकास के लिए अनिवार्य हैं। उन्होंने संसाधनों की रक्षा के साथ-साथ राज्य में समृद्धि लाने पर जोर दिया। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा, 'गुजरात बड़े पैमाने पर पर्यावरण अनुकूल उपायों का उदाहरण पेश करता है। इसने अपनी औद्योगिक क्षमता को संतुलित विकास और संसाधन दक्षता के माडल में बदल दिया है।' उन्होंने कहा कि गुजरात लंबे समय से भारत का विकास इंजन रहा है, जो राष्ट्रीय जीडीपी, निर्यात और विनिर्माण क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान दे रहा है। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि भविष्य के लिए स्थिरता के हमारे चार प्रमुख स्तंभ हैं पारिस्थितिकी तंत्र को प्राथमिकता, व्यापार करने की गति, तीसरा, पर्यावरण अनुकूल रोजगार और कौशल में निवेश और नीतिगत निश्चितता एवं दक्षता।

मैक्रों ने ट्रंप की धमकी के जवाब में ईयू से व्यापार में बदलाव को लेकर विचार का आग्रह किया

ब्रसेल्स, 21 जनवरी (एपी)।

ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से चिंतित यूरोपीय संघ, अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर विचार कर सकता है। यूरोपीय संघ (ईयू) अमेरिकी सामान पर भारी शुल्क से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के सुझाए गए तरीकों को अपना सकता है। मैक्रों ईयू 'एंटी-कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट (एसीआइ) को लागू करने का सुझाव दे रहे हैं। इसके तहत उन व्यक्तियों या संस्थानों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो यूरोपीय संघ पर अनुचित दबाव डालते पाए जाते हैं।

इन प्रतिबंधों से यूरोपीय संघ के बाजारों तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच सीमित हो सकती है, उन्हें यूरोपीय संघ के सार्वजनिक निविदाओं में भाग लेने से भी रोका जा सकता है। इसके साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात में कमी आ सकती है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। एसीआइ की स्थापना यूरोपीय आयोग द्वारा 2021 में तब की गई थी जब चीन ने ताइवान के साथ लिथुआनिया के संबंधों को लेकर उससे व्यापार प्रतिबंधित कर दिया था। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। मैक्रों ने मंगलवार को दावोस में आगाह किया कि अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क यूरोपीय संघ को पहली बार अपने दबाव-रोधी तंत्र का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।

शांति बोर्ड में शामिल होने पर भारत ने अभी तक नहीं लिया कोई फैसला

नई दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा)।

भारत ने अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 'शांति बोर्ड' का हिस्सा बनने के लिए दिये गए आमंत्रण पर कोई निर्णय नहीं लिया है। मामले से परिचित लोगों ने बुधवार को यह जानकारी दी। यह बोर्ड गाजा में स्थायी शांति लाने और संभवतः वैश्विक संघर्षों को हल करने की दिशा में काम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण के तहत गठित बोर्ड में शामिल होने के लिए जिन कई वैश्विक नेताओं को आमंत्रित किया है, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। ट्रंप गुरुवार को दावोस में वार्षिक विश्व आर्थिक मंच के दौरान एक समारोह की मेजबानी करने वाले हैं, जिसमें वे 'शांति बोर्ड' की व्यापक रूपरेखा और उसके संविधान की घोषणा करेंगे। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि भारत इस पहल के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा है क्योंकि इसमें संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं।

उधर ट्रंप के 'शांति बोर्ड' में शामिल होने के लिए कई देशों ने सहमति जताई है, जबकि यूरोपीय देशों समेत कुछ मुल्कों ने इसका सदस्य बनने का निमंत्रण ठुकरा दिया है। कई देशों ने अभी ट्रंप के न्योते पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप की अध्यक्षता वाले बोर्ड की मूल रूप से कल्पना वैश्विक नेताओं के एक छोटे से समूह के रूप में की गई थी, जिसका काम गाजा शांति योजना की निगरानी करना होगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन की महत्वाकांक्षाएं अब बढ़ गई हैं, जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने दर्जनों देशों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। इससे यह संकेत मिलता है कि बोर्ड भविष्य में संघर्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि 30 देश बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, जबकि 50 देशों को निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी। जिन देशों ने ट्रंप का आमंत्रण स्वीकार किया है, उनमें अर्जेंटीना, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, मिस्र, हंगरी, कजाकिस्तान, मोरक्को, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम शामिल हैं।

चीन, जर्मनी, इटली, पराग्वे, रूस, स्लोवेनिया, तुर्की और यूक्रेन सहित कई देशों ने आमंत्रण पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है।

सुरक्षा नासिक में बुधवार को 'तोपची 2026' अभ्यास के दौरान बोफर्स तोप से गोला दागते जवान। इस अभ्यास में उन्नत अग्नि शक्ति और निगरानी तकनीकों का एकीकरण दिखाया गया।

संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा की संपत्ति कुर्क

संभल, 21 जनवरी (भाषा)।

पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा की संपत्ति बुधवार को कुर्क की गई। यह कार्रवाई साठा की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करने का एक अदालत द्वारा एक वारंट जारी करने के बाद की गई।

अधिकारियों ने बताया कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नखासा पुलिस थानाक्षेत्र के दीपा सराय स्थित साठा के मकान पर कुर्की की कार्रवाई की गई। संभल तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई फरार आरोपी के खिलाफ अदालत के आदेशों का पालन करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के तहत की जा रही है। उन्होंने बताया कि हमने आरोपी के मकान की पहचान कर ली है और कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तर) कुलदीप सिंह ने कहा कि चार पुलिस थानों और पीएसी की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि हम साठा से जुड़ी अन्य संपत्तियों का भी ब्योरा जुटा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नखासा पुलिस थानाक्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा निवासी शारिक साठा तय समय पर अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद उसे धारा 84 के तहत भगोड़ा घोषित किया गया और संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हुआ।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि साठा के मकान की कुर्की मंगलवार को की गई और उसकी अन्य संपत्तियों का पता लगाने के लिए उसके साथियों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कहा कि शारिक साठा लंबे समय से फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए कई छापे मारे गए, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।

उत्तराखंड के दो न्यायिक अधिकारी दिल्ली न्यायिक सेवा में होंगे शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी न्यायिक अधिकारी को केवल इस आधार पर दूसरे राज्य की न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसके जाने से पहले राज्य में रिक्तियां पैदा हो जाएंगी।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने उत्तराखंड के दो न्यायिक अधिकारियों को राहत देते हुए उन्हें दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी। इन अधिकारियों को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा में चयनित होने के बावजूद वहां कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

अपीलकर्ताओं का चयन उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा के माध्यम से हुआ।

इसी दौरान उन्होंने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा में भी भाग लिया और साक्षात्कार चरण तक सफलतापूर्वक पहुंचे। उन्होंने साक्षात्कार में शामिल होने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट से अनुमति मांगी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी।

इस इनकार से आहत होकर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि इससे उनके आवागमन, निवास, बसने और पेशा अपनाने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक अंतरिम आदेश के जरिए उन्हें दिल्ली न्यायिक सेवा के साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति दी थी। बाद में घोषित परिणामों में दोनों अधिकारी चयनित पाए गए और उनकी नियुक्ति दिल्ली न्यायिक सेवा में सुनिश्चित हो गई।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

ममता के भड़काऊ भाषण से पुनरीक्षण को नुकसान हुआ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयोग ने कहा है कि ममता के भड़काऊ भाषणों, गलत जानकारी और चुनाव आयोग के अधिकारियों के प्रति धमकियों ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया। इससे निष्पक्ष चुनाव कराना चुनौती बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कड़ी आलोचना की है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि ममता ने भड़काऊ भाषणों और गलत जानकारी से पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया है। राज्य में चुनाव आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों का माहौल है, जिससे निष्पक्ष चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से हलफनामे में कहा कि ममता ने एसआइआर को नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए हैं।

उन्होंने डर फैलाने के लिए प्रेस कान्फ्रेंस की और भ्रामक व गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। आयोग ने कहा है कि अन्य राज्यों के विपरीत पश्चिम बंगाल में बहुत अधिक धमकियां और बाधाएं हैं। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि लोगों को एसआइआर की प्रक्रिया के प्रति गलत जानकारी देकर भड़काया जा रहा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है, उसमें कहा है कि ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर अधिकारियों को निशाना बनाया है। जिसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

बुजुर्ग की हृदयाघात से मौत

कोलकाता, 21 जनवरी (भाषा)।

उत्तर 24 परगना जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कवायद को लेकर चिंता के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान सहर अली मंडल के रूप में हुई है। वह एक परिवार के पांच सदस्यों में से एक थे, जिन्हें पुनरीक्षण के तहत बुधवार को सुनवाई के लिए नोटिस मिला था।

27 साल, तीन मिशन और अंतरिक्ष में 608 दिन गुजारे | संन्यास | सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी का रिकार्ड भी

सुनीता विलियम्स 60 साल बेमिसाल, नासा को कहा अलविदा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जनवरी।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महीनों तक फंसे रहे दो अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल नासा की सुनीता विलियम्स सेवानिवृत्त हो गई हैं। नौसेना की पूर्व कप्तान विलियम्स (60) ने नासा में 27 वर्षों से अधिक समय तक सेवाएं दीं और अंतरिक्ष स्टेशन के तीन मिशन में कुल 608 दिन अंतरिक्ष में गुजारे। उन्होंने एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चहलकदमी (स्पेसवाक) का रिकार्ड भी बनाया। उन्होंने कुल 62 घंटे अंतरिक्ष में चहलकदमी की।

अमेरिका की अंतरिक्ष एजंसी नासा ने मंगलवार को बताया कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सेवानिवृत्ति का आदेश पिछले साल दिसंबर के अंत से प्रभावी हो गया।

बयान में विलियम्स के हवाले से कहा गया कि जो कोई भी मुझे जानता है, उसे पता है कि अंतरिक्ष मेरा सबसे पसंदीदा स्थान है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कार्यालय में सेवाएं देना और अंतरिक्ष में तीन बार उड़ान भरने का अवसर मिलना मेरे लिए अविश्वसनीय सम्मान रहा है। नासा में 27 साल का मेरा करियर अद्भुत रहा और यह मुख्य रूप से मेरे सहकर्मियों से मिले अत्यधिक प्रेम एवं समर्थन की वजह से संभव हो पाया।

बोइंग की कैप्सूल परीक्षण उड़ान के दौरान विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में फंसे रहे बुच विलमोर ने पिछले साल गर्मियों में नासा छोड़ दिया था। विलियम्स और विलमोर को 2024 में अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था और वे बोइंग के नए 'स्टारलाइनर' कैप्सूल से उड़ान भरने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री थे। उनका मिशन केवल एक सप्ताह का था लेकिन स्टारलाइनर में आई दिक्कतों के कारण यह नौ महीने से भी लंबा खिंच गया। वे अंततः पिछले साल मार्च में पृथ्वी पर लौटे। नासा के नए प्रशासक जैरेड आइजैकमैन ने विलियम्स को 'अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में अग्रणी' बताया। उन्होंने एक बयान में कहा कि आपकी इस शानदार सेवानिवृत्ति पर बधाई। बोइंग का अगला स्टारलाइनर मिशन अंतरिक्ष स्टेशन तक मनुष्यों को नहीं, केवल माल को लेकर जाएगा। नासा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी को भी कैप्सूल से अंतरिक्ष में भेजने से पहले इसके थ्रस्टर और अन्य सभी समस्याओं को सुलझा लिए जाएं। यह परीक्षण उड़ान इस वर्ष बाद में होगी।

विलियम्स इस समय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने मंगलवार दोपहर को यहां अमेरिकी केंद्र में आयोजित एक संवाद सत्र में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम स्थल पर 'नजर सितारों पर, पैर जमीन पर' शीर्षक वाले पोस्टर लगाए गए थे जिनमें विलियम्स को 'नासा की सेवानिवृत्त अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी नौसेना की सेवानिवृत्त कप्तान' के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने संवाद के दौरान उस समय के अपने अनुभवों को भी साझा किया जब वह अंतरिक्ष में फंस गई थीं।

दक्षिण कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हान को 23 वर्ष की सजा

सियोल, 21 जनवरी (एपी)।

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि तत्कालीन राष्ट्रपति यून सुक योल द्वारा 2024 में लागू किया गया मार्शल ला विद्रोह की श्रेणी में आता है।

अदालत ने इस मामले में संलिप्तता के लिए यून के समय देश के प्रधानमंत्री रहे हान डक-सू को 23 साल की कारावास की सजा सुनाई। हान डक-सू, यून सरकार के पहले अधिकारी बन गए हैं, जिन्हें दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति यून द्वारा लगाए गए मार्शल ला से जुड़े विद्रोह के आरोपों में दोषी ठहराया गया। इस फैसले से राष्ट्रपति यून और उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ आने वाले फैसलों की दिशा तय होने की उम्मीद है। यून भी विद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। यून द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हान दक्षिण कोरिया के दूसरे सबसे बड़े पद पर थे।

चिंतन

प्रदूषण पर अब छोटे शहरों को भी सतर्क होना होगा

जिस कश्मीर को सदियों से धरती का स्वर्ग कहा जाता रहा है, वहां की हवा आज लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल बना रही है। जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वायु प्रदूषण का स्तर पिछले 7 वर्षों में सबसे खराब स्थिति में पहुंच चुका है। बुधवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 308 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्तर की हवा में सांस लेना लगभग चार सिगरेट पीने के बराबर है। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि उस खतरे का संकेत है, जो अब पहाड़ों, झीलों और हरियाली से घिरे शहरों तक भी पहुंच चुका है। एयर मॉनिटरिंग डेटा यह दर्शाता है कि जनवरी में श्रीनगर की वायु गुणवत्ता लगातार खराब रही। वर्ष 2019 के बाद 2026 को श्रीनगर का सबसे प्रदूषित वर्ष माना जा रहा है, जहां औसत एक्यूआई 159 रहा। इतनी तेजी से गिरती वायु गुणवत्ता यह दर्शाती है कि यदि अब भी सतर्क नहीं हुए तो छोटे और पहाड़ी शहर भी महानगरों जैसी प्रदूषण त्रासदी झेलने को मजबूर होंगे। अब तक वायु प्रदूषण को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों की समस्या माना जाता रहा है, लेकिन श्रीनगर में बढ़ता प्रदूषण इस धारणा को तोड़ता है। प्राकृतिक सुंदरता, कम औद्योगीकरण और अपेक्षाकृत कम जनसंख्या के बावजूद श्रीनगर का इस स्तर तक प्रदूषित होना गंभीर चेतावनी है। दिल्ली की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी का एक्यूआई 339 दर्ज किया गया, जो लगातार 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा समेत देश के कई राज्य गंभीर प्रदूषण की चपेट में हैं। हालांकि, हरियाणा में दिल्ली की तुलना में वाहनों की संख्या कम होने के कारण वहां प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम देखा जाता है। यह तुलना साफ तौर पर बताती है कि वाहनों की बढ़ती संख्या प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन चुकी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सर्वोच्च न्यायालय को यह स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान वाहनों से होने वाले उत्सर्जन का है। इसके बावजूद, अक्सर पराली जलाने को ही प्रदूषण का मुख्य कारण ठहराया जाता है। यह सच है कि पराली जलाना एक समस्या है, लेकिन यह मौसमी और सीमित समय तक प्रभाव डालती है, जबकि वाहनों से निकलने वाला धुआं पूरे वर्ष शहरों की हवा को जहरीला बनाता रहता है। प्रदूषण में सुधार के लिए सीएक्यूएम ने 15 दीर्घकालिक उपायों की सिफारिश की है। इनमें वाहनों को इलेक्ट्रिक, सीएनजी या अन्य ग्रीन फ्यूल पर स्थानांतरित करना प्रमुख है। प्रदूषण केवल स्वास्थ्य संकट नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने विश्व आर्थिक मंच में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रदूषण का प्रभाव, भारत पर लगाए गए किसी भी टैरिफ के प्रभाव से कहीं अधिक गंभीर है। उनका यह बयान इस सच्चाई को उजागर करता है कि पर्यावरणीय गिरावट की आर्थिक लागत दीर्घकाल में विकास दर, श्रम उत्पादकता और स्वास्थ्य व्यय पर भारी बोझ डालती है। आज जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ठोस और प्रभावी नीतियां लागू करें। छोटे शहरों में भी एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क को मजबूत किया जाए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि प्रदूषण से लड़ाई सामूहिक प्रयास से ही जीती जा सकती है।

विचार
डॉ. संजय शुक्ला

मनोरंजन की आड़ में अश्लीलता स्वीकार्य नहीं

देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध लोककला, परंपरा और संस्कृति है। यह राज्य जनजातीय लोकनृत्य और संस्कृति के नाम पर मशहूर है लेकिन वहीं के आदिवासी अंचलों में कथित तौर पर बार बालाओं के अश्लील डांस ने इस विरासत को शर्मसार किया है। राज्य के आदिवासी बहुल गरियाबंद और सूरजपुर में बीते दिनों मनोरंजन के नाम पर हुए अश्लील डांस के विडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सियासत और सोशल मीडिया में काफी खलबली मच गई। विडंबना यह कि सूरजपुर में जहां यह आयोजन सरकारी रेस्ट हाऊस में हुआ वहीं गरियाबंद के उरमाल गांव में हुए अश्लील डांस के दौरान जिले के एसडीएम और पुलिस कर्मी अर्धनग्न बार बालाओं पर पैसे उड़ाते देखे गए। सोशल मीडिया पर वायरल विडियो को देखें तो गरियाबंद जिले में हुए अश्लील डांस में नग्नता और फूहड़ता की सारी हदें लांघ दी। इधर इस खबर को लेकर जहां विपक्ष सत्तारूढ़ दल पर लगातार हमलावर रही वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स सत्तारूढ़ पार्टी पर तंज कसते नजर आए। राज्य सरकार ने मामले पर फौरी कार्रवाई करते हुए गरियाबंद जिले में अश्लील डांस करने वाले डांसर तथा कार्यक्रम आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया है वहीं इस आयोजन की अनुमति देने और डांसरों पर नोट उड़ाने वाले एसडीएम व तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी ओर सूरजपुर के रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस पर वहां के डिप्टी रेंजर और फारेस्ट गार्ड को निलंबित कर दिया गया है।

बहरहाल छत्तीसगढ़ में मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रम के आड़ में अश्लील डांस का यह कोई पहला वाकया नहीं है बल्कि पहले भी ऐसे भौंडे आयोजन होते रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार के समय भी महेन्द्रगढ़ - चिरमिरी-भरतपुर जिले के खड़गंवा में दशहरा उत्सव में रावड़ दहन के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में लड़कियों के बोल्ड डांस के दौरान नेता और जनता डांसरों पर नोट उड़ाते देखे गए थे। तब विपक्षी दल भाजपा ने डांस के दौरान बैठे सत्तारूढ़ दल के विधायक और नेताओं से सवाल किया था यह कौन सी संस्कृति और गांधीवाद है? इसके जवाब में तब के थाना प्रभारी ने जवाब दिया था कि वहां अश्लील डांस नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ी नाच हो रहा था। अलबत्ता थानेदार के दावे की पोल इस कार्यक्रम की वायरल वीडियो खोल रही थी जिसमें डांसरों के कपड़े और भाव- भंगिमा अत्यंत आपत्तिजनक थे। बहरहाल छत्तीसगढ़ जैसे संस्कृति और लोककला संपन्न राज्य में ऐसी अपसंस्कृति और अश्लीलता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता बल्कि सरकार और प्रशासन को इस दिशा में सख्ती बरतने की जरूरत है। विचारणीय है कि देश में मनोरंजन और कॉमेडी के नाम पर सिनेमा और टेलीविजन से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में जिस तरह से अश्लीलता और फूहड़ता परोसी जा रही है उसने मनोरंजन और कला के मायने को ही बदल कर रख दिया है। भारत एक धार्मिक और संस्कृति धर्मी देश है लेकिन यहां के धार्मिक नगरों और मेलों में भी अश्लील कार्यक्रम आयोजित करने के मामले सामने आए हैं। इसी साल धर्मनगरी मथुरा के एक होटल में न्यू ईयर के मौके पर पोर्नस्टार सनी लियोन का कार्यक्रम आयोजित था जिसे धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद रद्द कर दिया। बीते साल प्रयागराज के धार्मिक मेले में हिंदी और भोजपुरी गानों पर जमकर अश्लील डांस हुआ था जिस पर बवाल मचा था। अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम मंदिर में देवछठ मेले में रशियन लड़कियों के फूहड़ डांस पर भी विवाद हुआ था। अलबत्ता देश के विभिन्न राज्यों में धार्मिक मेलों के दौरान आस्था पर अश्लीलता का तड़का लगने की फेहरिस्त काफी लंबी है जो सीधे तौर पर प्रशासनिक उदासीनता का उदाहरण है।

मनुष्य हमेशा से कलाप्रेमी और संस्कृति धर्मी रहा है जिसके जीवन में त्योहार, नृत्य और उत्सव के रंग समाहित रहे हैं। विज्ञान के विकास के साथ ही कला और मनोरंजन के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है तथा इसके साधन बदलते गए।अतीत पर गौर करें तो देश में मनोरंजन का क्षेत्र शहरी और ग्रामीण परिवेश में बंटा हुआ था लेकिन टेलीविजन और इंटरनेट के प्रसार ने बहुत हद तक इस खाई को पाट दिया है। एक दौर वह था जब शहरों में मनोरंजन के केंद्र सिनेमा, थिएटर, मीना बाजार, रेडियो होता था तो ग्रामीण परिवेश में नाचा- गम्मत, मेला- मड़ई, विभिन्न त्योहारों पर होने वाले लोकनृत्य और गीत लोगों के जीवन में रस घोलते थे। साहित्य और गीत की विधा में कवि सम्मेलन और आर्केस्ट्रा भी लोगों का मन बहलाते थे।

सत्तर के दशक में टेलीविजन की दस्तक के साथ ही मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। अलबत्ता भारत में दूरदर्शन के एकाधिकार तक टेलीविजन एक स्हू पारिवारिक मनोरंजन का सबसे उम्दा साधन था। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले विभिन्न

पारिवारिक और धार्मिक धारावाहिक, कार्यक्रम और फिल्में लोगों के लिए स्वस्थ मनोरंजन का बेहतर माध्यम था। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए मनोरंजन का सबसे उम्दा साधन टेलीविजन अब सचमुच में 'बुद्धू बक्सा' साबित हो रहा है। टीवी चैनलों पर हास्य, हॉरर, कॉमेडी और रियेलिटी शो के नाम पर ऐसे धारावाहिक परोसे जा रहे हैं जिसमें अश्लीलता, फूहड़ता, अंधविश्वास, विवाहेत्तर संबंध, लिव इन रिलेशनशिप, नशाखोरी, अपराध और हिंसा के कथानक भरे पड़े हैं। रियेलिटी शो में प्रतिभागियों के कपड़े और संवाद इतने आपत्तिजनक होते हैं कि इन कार्यक्रमों को परिवार के साथ देखना असहज होता है।

सिनेमा को समाज का आईना कहा जाता है जिसके प्रति भारतीयों को शुरूआत से ही आकर्षण रहा है। भारतीय सिनेमा के इतिहास पर गौर करें तो कला और संस्कृति के प्रकटीकरण का सबसे सशक्त माध्यम सिनेमा ही था लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने इस उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। कुछ को छोड़ दें तो आज की फिल्में हमारे संस्कृति और कला पर लगातार हमला कर रही है। आज की अधिकांश फिल्मों में नग्नता, गाली-गलौज, हिंसा, नशाखोरी और अपसंस्कृति के दृश्य आम है जिसके कारण अब सिनेमा भी पारिवारिक मनोरंजन का साधन नहीं रहा।

इंटरनेट क्रांति ने मनोरंजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसने मनोरंजन से जुड़ी सामग्रियों को प्राप्त करने और देखने के तरीके को बदल कर रख दिया है। डिजिटल मीडिया के इस दौर में 'ओवर द टॉप' (ओटीटी) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन दिनों किशोरों और युवाओं से लेकर हर उम्र के लोगों के लिए पसंदीदा मनोरंजन माध्यम बन चुके हैं लेकिन इसकी दुश्वारियां भी सामने आ रही है।ओटीटी और सोशल मीडिया पर मनोरंजन के नाम पर कई ऐसे कई शो और वेब सिरीज़ प्रसारित हो रहे हैं जो नग्नता और भद्दी गालियों के चलते मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं।बीते साल ' उल्लू ऐप' के रियलिटी वेब शो ' हाउस अरेस्ट ' के अत्यंत अश्लील कंटेंट वायरल होने के बाद विभिन्न धार्मिक संगठनों ने काफी बवाल मचाया था जिसके चलते शो को बैन करना पड़ा। पिछले साल ही यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फलुएंसर रणवीर अलाहबादिया को " इंडिया गॉट लेटेस्ट" शो में उनके द्वारा अपने माता-पिता के नितांत निजी क्षणों के बारे में अत्यंत भद्दी टिप्पणी किए जाने पर सोशल मीडिया से लेकर संसद और सड़कों पर काफी विरोध देखा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अख्तियार करते हुए शो पर प्रतिबंध लगा दिया था।

गौरतलब है कि ओटीटी और यूट्यूब पर प्रसारित होने वाले अनेक आपत्तिजनक शो और वेब सिरीज़ के चलते जहां किशोरों और युवाओं के मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ रहा है वहीं हमारी सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर भी चोट पहुंचा रही है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में महिलाओं के साथ बढ़ते दुष्कर्म, हिंसा, अपराध और नशाखोरी के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार इंटरनेट और सोशल मीडिया में मौजूद आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट हैं। बहरहाल भारत सदियों से अपनी पुरातन कला, सभ्यता और संस्कृति के कारण ही समूची दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को यह बात भी अपने जेहन में रखना होगा कि भारतीय समाज लज्जा और मर्यादा के तानेबाने में गूंथा है लिहाजा कला के नाम पर अश्लीलता फैलाना कतई उचित नहीं है। सरकार को जहां ऐसे कार्यक्रमों के खिलाफ सख्ती बरतनी होगी वहीं मनोरंजन माध्यमों को भी इस दिशा में स्व- नियमन और आत्मानुशासन की जरूरत है।

मुद्दा
राज कुमार सिंह

ट्रंप को नोबेल सौंप संदेह व सवालों में घिरीं मचाडो

आखिरकार शांति का नोबेल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच ही गया। खुद को शांति दूत बताने वाले ट्रंप की दावेदारी के बावजूद नोबेल पुरस्कार समिति ने तो उन्हें इस लायक नहीं माना, पर वेनेजुएला की जिन विपक्षी नेता मारिया मचाडो को नोबेल दिया गया था, वही खुद वाशिंगटन जाकर उन्हें अपना पुरस्कार सौंप आयीं। अपने साल भर के शासन में युद्ध विराम का इतिहास रचने के एकतरफा दावे करते हुए ट्रंप खुद को शांति के नोबेल का सही पात्र बताते रहे, लेकिन पुरस्कार समिति को ऐसा नहीं लगा। सो, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को नजरअंदाज कर समिति ने नोबेल दे दिया वेनेजुएला में लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के लिए संघर्षरत विपक्षी नेता मारिया मचाडो को। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले ट्रंप नाराज हुए। नोबेल समिति को बुरा-भला भी कहा। फिर भी मचाडो ने वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली में सहयोग की आकांक्षा जताते हुए अपना नोबेल उन्हें समर्पित करने की बात कही थी। तब माना गया था कि यह एक नोबेल विजेता का बड़प्पन है कि उसने अपनी प्रतिक्रिया में पदक से वंचित को अपना पदक समर्पित किया पर मचाडो ने ट्रंप से मुलाकात में उन्हें बाकायदा अपना नोबेल सौंपकर अब दुनिया को चौंका दिया है। हालांकि नोबेल पुरस्कार समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि इसे किसी को गिफ्ट या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यह भी कि सिर्फ मूल विजेता ही हमेशा नोबेल पुरस्कार विजेता कहलाएगा। मचाडो द्वारा अपना नोबेल ट्रंप को देने के पीछे की किसी डील पर फिलहाल अटकलें ही लगाई जा सकती हैं। वैसे मचाडो से पहले वेनेजुएला पर हमला

कर ट्रंप दुनिया को चौंका चुके थे। नार्को टैररिज्म आदि के आरोपों के बीच लगातार धमकाते रहने के बाद एक दिन अचानक ट्रंप ने अपनी डेल्टा फोर्स भेज कर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सपत्नीक उठवा लिया। मादुरो पर अमेरिका में जारी मुकदमे के बीच ही मचाडो वाशिंगटन पहुंच कर ट्रंप से मिलीं और अपना नोबेल उन्हें गिफ्ट कर दिया। उन्होंने ट्रंप पर पूरा भरोसा जताते हुए इसे वेनेजुएला के निवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन भी करार दिया। ट्रंप ने भी मारिया से मुलाकात को सम्मानजनक बताते हुए टिप्पणी कीः 'उन्होंने मेरे अच्छे कामों के लिए मुझे अपना नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। हमारे बीच का यह आपसी सम्मान कमाल का है।' इसमें दो राय नहीं कि इंजीनियरिंग का पेशा छोड़कर राजनीति में आयीं तलाकशुदा 58 वर्षीय मचाडो ने वाकई वेनेजुएला में तानाशाही शासन समाप्त कर लोकतंत्र बहाली के लिए लंबा शांतिपूर्ण संघर्ष किया है। उन्होंने बहुत कुछ सहा भी है। उसी संघर्ष के लिए उन्हें विश्व का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार भी मिला, जो उन्होंने अब उसी व्यक्ति को सौंप दिया है, जिसे पूरी दुनिया वेनेजुएला पर सैन्य आक्रमण करने वाले विदेशी शासक के रूप में देखती है। ट्रंप खुद वेनेजुएला का तेल बेच कर मुनाफा कमाने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना नोबेल सौंपते हुए मचाडो ने लिखाः 'ट्रंप ने वेनेजुएला की आजादी के लिए जो किया है, उसे वेनेजुएला के लोग कभी नहीं भूलेंगे।' मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में भावी सत्ता व्यवस्था और चुनावों की अटकलों के बीच ट्रंप से मिलीं मचाडो कोई ठोस आश्वासन नहीं पा सकीं। वेनेजुएला के संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है, पर ट्रंप खुद को वहां का कार्यवाहक राष्ट्रपति बता रहे हैं। शायद ट्रंप को रोड्रिग्ज के साथ काम करने में कोई समस्या भी न हो, क्योंकि उनकी नजर तो वेनेजुएला में तेल और दुर्लभ खनिज संपदा के दोहन पर है। ऐसे में वेनेजुएला समेत दुनिया भर में मचाडो की नई भूमिका पर संदेह और सवाल स्वाभाविक हैं। बेशक मचाडो लंबे समय से वेनेजुएला में लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकारों की बहाली के लिए संघर्षरत हैं। 2024 में उन्हें राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ने दिया गया और उनके द्वारा समर्थित विपक्षी उम्मीदवार एडमंड गोंजालेज को जीत के बावजूद सत्ता नहीं सौंपी गई। यह भी कि मादुरो की छवि तानाशाह शासक की रही है, लेकिन देश पर हमला कर उसके संसाधनों की लूट करने वाले विदेशी शासक का गुणगान करते हुए उसे अपना नोबेल सौंप कर खुद मचाडो अपनी साख पर उठते संदेह और सवालों से नहीं बच पाएंगी। अपने देश में लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष निश्चय ही देश-समाज के प्रति साहसिक प्रतिबद्धता का काम है, लेकिन उसके लिए विदेशी आक्रांता का सहयोग लेना और उसका गुणगान करना कम-से-कम देश प्रेम के दायरे में तो नहीं आता।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है समर्पण

संकलित
दर्शन

समर्पण प्रत्येक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक भाव है। यही वह भाव है जिसके माध्यम से हम अपने आत्मीय जनों के प्रिय बन सकते हैं। यह स्मरण रहे कि राग, द्वेष, घृणा तथा स्वार्थ का त्याग किए बिना समर्पण की कल्पना व्यर्थ है। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू में समर्पण का भाव आवश्यक है। समर्पण हमारे लौकिक एवं पारलौकिक दोनों जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है। संबंधों में मधुरता के लिए हमें परस्पर समर्पण भाव रखते हुए रिश्तों का निर्वहन करना होता है। स्वार्थ की दृष्टि से बनाए गए रिश्ते अल्पावधि के उपरांत समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी समर्पण भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। जब हम अपने संपूर्ण समर्पण के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित हो जाते हैं, तब कोई भी लक्ष्य हमसे दूर नहीं रहता। समर्पण के साथ-साथ विश्वास का होना भी आवश्यक है। जिस प्रकार एक बीज धरती में रोपित किया जाता है, तो वह संपूर्ण रूप से खुद को धरती मां की गोद में समर्पित कर देता है। तभी उसमें विकास के नए अंकुर फूट पड़ते हैं। भास्कर की किरणों उसे शक्ति प्रदान करती हैं। पवन की शीतलता उसे दुलारती है। मेघ उसका अभिसिंचन करते हैं। इस प्रकार उसे संपूर्ण प्रकृति का सहयोग एवं साहचर्य मिलने लगता है। उसके बाद वह धीरे-धीरे एक संपूर्ण वृक्ष का आकार ले लेता है। एक ऐसे वृक्ष का, जिसके आश्रय में तमाम प्राणी शीतलता प्राप्त करते हैं।

बिन बुलाए किसी के घर न जाएं

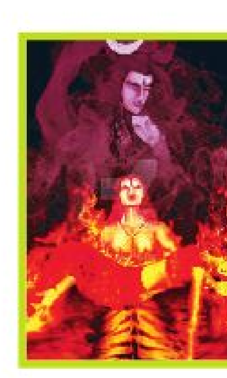

संकलित
प्रेरणा

माता सती के पिता प्रजापति दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा जी का पांच में से एक सिर काट दिया था। अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ हुई इस घटना की वजह से दक्ष शिव जी को अपमानित करने के अलग-अलग अवसर खोजते रहते थे। दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया था और दक्ष इस विवाह को रोक नहीं सके। विवाह के कुछ समय बाद दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को नारद से मालूम हुआ कि उनके पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं। सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गईं। शिव जी ने देवी सती को समझाया कि बिना बुलाए हमें यज्ञ जैसे आयोजन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिव जी के समझाने पर भी देवी नहीं मानीं और यज्ञ में चली गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव जी के अतिरिक्त सभी देवी-देवता आए हुए हैं। सती ने पिता दक्ष से शिव जी को न बुलाने का कारण पूछा तो दक्ष ने शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दीं। शिव जी का अपमान सती सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब ये बात शिव जी को मालूम हुई तो वे बहुत क्रोधित हो गए। शिव जी के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। इसके बाद शिव जी के कहने पर वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और दक्ष का सिर काट दिया।

अंतर्मन

आज की पाती

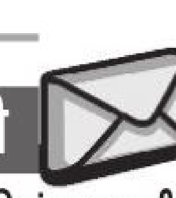

सोना-चांदी के दामों पर नियंत्रण जरूरी

चांदी के भाव तो गजब ही ढा रहे हैं। 10-15 हजार के रोज भाव बढ़ रहे हैं जो जाकर अब एक किलो चांदी के 3 लाख पार हो गए हैं। आगे क्या होगा भगवान जाने। ठीक सोने के मूल्य भी 10 ग्राम डेढ़ लाख छू गए हैं। मेक्स (मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज) को बंद करने की मांग भी जूलरी संगठन ने उठाई है क्योंकि इसी से कतिपय धनाढ्य सट्टेबाज/उद्योगपति कृत्रिम भाव बढ़ा रहे हैं, जबकि वास्तव में इतने भाव हैं नहीं। इससे छोटे व्यापारी असमंजस में पड़े हुए हैं और उन्हें कभी भी भारी घाटा हो सकता है। उनकी मांग है कि सोना-चांदी के मूल्य-नियंत्रण वो खुद अपने हाथ में ले, ताकि बढ़ते सट्टाधारी भाव पर कंट्रोल हो सके। उन्होंने आने वाले बजट में इसके लिए नीति बनाने की मांग की है।

- सुनील देशपांडे, दुर्ग

करंट अफेयर

दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र का फिर होगा संचालन

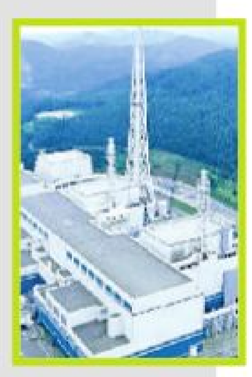

जापान में 2011 में हुए फुकुशिमा परमाणु हादसे के बाद दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र का संचालन बुधवार को फिर से शुरू हो जाएगा। जापान बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। काशीवाजाकी–कारिवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के नंबर–6 रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन की शुरुआती प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संचालन तोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स (टीईपीसीओ) कर रही है। यह वही कंपनी है जो क्षतिग्रस्त फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र का भी संचालन करती है। फुकुशिमा में टीईपीसीओ से जुड़ी पिछली सुरक्षा समस्याओं के कारण काशीवाजाकी–कारिवा संयंत्र के संचालन को लेकर लोग चिंतित हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि यह संयंत्र एक अलग–थलग और भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है। काशीवाजाकी–कारिवा परमाणु संयंत्र के सभी सात रिएक्टर मार्च 2011 में जापान के उत्तर–पूर्वी तट पर स्थित फुकुशिमा दाइची संयंत्र में भीषण भूकंप और सुनामी आने के एक साल बाद से बंद पड़े हैं। उस हादसे में रिएक्टर पिघल गए थे और रेडियोधर्मी पदार्थों के भारी रिसाव से आसपास की जमीन इतनी दूषित हो गई कि कुछ इलाके आज भी रहने योग्य नहीं हैं। टीईपीसीओ अभी भी अपनी छवि को हुए नुकसान से उबरने की कोशिश कर रही है।

ऑफ बीट

टैटू इंक में मिले भारी मात्रा में लेड और विषैली धातु

अध्ययन में पाया गया, टैटू की स्याही को जीवित ऊतक में डाला जाता है और यह मूल रूप से स्थायी रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शरीर में मौजूद पिगमेंट समय के साथ घुल सकते हैं, लिम्फ सिस्टम में फैल सकते हैं या धीरे–धीरे टूट सकते हैं। यूरोप में टैटू की स्याही की सुरक्षा पर मार्गदर्शन पिछले दशक से उपलब्ध है और 2022 से यूरोपीय संघ ने इस स्याही में धातु जैसे आर्सेनिक, कैडमियम और लेड तथा कुछ ऑर्गेनिक यौगिकों की सीमा तय की है। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई नियामक ढांचा नहीं है। यहां टैटू की स्याही की नियमित निगरानी नहीं होती और उपभोक्ताओं के पास सीमित जानकारी उपलब्ध है। अध्ययन में 15 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की काली और रंगीन टैटू की स्याही का विश्लेषण किया गया। परिणाम दिखाते हैं कि हर स्याही में कम से कम एक यूरोपीय सुरक्षा मानक का उल्लंघन था। इसमें आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम और लेड जैसी विषैले धातुएं शामिल थीं। कुछ स्याही में एरोमैटिक अमाइन जैसी ऑर्गेनिक यौगिक भी पाए गए, जिन्हें यूरोप में उनके कैंसरजनक होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है। विशेष रूप से, काली स्याही में धातुओं की व्यापक श्रृंखला पाई गई, जबकि चमकीले रंग की स्याही में कुछ विशेष धातुओं की उच्च मात्रा थी।

ट्रेंड

लालच की महामारी

हर आम भारतीय की ज़िंदगी आज नर्क की यातना बन गई है। सिस्टम सत्ता के सामने बिक चुका है। सब एक-दूसरे की पीठ थपथपाते हैं और मिलकर जनता को रौंदते हैं। देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, शहरी सड़न जिसका सबसे डरावना चेहरा है।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

असम चाय के नए बाजार

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर और आगामी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के साथ, असम चाय को नए बाजार मिलेंगे। राज्य सरकार के दृष्टिकोण से, हम चाय उत्पादन के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

- हिमंता बिस्वा सरमा, सीएम, असम

यमुना की सफाई

यमुना की सफ़ाई के लिए संकल्प, टेक्नोलॉजी और ज़मीनी स्तर पर बदलाव, तीनों पर हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इसी दिशा में 'वाटर मास्टर' को नजफगढ़ ड्रेन में तैनात किया गया है। यह पहल ड्रेन्स की स्वच्छता की दिशा में एक निर्णायक बदलाव लाएगी।

-रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

गर्व की अनुभूति

पहले जम्मू-कश्मीर के लाल-चौक पर पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते थे और कांग्रेस की सरकारें मौन रहती थीं, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाल चौक पर शान से तिरंगा लहरा रहा है। इसे देखकर गर्व की अनुभूति होती है।

- नितिन नबीन, अध्यक्ष, भाजपा

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

क्या शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद?

1941 से वैधता पर शुरू हुआ विवाद, दावा और कोर्ट के फैसलों के बीच अटका

मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के एक आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्होंने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया। शंकराचार्य पद की वैधता पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो 1941 से शुरू हुआ था

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

प्रयागराज में माघ मेला के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और मेला प्रशासन के बीच टकराव हो गया था। इस विवाद ने तूल पकड़ते हुए राजनीतिक रंग ले लिया। आरोप-प्रत्यारोप के दौर के बीच मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के एक आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी कर पूछा था कि उन्होंने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया। शंकराचार्य पद की वैधता पर लंबे समय से विवाद चल रहा है, जो 1941 से शुरू हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बीच मामला अटका हुआ है। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद साल 2022 से ही ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि इस पद पर उनकी नियुक्ति शुरू से ही विवादित मानी जाती रही है।

1941 से पहले शंकराचार्य की गद्दी खाली थी

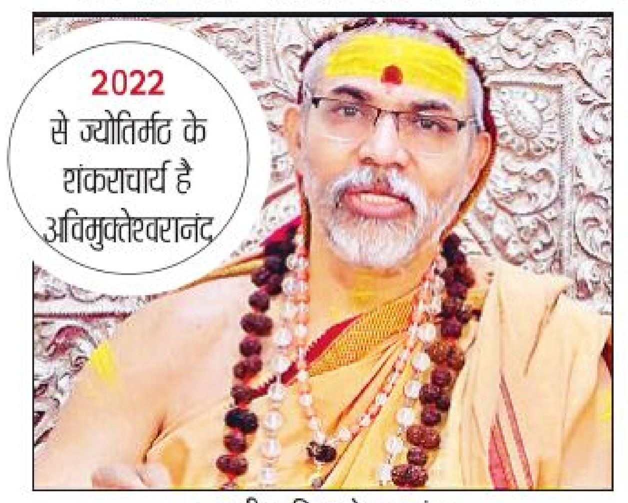
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

2022 से ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद

18वीं सदी में ज्योतिर्मठ पर स्वामी रामकृष्ण तीर्थ काबिज रहे। उनकी मृत्यु के बाद लगभग 165 वर्षों तक मठ निष्क्रिय रहा। तीन और पीठों के शंकराचार्यों ने मिलकर स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को शंकराचार्य पद के लिए राजी किया और उन्हें इस पद के लिए स्वीकृति भी दी। इस तरह 11 मई 1941 को स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की नियुक्ति वाराणसी के 'भारत धर्म महामंडल' से जुड़े साधु-संतों की ओर से की गई। इस नियुक्ति को पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ और श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी चंद्रशेखर भारती का समर्थन था।

पूरे विवाद को यूं समझें

1952 को स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती ने वसीयत कर स्वामी शांतानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी बनाया। उनके निधन के बाद 1953 को स्वामी शांतानंद सरस्वती को काशी में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के रूप में स्वीकृति दी गई, लेकिन स्वामी कृष्णबोध आश्रम को शंकराचार्य के रूप में स्वीकार किया और वसीयत के आधार स्वामी शांतानंद की नियुक्ति को गलत बताया। 1955 को सिविल कोर्ट ने स्वामी शांतानंद सरस्वती को उत्तराधिकार का सर्टिफिकेट दिया। स्वामी शांतानंद सरस्वती ने स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी बना दिया। स्वामी विष्णुदेवानंद सरस्वती ने वसीयत कर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को उत्तराधिकारी बनाया।

2017 से सुप्रीम कोर्ट में है मामला

नवंबर 1989 स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इसको चुनौती देते हुए मामला फिर से कोर्ट में ले गए। इसके बाद वासुदेवानंद सरस्वती और स्वामी स्वरूपानंद के बीच लंबी कानूनी लड़ाई जारी रही।साल 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वरूपानंद और वासुदेवानंद सरस्वती सहित कई शंकराचार्यों की नियुक्तियों को अवैध ठहराया था और एक कमेटी बनाकर नए शंकराचार्य की नियुक्ति के निर्देश दिए, जिससे विवाद और गहरा गया।

अविमुक्तेश्वरानंद के साथ सही हुआ: रामभद्राचार्य

जगद्गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ। अन्याय तो उन्होंने किया है। नियम यह है कि गंगा तक पालकी से नहीं जाया जाता। हम लोग भी पैदल ही जाते हैं। सरकार ने उन्हें खुद को शंकराचार्य साबित करने के लिए, बिल्कुल सही नोटिस जारी किया है।

वहीं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले को लेकर कहा कि उनसे जुड़े मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीद जताई की विवाद जल्द ही खत्म हो जाएगा।

खबर संक्षेप

राष्ट्रपति मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या जाएंगी

अयोध्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। ट्रस्ट के अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उनके मुताबिक, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2083 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि मुर्मू इस आयोजन की मुख्य अतिथि होंगी।

अमृत उद्यान 3 फरवरी से लोगों के लिए खुलेगा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च, 2026 तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। लोग सप्ताह में छह दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक (अंतिम प्रवेश 5.15 बजे) उद्यान में घूमने आ सकते हैं। उद्यान सोमवार को रखरखाव के दिन और 4 मार्च को होली के कारण बंद रहेगा। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी इसकी जानकारी दी है।

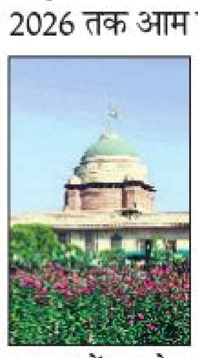

संजौली हेलीपोर्ट से हेली टैक्सी सेवाएं शुरू

शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली हेलीपोर्ट को केंद्र से जरूरी मंजूरी के बाद आधिकारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए खोल दिया गया है। इसी के साथ दो कंपनियों ने यहां से हेली टैक्सी सेवाएं शुरू कर दी हैं। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिकांगपिओ व भुंतर के लिए उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

उदयपुर में जीप खाई में गिरी, 3 की मौत

उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में सवारी से भारी जीप बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल कोटड़ा में बिलवन की ओर से जा रही जीप का चढ़ाई के दौरान अचानक ब्रेक फेल हो गया।

दोबारा हिंदू बन जाओ फिल्में मिलने लगेंगी

नई दिल्ली। म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान ने जबसे इंडस्ट्री में सांप्रदायिक भेदभाव होने की बात कही है, वो विवादों में फंस गए हैं। अब भजन सम्राट अनूप जलोटा ने कहा है कि रहमान को इस बात का विश्वास है कि हमारे देश में मुस्लिम होने की वजह से उनको फिल्में नहीं मिल रही हैं म्यूजिक देने के लिए, तो फिर वो दोबारा हिंदू हो जाएं।

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

अवैध खनन कतई बर्दाश्त नहीं, चार हफ्ते में हाई पावर कमेटी के सदस्यों के नाम दें

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा मात्र तकनीकी नहीं, बल्कि देश के पर्यावरण भविष्य से जुड़ा हुआ है। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे खनन के परिणाम अपूर्णीय और दूरगामी होते हैं

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए, कहा कि यह मुद्दा मात्र तकनीकी नहीं, बल्कि देश के पर्यावरण भविष्य से जुड़ा हुआ है। अदालत ने साफ निर्देश दिया कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे खनन के परिणाम अपूर्णीय और दूरगामी होते हैं। शीर्ष अदालत ने यह भी दोहराया कि अरावली की वैज्ञानिक और स्पष्ट परिभाषा तय करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। इस समिति में पर्यावरण, वानिकी, भू-विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों के स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे। अदालत ने सभी पक्षों जिसमें एमिकस क्यूरी भी शामिल हैं उससे समिति के संभावित सदस्यों के नाम और सुझाव चार हफ्ते में पेश करने को कहा है।

यह मुद्दा संवेदनशील

कोर्ट ने अपने उस पुराने फैसले पर लगी रोक को भी बढ़ा दिया है, जिसमें 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की सिफारिश थी। पर्यावरण मंत्रालय की समिति की इस सिफारिश को अदालत ने पहले ही पुनर्विचार योग्य बताते हुए स्थगित कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर लगी रोक बढ़ाई

राजस्थान में हो रहे अवैध खनन का मामला भी उठाया

सुप्रीम कोर्ट, अरावली की पहाड़ियां

गहराई से होगी जांच

सुनवाई के दौरान एक वकील ने राजस्थान के कई क्षेत्रों में लगातार हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया। इस पर न्यायालय ने राजस्थान सरकार के वकील को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि अरावली जैसा पर्यावरणीय क्षेत्र किसी भी प्रकार का भार नहीं उठा सकता है। अदालत ने साथ ही कहा कि अवैध खनन भविष्य की पीढ़ियों के पर्यावरण अधिकारों को सीधे प्रभावित करता है, इसलिए न्यायालय इस पूरे मामले में सभी पहलुओं की गहराई से जांच करेगा।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले साल दिसंबर में पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा।

सीजेआई ने जताई चिंता

सुखना झील को कितना सुखाओगे? गलती न दोहराएं

चंडीगढ़ की सुखना झील

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील के सूखने पर चिंता जताई है। हरियाणा सरकार को पिछली गलतियों को न दोहराने की चेतावनी देते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अधिकारियों और बिल्डर माफिया की मिलीभगत के कारण सुखना झील पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी अरावली पहाड़ियों के मामले पर सुनवाई करते हुए की।

झील का गिर रहा जलस्तर

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से बिल्डर माफिया काम कर रहा है। आप सुखना झील को कितना सुखाओगे? आपने झील को तो पूरी तरह से खराब कर दिया है। दरअसल, बारिश के पानी पर निर्भर सुखना झील कभी चंडीगढ़ का प्रमुख पर्यटन केंद्र हुआ करती थी, लेकिन बीते वर्षों में लगातार गिरते जलस्तर ने इसकी सुंदरता और अस्तित्व दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

मदुरै पीठ की सख्त टिप्पणी

उदयनिधि का 'सनातन मिटाओ' बयान 'नरसंहार' की मांग जैसा

अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर रद्द

उदयनिधि स्टालिन

एजेंसी ▶▶ चेन्नई

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने सोमवार को तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन के उस बयान पर सख्त टिप्पणी की, जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक संबोधन में सनातन धर्म का सफाया करने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ कहा कि उदयनिधि स्टालिन का बयान नरसंहार की मांग जैसा है। हाईकोर्ट की पीठ ने भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। मदुरै पीठ की जस्टिस एस श्रीमथी ने कहा कि अगर सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का समूह यहां नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए सही शब्द 'नरसंहार' है।

ओझिप्पु का मतलब 'सफाया'

जस्टिस श्रीमति ने स्टालिन के भाषण में ओझिप्पु शब्द पर विशेष जोर दिया और कहा कि पूरा मामला एक शब्द पर है, जो बेहद अहम है। पीठ ने कहा कि सरकार भी ओझिप्पु शब्द का मतलब सफाया मानती है। इसके बाद अदालत ने इस शब्द के पर्यायवाची का भी जिक्र किया, जिनका मतलब भी सफाया, मिटाना, तबाह करना आदि बताया गया। जज ने कहा कि अमित मालवीय ने पोस्ट में जो सवाल किया था, उसमें हिंसा या आंदोलन की मांग नहीं की गई थी। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि अदालत ने डीएमके सरकार द्वारा दर्ज की गई राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदले की भावना वाली एफआईआर को खारिज कर दिया।

एस. श्रीमथी

लिव-इन में महिला तभी सुरक्षित, जब पत्नी

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षा तभी मिलेगी, जब उन्हें पत्नी का दर्जा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे रिश्तों में महिलाओं को वैवाहिक सुरक्षा नहीं मिल पाती इसलिए कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को संरक्षण दें। जस्टिस एस श्रीमथी ने यह टिप्पणी एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की। शख्स पर आरोप है कि वह महिला के साथ पहले लिव-इन में रहा। फिर शादी का झूठा वादा कर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि पुरुष पहले मॉडर्न बनकर लिव-इन का रिश्ता बनाते हैं। बाद में रिलेशनशिप खराब होने पर महिला के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि कानून में लिव-इन को लेकर कोई नियम नहीं हैं।

कल्याण-डोंबिवली नगर निगम चुनाव

राज ठाकरे के 5 नगरसेवकों ने शिंदे गुट को दिया 'समर्थन'

एजेंसी ▶▶ मुंबई

कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) में निकाय चुनाव के बाद राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन देने का फैसला किया है। एमएनएस के पूर्व विधायक प्रमोद राजू पाटिल ने पार्टी के पांचों नगरसेवकों की ओर से शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे पहले शिवसेना के सभी 53 नगरसेवक नवी मुंबई में स्थित कोंकण संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंच, जहां उन्होंने अपने गुट का औपचारिक पंजीकरण कराया। इस दौरान एमएनएस के 5 नगरसेवकों ने भी वहीं अपनी प्रक्रिया पूरी कर शिवसेना को समर्थन देने की घोषणा की।

एकनाथ शिंदे, राज ठाकरे फाइल फोटो

स्कूल बैंड प्रतियोगिता जारी

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में प्रस्तुति देने वाली स्कूल बैंड टीमों के चयन की प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता का जोनल चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिसमें देश के अलग-अलग स्कूलों की 16 टीमों का चयन किया गया है। ये टीमें 24 जनवरी को दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाल भवन में आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में अपनी प्रस्तुति देंगी। हर जोन से चार टीमों को चुना गया है। कुल चार जोन- पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से चयनित 16 टीमें ब्रास बैंड बॉयज, ब्रास बैंड गर्ल्स, पाइप बैंड बॉयज और पाइप बैंड गर्ल्स श्रेणियों में ग्रैंड फिनाले में मुकाबला करेंगी।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **मोहम्मद शफीक पुत्रः मोहम्मद तफीक पताः डी – 31/32, जे जे कॉलोनी, शकुरपुर, दिल्ली** ने case **FIR No. 259/2014 U/s 377/323/506/34 IPC & FIR No. 260/2014 U/s 377/323/34 IPC, थानाः हरि नगर, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **मोहम्मद शफीक** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **मोहम्मद शफीक** फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है।)

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि case **FIR No. 259/2014 U/s 377/323/506/34 IPC & FIR No. 260/2014 U/s 377/323/34 IPC, थानाः हरि नगर, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **मोहम्मद शफीक** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद/मुकद्मा का उत्तर देने के लिए **दिनांक 23.02.2026** को या उससे पूर्व हाज़िर हो।

आदेशानुसार
सुश्री मोक्षा बैंस
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी–11
पश्चिम जिला, कोर्ट नं. 31
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/934/WD/2026 (Court Matter)

गणतंत्र दिवस परेड में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना दे रही ये

महिला सशक्तिकरण, समान अवसर और स्वदेशी जहाज निर्माण

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

गणतंत्र दिवस की परेड 2026 की रिहर्सल जारी हैं। भारतीय सैन्य बल कर्तव्य पथ पर दमदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड महिलाओं को समर्पित है। नौसेना की झांकी में भी महिला सशक्तिकरण और स्वदेशी ताकत की झलक दिखेगी। नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के. ने बताया कि गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में नेवल टेब्लयू महिला सशक्तिकरण, समान अवसर और स्वदेशी जहाज निर्माण को दिखाएगा। वे उस समय चर्चा में आईं थी, जब पीएम मोदी ने मन की बात में नविका सागर परिक्रमा जैसी समुद्री महायात्रा का जिक्र किया था। दिलना ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये उपलब्धि व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि देश की प्रेरणा बन गई

नविका सागर परिक्रमा में लिखा इतिहास

लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के

नेवल टेब्लयू का संदेश

महिला सशक्तिकरण– नौसेना में महिलाएं अब भूमिका नहीं, नेतृत्व निभा रही हैं। समान अवसर– पुरुष और महिला, दोनों के लिए एक जैसे मानक। स्वदेशीकरण– भारत में बने युद्धपोत, आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति।

विश्व भ्रमण मिशन का हिस्सा बनीं

नविका सागर परिक्रमा भारतीय नौसेना का ऐतिहासिक समुद्री अभियान रहा। उन्होंने इस ऐतिहासिक समुद्री अभियान में हिस्सा लिया, जो भारतीय नौसेना का दूसरा 'ऑल-वीमेन' विश्व भ्रमण मिशन था। जिसका उद्देश्य था, भारतीय महिला अधिकारियों की सहनशक्ति और समुद्री कौशल को परखना। दुनिया को दिखाना कि भारतीय नौसेना लैंगिक समानता को जमीन से समंदर तक निभाती है। दिलना के ने इस अभियान के जरिए लंबी समुद्री यात्रा, चुनौतीपूर्ण मौसम और तकनीकी जटिलताओं का सामना किया। उनके अनुभवों ने यह संदेश दिया कि डिफेंस करियर केवल ताकत नहीं, धैर्य और टीमवर्क भी मांगता है।

कॉमर्स से स्नातक के बाद नौसेना में प्रवेश

दिलना के का जन्म केरल के कोझिकोड में पैराम्बिल कड़ाव में हुआ था। उनके पिता लेफ्टिनेंट डेबडासन भारतीय सेना में सेवा करते थे, जिनका देहांत बाद में हो गया। उनकी मां का नाम रीजा है, जिन्होंने हमेशा दिलना के करियर को हमेशा समर्थन दिया। उन्होंने कॉमर्स से स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में भारतीय नौसेना में प्रवेश लिया। जून 2014 में लॉजिस्टिक्स ब्रांच में कमीशन प्राप्त किया।

अभियुक्त की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 Cr.P.C. देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **नितिन जैन**, पुत्रः सुरेश चंद जैन, पताः एच–40, चौथा तल, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली–26 तथा **ज्योति जैन, पत्नीः** नितिन जैन, **पताः** एच–40, चौथा तल, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली–26; दूसरा पताः द्वारा चौबारा–चाट, चाय एंड चर्चा, पी ब्लॉक, कनॉट सर्किल, जैन चावल वाले के पास, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–01; तीसरा पताः द्वारा चौबारा–चाट, चाय एंड चर्चा, अपर ग्राउंड फ्लोर, कैपिटल साइबरस्केप, उल्लावास, सेक्टर–59, गुरुग्राम; चौथा पताः चौबारा–चाट, चाय एंड चर्चा, 17 ए/35, प्रथम तल, पश्चिमी पंजाबी बाग, नई दिल्ली–26 ने **CC No. 3666/2021, U/s 138 NI ACT, थानाः पंजाबी बाग, नई दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उन्होंने किया है), और उन पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारण्ट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **नितिन जैन** तथा **ज्योति जैन** मिल नहीं रहे हैं और मुझे समाधानप्रद रूप में दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **नितिन जैन** तथा **ज्योति जैन** फरार हो गये हैं (या उक्त वारण्ट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहे हैं)।

इसलिए इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि **CC No. 3666/2021, U/s 138 NI ACT, थानाः पंजाबी बाग, नई दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **नितिन जैन** तथा **ज्योति जैन** से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **21.02.2026** को या इससे पहले हाजिर हों।

आदेशानुसार
सुश्री कोमल गर्ग
न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी–03
कमरा नं. 292, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/901/WD/2026 (Court Matter)

Please Support me by joining My Private Channel

✅ I Give My Earliest Newspapers updates from 5 AM in Private channel with All Editions

♦ Indian Newspaper

1) Times of India
2) The Hindu
3) Business line
4) The Indian Express
5) Economic Times
6) Financial Express
7) Live Mint
8) Hindustan Times
9) Business Standard

♦ International Newspapers channel

[Europian, American, Gulf & Asia]

♦ Magazine Channel

National & International

[Genaral & Exam related]

Click Here

♦ English Editorials

[National + International Editorials]